HP/129/SML/2019-2021

Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500

16-31 जनवरी, 2020

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 2, अंक 37/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com ज़िम्मेवार नागरिक होना ही हमारा धर्म होना चाहिए.... डॉ॰ एल सी शर्मा

THE ONLY INITIATIVE THAT COVERS ALL 17 SDG's GOALS

यूनाईटेड नेशन के आमंत्रण पर आईआईआरडी करेगा न्यूयार्क में शिरकत

मिशन रीव और सामाजिक विकास पर संस्था देगी प्रस्तुतिकरण

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

आईआईआरडी ने सामाजिक सेवाओं का विस्तार अब वैश्विक स्तर पर कर लिया है । विगत वर्ष में जिनेवा से लेकर दक्षिण अफ्रीका के देशों में संस्था के प्रयासों को खूब सराहना मिली है । वर्ष 2020 में संस्था अमेरिका के यूनाईटेड नेशन में आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों और विकास हेतु भावी प्रयासों पर प्रस्तुतिकरण करेगी । इसी माह के 20 जनवरी से 30 जनवरी तक ईकॉनोमिक एंड सोशल अफेयरस्-2020 बैठक एवं कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक डॉ॰ एल सी शर्मा एवं निदेशक ब्रिगेडियर बी के खन्ना भाग लेने गए हैं । डॉ॰ एल सी शर्मा वहां अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे जिसमें सामाजिक क्षेत्र में संस्था के योगदान के साथ-साथ भावी संभावनाओं पर संस्था का तकनीकि एवं सामाजिक सहयोग क्या होगा, इस पर अपनी बात रखेंगे ।

गौरतलब है कि आईआईआरडी ने सीएसआर और नवीनतम प्रयासों से देश भर में एक अलग पहचान बनाई है । जिनेवा में संस्था के सराहनीय प्रयास मिशन रीव पर चर्चा की जा चुकी है और इसके अलावा अन्य यूरोपीय देशों में भी इस पर चर्चा के प्रस्ताव आना यह बताता है कि इस प्रयास में जनसेवा के मूलमंत्र को बहुत बारीकी से उकेरा गया है तथा आमजन को इससे सरलता और सुविधाजनक तरीके से सामने लाने का सफल प्रयास किया गया है । 12 प्रभागों में विभाजित सर्वथा ऑनलाईन एंव पारदर्शी प्रारुप के साथ मिशन रीव ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में जनता को सेवाऐं प्रदान की तथा प्रक्रिया अभी भी जारी है । इसके अलावा आसाम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी मिशन रीव के लिए सेवा के अनेक चरणों में प्रगतिशील किया गया है । देश से विदेश तक की यह सफलता मिशन रीव के दिल से सेवा-दिल से भुगतान के मूल मंत्र को सार्थक करती है ।

अमेरिका में यूनाईटेड नेशन में आईआईआरडी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विकास के क्षेत्र में सेवाओं के लिए ज़मीन तलाशेगा तथा अपनी सेवाओ का विस्तार करेगा ।

सरकार ने फोरलेन के कार्य को नहीं लिया गंभीरता से

फोरलेन पर केन्द्रिय मंत्री की लताड़, तय समयसीमा में नहीं हुए काम

लाखों पेड़ काट दिये, कार्य फिर भी पड़ा है बंद

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

बिना औपचारिकता किए शिमला बाईपास और सोलन परमाणु फोरलेन का जो कार्य शुरु किया गया था वो एक लंबे समय से अब जस का तस खड़ा है और लोग काटे और छीले गए नग्न पहाड़ों को देखकर अब बना तब बना की स्थिति में मूक हैं । सरकार ने अपनी ओर से तो कोई ठोस क़दम नहीं उठाया लेकिन केन्द्रिय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लताड़ लगाते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस विषय पर बात की । उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब औपचारिकाऐं पूरी नहीं थी तो कार्य शुरु कैसे कर दिया गया ? और जिन अधिकारियों की इसमें ढील है उन पर कार्यवाही करने की भी बात कही ।

द रीव टाइम्स ने दिसंबर 2018 में ही एक लेख में यह मुद्दा उठाकर सरकार को चेताया भी था कि हज़ारों पेड़ इन फोरलेन में बलि चढ़ चुके हैं तथा कितने ही अभी बाकि है जबकि आधा-अधूरा काम जो हो भी रहा था उस पर भी लोगों की आपत्ति के कारण काम बंद होने के कगार पर था । सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी को आधार बनाकर द रीव टाइम्स ने बताया था कि किस प्रकार परमाणु से ढली शिमला तक अंधाधुंध खनन करके पहाड़ों को चीरा गया था और बेतहाशा पेड़ों की बलि दे दी गई थी । अब 2020 में जब केन्द्रिय सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट यहां खटाई में पड़ा है तो यह जिम्मेवारी तो तय होनी ही चाहिए कि सरकार के स्तर पर किसकी लापरवाही से कार्य ठप्प पड़ा है और तय समयसीमा में यह पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है ? द रीव टाइम्स ने सूचना के अधिकार में ये आंकड़े सरकार के पास रखे थे ।

सूचना में एनएचएआई ने बताया कि एनएचडीपी-111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ईपीसी मोड़ के आधार पर परमाणु से सोलन अनुभाग एनएच 22 में 67.00 किलोमीटर से 106.139 किलामीटर का निर्माण हो रहा है ।

एनएचडीपी-111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ईपीसी मोड़ के आधार पर ही सोलन से कैथलीघाट अनुभाग एनएच 22 में 106.139 किलोमीटर से 129.05 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है ।

एनएचडीपी-111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) एन्यूटी (वार्षिकी) हाईब्रिड मोड़ के आधार पर ही कैथलीघाट से ढली अनुभाग एनएच 22 में 129.05 किलोमीटर से 156.507 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है ।

द रीव टाइम्स www.therievtimes.com अभिव्यक्ति 01-15 दिसम्बर, 2018 09

हज़ारों पेड़ चढ़ चुके हैं फोरलेन की बलि

पेड़ लगाने के नाम पर अभी ज़मीन तक का चयन नहीं

पहाड़ों को चीर कर बन रहा तरक्की का फोरलेन

रीव रिपोर्ट, शिमला (हेम राज चौहान)

तरक्की की राह सड़कों से होकर गुजरती है .....यह बात आज के संदर्भ में विल्कुल सटीक एवं सत्य है। लेकिन पहाड़ों में सड़क की आपातकुल आवश्यकता के बाद फोरलेन के लिए सारी भौगोलिक स्थिति को ही आकलन के दायरे में लाया जाना जरुरी है। ये सड़कें हालांकि हमारे समाज की वर्तमान में जीवन रेखा है फिर भी सड़कों का बढ़ा स्वरुप यानि फोरलेन कहीं न कहीं भविष्य के लिए खतरे से कम नहीं है । हमारी पड़ताल इसी संदर्भ में की गई जिसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पर्यावरणविदों एवं प्रकृति के शुभचिंतक अक्सर अपनी चिंता कंक्रीट के बढ़ते जंगलों और कटते पेड़ों के अलावा अंधाधुंध खनन पर जताते रहे हैं। और यह चर्चा भी है। पहाड़ बिना पेड़ों और जंगलों के पहाड़ नहीं हो सकते। यहां का जीवन भी जल-जंगल-जलवायु पर ही निर्भर है। ऐसे में बढ़े पहाड़ों पर फोरलेन के शिमला महापीपी पंजी ने इन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया है। सबसे अधिक नुकसान तो वहाँ से हमारे जीवन को ऑक्सीजन और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहे मूक पेड़ झेल रहे हैं जिन्हें एक झटके में गिरा कर जेसीबी रौंद रही है। ऐसा नहीं कि बिना नुकसान के तरक्की का इतिहास लिखा जा सकता हो.....तरक्की के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है किंतु उसका विकल्प जब तक सामने न हो तब तक इस प्रकार का नुकसान प्रकृति को अस्तित्व कर देगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सूचना के अधिकार में प्राप्त सूचना की माने तो प्रदेश सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन में जिन शर्तों पर सहमति बनी है उसमें सबसे पहले यदि कोई कार्य हुआ और ही रहा है तो वो है पेड़ों का अंधाधुंध काटना। तीनों ज़ोन में ही यानि परमाणु से सोलन, सोलन से कैथलीघाट और कैथलीघाट से ढली के बीच पेड़ों का व्यापक स्तर पर कटान हो चुका है तथा अभी कितने ही इस फोरलेन की भेंट चढ़ने बाकि है ।

सूचना में एनएचएआई ने बताया कि

- एनएचडीपी-111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ईपीसी मोड़ के आधार पर परमाणु से सोलन अनुभाग एनएच 22 में 67.00 किलोमीटर से 106.139 किलामीटर का निर्माण हो रहा है ।
- एनएचडीपी-111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ईपीसी मोड़ के आधार पर ही सोलन से कैथलीघाट अनुभाग एनएच 22 में 106.139 किलोमीटर से 129.05 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है ।
- एनएचडीपी-111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) एन्यूटी (वार्षिकी) हाईब्रिड मोड़ के आधार पर ही कैथलीघाट से ढली अनुभाग एनएच 22 में 129.05 किलोमीटर से 156.507 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है ।

परियोजना निदेशक सनवर मल स्वामी ने बताया कि समझौता ज्ञापन के तहत इन तीन अनुभागों में प्रदेश सरकार के साथ औपचैरिटी द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। पेड़ों को काटने का कार्य प्रगति पर है तथा नए पेड़ लगाने का कार्य प्रदेश वन विभाग के डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) के अधीन है क्योंकि सरकार को पेड़ों का उचित मुआवजा दिया जा चुका है तथा हरना ही नहीं... पेड़ों के लगाने से उसके दस वर्षों तक के संरक्षण तक के लिए पैसा जमा किया गया है । प्राधिकरण फोरलेन के निर्माण से संबन्धित ही कार्य देख रहा है तथा पेड़ों के लगाने के लिए हिमाचल सरकार के पास नियमानुसार धनराशि जमा करवाई जा चुकी है ।

फोरलेन की भेंट अब तक हुए इतने पेड़ शहीद

4 सितंबर 2018 तक फोरलेन में परमाणु से ढली शिमला तक तीनों अनुभागों में कुल 40 हज़ार से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं । यह आंकड़ा अगस्त के आख़िर तक का है जिसमें अभी के आंकड़े शामिल नहीं है । यानि यह आंकड़ा अब कहीं अधिक हो चुका है ।

- परमाणु से सोलन में वन विभाग की ज़मीन पर 12 हज़ार 508 पेड़ काटे गए हैं जबकि डिफेंस भूमि पर 1 हज़ार 882 तथा निजी भूमि पर 7 हज़ार 807 पेड़ काटे गए हैं । जिनका कुल योग 22 हज़ार 197 बनता है ।
- सोलन से कैथलीघाट के बीच वन विभाग की ज़मीन पर 1 हज़ार 150 पेड़ काटे गए हैं ।
- कैथली घाट से ढली के बीच वन विभाग की ज़मीन पर 9 हज़ार 576 पेड़ काटे गए और निजी भूमि पर 7 हज़ार 173 पेड़ों को कटना पड़ा है । जिसका कुल योग 16 हज़ार 749 है । यानि सितंबर प्रथम सप्ताह तक 40 हज़ार से अधिक पेड़ ज़मींजोद हो चुके हैं ।

यह आंकड़ा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्राप्त हुआ जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी इससे भी अधिक के पेड़ काटे जाने की बात कर रहे हैं ।

यहां प्रश्न यह है कि जब समझौता ज्ञापन में पेड़ काटे जाने के एवज में पेड़ लगाने की शर्तें हैं और उसके लिए प्राधिकरण ने बाकायदा सरकार को पर्याप्त राशि जमा भी करवा दी है तो कितने पेड़ लगाए गए हैं तथा कितने अभी नहीं लगे ...इसका स्पष्टीकरण होना भी आवश्यक है । इन तीनों अनुभागों के लिए पेड़ लगाने आदि के लिए संबंधित डिवीजनल फोरेस्ट ऑफिसरों यानि डीएफओ की जिम्मेवारी को सुनिश्चित की गई है।

क्या कहते हैं शिमला डीएफओ सुशील राणा

इस बाबत जब डीएफओ शिमला सुशील राणा से बात की तो उन्होंने बताया कि एनएचएआई द्वारा पैसे जमा करवा दिए गए हैं तथा पेड़ों को काटा भी जा रहा है। लेकिन अभी तक एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है । पेड़ को लगाने की दस्तावेज़ी औपचारिकाएं अधिक है तथा अभी लैंड बैंक भी नहीं बन पाया है। ज़मीन की तलाश जारी है तथा जल्द ही इस पर गंभीरता से कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि जहां फोरलेनिंग का कार्य हो चुका है और उसके मलबे आदि में भी पेड़ लगाने का कार्य है तो उन्होंने बताया कि अभी कोई भी पेड़ नहीं लगाया गया है। डीएफओ ने बताया कि अभी शिमला ज़ोन में ही लगभग 24 हज़ार पेड़ और कटने हैं। 50 हज़ार 749 पेड़ काटे जा चुके हैं तथा 30 ऐसे पेड़ हैं जो किसी न किसी विवाद के कारण नहीं काटे जा सके हैं। साथ ही 494 ऐसे पेड़ हैं जिन्हें टनल आदि बनने के कारण कटने से बचाया गया है। शिमला शामीन एवं शहरी अलग-अलग क्षेत्रों में लैंड बैंक की समस्या बनी हुई है।

लेकिन यहां प्रश्न यह है कि टनल बनने से उसके ऊपर बने मकान और पेड़ दोनों ही अनुपस्थित हो जाएंगे। भारीभरकम से मकानों को खतरा तो रहेगा ही साथ ही पेड़ों की जड़ें जब कट जाएंगी तो ऊपर खड़ा पेड़ स्वतः ही सूख जाएगा। यानि पेड़ काटने के बजाए सूखेगा और इससे यह संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। हालांकि सुशील राणा कहते हैं कि टनल के ऊपर पेड़ सुरक्षित नहीं रखे जा सकते क्योंकि उनकी जड़ें कट जाएंगी। इसलिए उन सूखे पेड़ों को वाइल्ड लाईफ सेंचरी आदि में उपयोग लाया जा सकेगा।

क्या कर रही है सरकार जमा पैसों का

सरकार के पास करोड़ों रुपए पेड़ लगाने का जमा है जिसकी मांग सरकार के खाते में आ रही है और पेड़ अभी एक भी नहीं लगाया गया है। यदि लैंड बैंक नहीं है अथवा कोई अन्य दस्तावेज़ी गतिविधियां भी पूरी नहीं की गई हैं तो पेड़ काटा जाना भी कहां तक वाजिब कहा जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में बंजर वन भूमि की कमी नहीं है तथा पौधारोपण कार्यक्रम करवाने संस्थाओं की भी भरमार है। सरकार को सबसे पहले बंजर वन भूमि को ही लैंड बैंक बनाकर उस पर पौधारोपण का संतुलन बनाने की आत्मिक पहल करने की प्रबल आवश्यकता है। क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने तथा गुणों के विकास में बहुत वर्ष का सफर तय करना होता है। ऐसे में इतना अंधाधुंध कटान हिमाचल प्रदेश की भूमि को नग्न कर देगा। इसके दूरगामी दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

पर्यावरणविद की पीड़ा

वनोपज, संवर्धित एवं पर्यावरणविद प्रोफ़ेसर आर के सूरा ने इसके अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए साझा किया कि पहाड़ टूट रहे हैं ...नदियां सूखती जा रही हैं....प्राकृतिक स्रोत सूखे पड़े हैं....पहाड़ों के नीचे सुरंगे बना कर उपर बने मकान कभी भी ज़मींजोद हो सकते हैं। यह सब अब देखा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि एक उमाना था कि पहाड़ हरे-भरे और पेड़ों से लदे होते थे। इसके कारण कभी पानी और नमी की भी कमी नहीं रही। आज वही पहाड़ नंगे और जर्जर हैं, उन्हें कुरेदा जा रहा है, मशीनी पंजी से खरोंचा जा रहा है। पहाड़ नहीं बचे तो मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं हो सकता। उनके अनुसार जल-जंगल-ज़मीन को बचाना आज की पुकारी है।

सरकार से लेकर आम आदमी तक की जिम्मेवारी

विकास हमेशा नुकसान की शर्त पर ही चलता है, लेकिन उसके विकल्पों पर समय रहते विचार न किया गया तो भविष्य के लिए जो मुश्किलें होंगी उनका निदान अगली पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल होगा। पेड़ों का संरक्षण और उसके कटने के बाद प्रकृतिक जख्मों को बचाने के लिए हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। सरकार को योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है और आम आदमी को भी विकास के लाभ लेने से पहले अपने कर्तव्यों को नहीं भुलना चाहिए। क्योंकि यहां पहाड़ नहीं दरक रहे...दरक रहा है भविष्य के गर्भ में प्रलय का भूचाल.....

हेम राज चौहान
सहायक संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

इतना ही नहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त सूचना में सरकार के पास पेड़ काटे जाने के बाद नये पेड़ लगाने के लिए करोड़ों रुपये वन विभाग में जमा किए गए हैं। और जब वन विभाग में अधिकारियों से द रीव टाइम्स ने बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमें पैसा मिल चुका है लेकिन अभी लैंड बैंक की पहचान नहीं की गई है और एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है । मतलब साफ है कि सरकार को संबन्धित विभागों की जिम्मेवारी तय करनी होगी ताकि इस प्रकार पर्यावरण को हो रहे नुकसान और अरबों के इस प्रोजेक्ट को बर्बाद होने से बचाया जा सके । अब केन्द्रिय मंत्री की लताड़ से सरकार को त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है । परमाणु से शिमला तक जहां-तहां पहाड़ों के सीने चीर कर उसे नंगा करके छोड़ दिया गया है । अब काम ठप्प पड़ा है । लोगों को ज़मीन व मकानों का भुगतान हो जाने के बाद भी पेचिदगियां ख़त्म नहीं हुई और अधिकारी सोये हुए हैं । केथलीघाट से शिमला तक जो तीन सुरंगे बननी थी उसमें भी बहुत ढील से कार्य किया गया और अभी तक ये काम हुए ही नहीं है । अब केन्द्र की लताड़ के बाद हिमाचल सरकार को ये सोचना होगा कि देश में परिवहन क्रांति और हिमाचल के प्रति केन्द्र सरकार की दरियादिली के कारण यदि सरकार छोटी-बड़ी औपचारिकताओं को भी पूरी नहीं करवा पा रही है तो यह शर्मनाक है और इससे प्रदेश की विकास के प्रति गंभीरता का भी पता चलता है ।

इंपोर्टेड रुट स्टॉक से आर्गेनिक नर्सरी और बागीचा होगा तैयार

मिशन रीव बागवानों का देगा सुविधा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश के बागवानों को जल्द ही उच्च गुणवत्ता का रूट स्टॉक उपरी शिमला में ही मिलेगा। इसके साथ ही शिमला के रामपुर में सेब का ऐसा बागीचा तैयार किया जाएगा जिसमें पूरी तरह आर्गेनिक सेब तैयार होगा। इसके लिए आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत से रामपुर के शोली में विशेष प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है।

यहां तैयार की जा रही नर्सरी पूरी तरह से आर्गेनिक होगा। इसके तैयार करने में किसी भी तरह की रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दरअसल आईआईआरडी की ओर से

मिशन रीव के तहत प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। किसान और बागवान भी इन सुविधाओं का खूब लाभ उठा रहे हैं। मिशन रीव के तहत बागवानों को सेब उत्पादन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए हाल ही में उपरी शिमला में विशेषज्ञों को साथ लेकर विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में जहां बागवानों ने सेब व अन्य फलों की बेहतर पैदावार के बारे में जानकारी प्राप्त की वहीं

मौसम और अन्य कारणों से सेब उत्पादन को बढ़ाने में पेश आ रही परेशानियों को भी साझा किया। बागवानों ने बताया कि आज के दौर में बाजार में बहुत से वेंडर हैं जो बेहतर रूट स्टॉक का दावा करते हैं लेकिन जब फसल की बात आती है तो बागवानों की लागत भी नहीं निकल पाती। बागवानों की इसी समस्या को दूर करने करने के लिए मिशन रीव के तहत रामपुर की शोली पंचायत में प्रदेश के बागवानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रूट स्टॉक मंगवाकर नर्सरी तैयार की जाएगी।

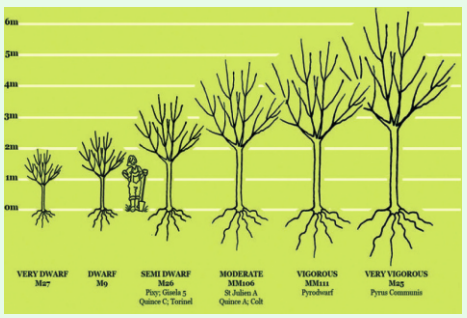

हिमाचल प्रदेश के 2019 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में फलों के तहत आने वाले कुल क्षेत्र में से 49 प्रतिशत क्षेत्र सेब के तहत आता है जबकि कुल फल उत्पादन में सेब का योगादन 79 प्रतिशत है। अगर 1950–51 से अब तक सेब उत्पादन के तहत आने वाले क्षेत्र को लेकर दर्ज आंकड़ों की बात करें तो यह साफ हो जाता है कि हिमाचल की आर्थिकी को बदलने में सेब के क्या मायने हैं। वर्ष 1950–51 में 3 हजार 25 हैक्टेयर के मुकाबले आज 1 लाख 12 हजार 634 हैक्टेयर पर सेब उगाए जाते हैं। कहा जा सकता है कि सेब हिमाचल की आर्थिकी की मजबूत रीढ़ है। ऐसे में

जरूरी है कि बागवानों को सेब उत्पादन के आधुनिक और कम जोखिम वाले तरीकों से अवगत करवाया जाए और उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाए। मिशन रीव जिला शिमला के तहत रामपुर की शोली पंचायत से इसकी शुरूआत करने जा रहा है। यहां पर जो बागीचा तैयार किया जाएगा उसके परिणाम 2023 तक सामने होंगे।

उल्लेखनीय है कि आईआईआरडी मिशन रीव के तहत प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में कृषि और बागवानी के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बात जैविक खेती की हो या

किसानों – बागवानों को मृदा परीक्षण की सुविधा घर – द्वार पर देने की, सभी में मिशन रीव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मिशन रीव का संचालन कर रहे आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एलसी शर्मा का कहना है कि मिशन रीव की शुरूआत ही गांव के किसानों और बागवानों को सुविधा मुहैया कराने के लिए की गई है। शोली में तैयार की जा रही विशेष किस्म की नर्सरी बागवानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी।

केंद्रीय विवि में भरेंगे गैर शिक्षकों के पद, 31 तक करें आवेदन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार के विभागों और संस्थानों में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए हिमाचल की सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को फीस न देने की कोई छूट नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने गैर शिक्षक वर्ग के 29 पद भरने के लिए आवेदन मांगे हैं।

इन पदों के पात्र अभ्यर्थी 15 से 31 जनवरी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैंसामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 400 रुपये फीस भरनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अभ्यर्थियों को बिना फीस से आवेदन करना होगा।केंद्रीय विवि के कुलसचिव डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि गैरशिक्षक वर्ग के 29 पदों के लिए 15 जनवरी से आवेदन मांगे हैं। पात्र अभ्यर्थी 31 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

केंद्रीय विवि गैर शिक्षक वर्ग के 29 पदों में निजी सचिव के पांच पद, चालक के पांच, सुरक्षा अधिकारी का एक, निजी सहायक के तीन, कनिष्ठ तकनीकी सहायक का एक, कनिष्ठ अनुवादक का एक, सुरक्षा निरीक्षक का एक पद।

सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का एक, फार्मासिस्ट का एक, अप्पर डिविजन क्लर्क के दो, लोअर डिविजन क्लर्क का एक, कुक का एक, लेबोरेटरी अटैंडेंट का एक, लाइब्रेरी अटेंडेंट का एक, मेडिकल अटैंडेंट का एक, किचन अटैंडेंट के दो और हॉस्टल अटैंडेंट का एक पद भरेगा।

एनडीए परीक्षा 19 अप्रैल को, ऑनलाइन आवेदन शुरु

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संघ लोक सेवा आयोग ने सेना में एनडीए के फार्म ऑनलाइन भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एनडीए में 418 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 28 जनवरी निर्धारित की गई है। 28 जनवरी शाम 6 बजे तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 19 अप्रैल को लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। इसके लिए 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में लिखित परीक्षा के लिए शिमला को केंद्र बनाया गया है। जून माह में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 100 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए फीस नहीं ली जाएगी। फीस डेबिट और नेटबैंकिंग के माध्यम से देनी होगी। लिखित और एसएसबी परीक्षा 900 अंक की होगी। लिखित परीक्षा की मेरिट में आने वाले

अभ्यर्थियों को एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी एनडीए के फार्म भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने लोक मित्र केंद्रों पर फार्म भी ऑनलाइन फार्म भरने की सुविधा दी है। कहमन सर्विस सेंटर के समन्वयक लक्की पुरी ने बताया कि कम शुल्क देकर अभ्यर्थी अपने नजदीक के लोकमित्र केंद्र में फार्म भर सकते हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई 1995 किलोग्राम खिचड़ी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सक्रांति के मौके पर जिला मण्डी के तत्तापानी में 1995 किलोग्राम दाल और चावल से बनाई गई खिचड़ी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक कि सबसे अधिक परोसी जाने वाली खिचड़ी के रूप में दर्ज की गई है। इस खिताब के तहत इससे पहले का रिकॉर्ड 918.8 किलोग्राम था। यह घोषणा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंकर संक्रान्ति के पावन अवसर पर जिला मण्डी के करसोग क्षेत्र के तत्तापानी में 'तत्तापानी महोत्सव' के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरान्त विशाल जन समूह को सम्बोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी मात्रा में खिचड़ी पकाने के अपने लक्ष्य में सफलता हासिल करने के लिए पर्यटन विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभाग ने लगभग 1000 किलो के बड़े अन्तर के साथ पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निदेशक पर्यटन और नागरिक उड्डयन युनूस ने कहा कि खिचड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन 7x4 फीट के दायरे का था और इस प्रयास का उद्देश्य तत्तापानी को विश्व पर्यटन के मानचित्र में लाना था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडजुडिकेटर ने घोषणा की कि पर्यटन और नागरिक उड्डयन

विभाग ने एक ही बर्तन में 1995 किलो खिचड़ी पकाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री ने जल क्रीड़ा गतिविधि प्रदर्शन का भी निरीक्षण किया और हिमाचल पथ परिवहन निगम की टूरिज्म सर्किट बस को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया।

इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल की बेटी जीना खिट्टा ने गोल्ड पर लगाया निशाना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल की बेटी जीना खिट्टा ने फिर से अपने निशाने का लोहा मनवाया है। असम में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मंगलवार को जीना खिट्टा ने गोल्ड पर निशाना साधा। जीना खेलो इंडिया की शूटिंग इंवेट में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। जीना ने इस बार हिमाचल को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। खेलो इंडिया-2020 की अंक तालिका में अभी हिमाचल 25 पायदान पर है। जीना ने हिमाचल को दूसरा मेडल दिलाया है। बीते दिनों हिमाचल की अंडर-19 कबड्डी टीम ने रजत पदक जीता था। जीना खिट्टा का निशानेबाजी का सफर आठवीं कक्षा से शुरू हुआ। रोहड़ू में अराधना शूटिंग क्लब के कोच वीरेंद्र बांश्टू से जीना के प्रशिक्षक हैं। आजकल भी जीना को विरेंद्र बांष्टू ही शूटिंग की कोचिंग दे रहे हैं। दसवीं कक्षा तक जीना रोहड़ू में अराधना पब्लिक स्कूल की छात्रा रहीं। आजकल डीएवी चंडीगढ़ के सेक्टर दस में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। जीना के पिता पृथ्वी राज खिटटा बागवान के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहते है, जबकि माता गृहिणी हैं। दिसंबर 2019 में भोपाल में जीना खिट्टा ने सीनियर नेशनल में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 2017 में पुणे में एसजीएफआई शूटिंग में कांस्य पदक और इसी साल नई दिल्ली में नॉर्थ जोन शूटिंग में रजत पदक जीता। पिछले साल केरल में नेशनल शूटिंग में एक रजत और कांस्य जीता।

हिमाचल की 24 और खनन साइटों की होगी नीलामी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल सरकार राज्य की 24 खनन साइटों की नीलामी मार्च के पहले हफ्ते में करेगी। अभी तक सरकार ने दो चरणों में प्रदेश की 185 साइटों की नीलामी कर दी है। सरकार तीसरे चरण में कुल 24 साइटों की नीलामी कर रही है। प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति में कोई भी साइट नीलाम नहीं हो पाई है। इन जिलों में खनन नीलामी से पहले पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी है। राज्य सरकार ने अभी कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और बिलासपुर में 40 साइटों की खनन नीलामी कर दी है। अब तीसरे चरण में हमीरपुर की 12 साइटों की नीलामी 3 मार्च को की जानी है। इसके अलावा चंबा की एक दर्जन साइटों की नीलामी 5 मार्च को होगी। इससे पहले सरकार ने जिला कांगड़ा में 14, सिरमौर 17, शिमला 4 और बिलासपुर की 5 साइटों की नीलामी की है। खनन साइटों की नीलामी के साथ पचीस फीसदी राशि तत्काल जमा करानी पड़ती है। जियोलॉजिस्ट पुनीत गुलेरिया कहते हैं कि प्रदेश सरकार की ओर से तीसरे चरण में खनन के लिए साइटों की

नीलामी की जानी है। अभी तक कुल 185 साइटों की नीलामी हो चुकी है। अब जिला चंबा और हमीरपुर की दो दर्जन साइटों की खनन नीलामी की जानी है। हमीरपुर में 3 मार्च और चंबा में 5 मार्च को नीलामी की जानी है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

दादा की बंदूक से खेल रहे थे भाई-बहन, गोली लगने से मासूम घायल, 1 घंटे पैदल चल पहुंचे अस्पताल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बंदूक से खेलना 4 वर्षीय बच्ची की जान के लिए आफत बन गया। गोली लगने से बच्ची घायल हो गई, जिसका शिमला के आईजीएमसी में इलाज चल रहा है। फिलहाल, बच्ची की हालत ठीक है और खतरे से बाहर है। मामला हिमाचल की राजधानी शिमला के रामपुर (Rampur) का यह मामला है।

खेल-खेल में हादसा

दरअसल, 5 साल के एक बच्चे के हाथ से चली गोली चार साल की बच्ची को लग गई और वह घायल हो गई। परिजन उसे निकटवर्ती अस्पताल ले गए हैं, जहां से उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। बच्ची के हाथ में गोली लगी है और फ्रैक्चर है।

पंचायत भवन और डाकघर समेत तीन मकान भीषण अग्निकांड में जलकर राख, दुकानें भी जलीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के शिमला जिले की तहसील कोटखाई के प्रेमनगर में भीषण अग्निकांड से व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार देररात भड़की आग से पांच दुकानें, दो स्टोर, पंचायतघर, उचित मूल्य की दुकान, डाकघर, क्लिनिक व दो क्वार्टर जलकर राख हो गए हैं।

अग्निकांड से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। अचानक भड़की आग से प्रेमनगर बाजार में अफरातफरी मच गई। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई और लोगों ने स्वयं भी आग बुझाने की कोशिश की। लकड़ी से बने मकान होने के चलते आग तेजी से फैली।

देखते ही देखते आग ने अन्य भवनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरि गोपाल, पंकज और बालक राम का का मकान, पूर्ण चंद का ढाबा, सही राम की दुकान आग की भेंट चढ़ गई।

बर्फबारी में लोगों की नाराज़गी का शिकार हुए प्रतिनिधि उपमहापौर और पार्षदों ने लोगों से मांगी माफी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पोर्टब्लेयर के दौरे से लौटे निगम के उप महापौर शेलेंद्र चौहान और सभी पार्षदों ने शहर पहुंचते ही बर्फबारी के कारण शहर में फैली अव्यवस्था के लिए लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि दौरा पूर्व निर्धारित था और इसके लिए सरकार से अनुमति मिलने के बाद वे गए थे। शिमला पहुंचने पर खेद जताते हुए कहा कि इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालने का प्रयास किया जाएगा। दौरे से लौटे पार्षद भी कुदरत के कहर से फैली अव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम के पार्षदों सहित अधिकारी कर्मचारी फील्ड में तैनात रहे और अब भी स्थिति को

संभालने में जुटे हैं। निगम के 28 पार्षद पोर्टब्लेयर के दौरे पर गए थे। वहां पर पार्षदों ने स्वच्छता का पाठ सीखा और अब उप महापौर पोर्टब्लेयर की स्वच्छता प्रणाली को शिमला में लागू करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि लोगों ने सोशल मीडिया पर खुलकर नाराजगी जताई थी।

सीबीआई की शिमला शाखा करेगी पटवारी भर्ती मामले की जांच

हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पटवारी भर्ती में कथित गड़बड़झाले की जांच सीबीआइ की शिमला शाखा करेगी। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में जांच एजेंसी ने अपने दिल्ली स्थित निदेशालय से प्रारंभिक जांच की अनुमति मांगी है। जैसे ही अनुमति मिलेगी, जांच शुरू होगी। इसके बाद विभाग से रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाएगा। प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच सीबीआई को सौंपी है। आठ अप्रैल तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।

एड्स जागरुकता कार्यक्रम शिरकत करते स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य निदेशक

हिमाचल में 24 जगहों पर हिमखंड गिरने की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जनवरी माह के पहले और दूसरे सप्ताह में हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बीच अब इन इलाकों में हिमखंड गिरने का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सैलानियों के साथ आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वे इन क्षेत्रों के आसपास न जाएं। आपदा प्रबंधक ने भी हिमखंड गिरने के खतरे को लेकर सतर्क रहने को कहा है।

प्रदेश में सबसे अधिक हिमखंड गिरने का खतरा लाहौल के उदयपुर और चंबा के किलाड़ क्षेत्र में है। जहां नौ जगहों पर हिमस्खलन हो सकता है। प्रदेश के 24 बर्फीले इलाके चयनित किए गए हैं, जहां हिमखंड गिर सकते हैं। इनमें जलोड़ी दर्रा से लेकर मनाली, लेह, किन्नौर और शिमला के क्षेत्र भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने सैलानियों और आम लोगों को जिला कुल्लू के खनाग, जलोड़ी दर्रा-सोझा के साथ सोलंगनाला के आसपास न जाने की हिदायत दी है।

जनजातीय क्षेत्र लाहौल में दो दिन से रोज हिमखंड गिर रहे हैं। जिसमें एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदारों को स्टेशन न छोड़ने और जिला कुल्लू आपदा प्रबंधन को रात दिन चौकस रहने के आदेश दिए हैं।

हेपेटाइटिस बी-सी के एमआरआई से लेकर सारे क्लीनिकल टेस्ट भी हुए फ्री, सरकार ने जारी किया कॉलेजों को पांच लाख का फंड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईजीएमसी में अब हेपेटाइटिस ए, सी, ई के एमआरआई से लेकर सारे क्लीनिक टेस्ट फ्री होंगे। मरीजों को ना तो किसी टेस्ट का खर्च उठाना होगा और ना ही उन्हें कोई दवा बाहर से खरीदने की जरूरत होगी। इसके लिए आईजीएमसी प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी कर दिए है।

इसके अलावा आईटी इंचार्ज को भी इस बारे में बता दिया है, ताकि वह सभी कैश काउंटरों पर इस बारे में व्यवस्था बना दें कि किसी भी हेपेटाइटिस मरीज के टेस्ट फीस ना कटें। इससे आईजीएमसी में आने वाले हेपेटाइटिस के मरीजों को काफी फायदा होगा। उनका इलाज में कोई खर्चा नहीं आएगा।

नेशनल वॉयरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सारा इलाज फ्री किया गया है। हालांकि इसकी घोषणा बीते वर्ष जुलाई में की गई थी। मगर अब इसके लिए पांच लाख रुपए का फंड जारी कर दिया गया है। आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कालेज में ही हेपेटाइटिस का इलाज किया जा रहा है।

कुंडू ने केंद्र से रोप-वे परियोजनाओं के लिए मांगा धन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू और लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी दी।

संजय कुंडू ने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में रोप-वे परिवहन के लिए व्यवहारिक और मजबूत साधन बन सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में रोप-वे परियोजनाओं के

लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

सब्जियां पहले ही महंगी, डिपुओं पर तीसरे महीने भी नहीं मिली दालें, उपभोक्ता परेशान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पहले ही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बीते कई माह से कोई भी सब्जी 40 रुपए से कम नहीं मिल रही। ऐसे में डिपुओं पर मिलने वाली दालें लोगों की रसोई में कुछ राहत पहुंचा देती थी। मगर जनवरी का आधा माह बीत चुका है, अभी तक डिपुओं पर दालें नहीं पहुंची पा रही है।

उपभोक्ता डिपुओं पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें आटा, तेल और चावल लेकर ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। दालों के बारे में डिपो होल्डर कह रहे हैं कि अभी दालें नहीं आई है। कब आएगी यह भी पता नहीं। ऐसे में लोगों का घर का बजट बनाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि शहर के कई डिपुओं में बीते माह भी

दालें नहीं मिली थी। ऐसे में दो माह से जब दालें नहीं मिली है तो या तो महंगे दामों पर बाजार से दालें खरीदनी पड़ रही है या फिर महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ रही है। जिससे लोगों के घरों का बजट बिगड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में कईयों के घरों से तो सब्जियां भी गायब होना शुरू हो गई है। आने वाले समय में अगर दाम बढ़े तो दिक्कतें आएगी।

बालूगंज थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजधानी के बालूगंज थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छह साल की बच्ची के साथ एक किशोर द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस बारे में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाना बालूगंज में शिकायत दी है। आरोपी 15 वर्षीय किशोर बच्ची के पड़ोस में ही रहता है। बताया जा रहा है कि खेलने के बहाने आरोपी किशोर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने यह सब बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची का मैडिकल करवाया है। पुलिस जल्द ही आरोपी

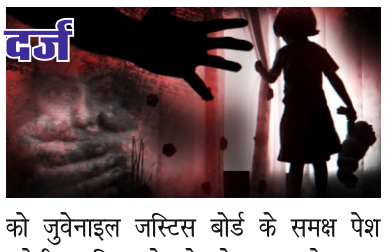

को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश करेगी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

शहर के कोर एरिया के शौचालय बनेंगे प्री फेब्रिकेटेड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजधानी शिमला के कोर एरिया में बने नगर निगम के शौचालय अब प्री फेब्रिकेटेड बनेंगे। निगम पुराने सभी शौचालयों को तोड़ कर प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाकर इन शौचालयों का निर्माण करेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

शहर के कोर एरिया में करीब 16 शौचालय ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं और गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस कारण शौचालयों में गंदगी पसरी रहती है, छत से पानी टपकता है। निगम अब इन शौचालयों को तोड़ेगा और नए शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। सोमवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रिव्यू बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसी माह के अंत तक नए शौचालयों को बनाने के लिए टेंडर भी आमंत्रित कर दिए जाएंगे। फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर से बने शौचालय आधुनिक होंगे।

भूस्खलन से किन्नौर में नेशनल हाईवे फिर बाधित, लोग परेशान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के किन्नौर जिले के भावनगर के पास डेट सुंगर नामक स्थान पर भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-5 अवरुद्ध हो गया। इससे सैलानियों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनजातीय जिला में बीते दिन जंगी में ग्लेशियर और शौंगटोंग में भारी भरकम चट्टानें गिरने के कारण नेशनल हाईवे पांच यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया था। बर्फबारी से जिले के सभी ग्रामीण रूट भी यातायात के लिए ठप पड़े हैं, जिस कारण लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। एनएचएआई के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा।

वहीं जिले के कई ग्रामीण इलाकों सहित स्पीति वैली में अंधेरा पसरा हुआ है। गौरतलब है कि बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के कारण समूचे किन्नौर जिले में विभिन्न व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। रिकांगपिओ से पूह काजा की तरफ एनएच पांच पर कई स्थानों पर ग्लेशियर और भारी भरकम चट्टानें गिरने के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए ठप रहा।

पोवारी से पूह की ओर पूर्वणी झूला, जंगी के पास, नेसंग, भगत नाला, टिंकू नाला के पास एनएच पर करीब 5 स्थानों पर पहाड़ी से ग्लेशियर आने और भूस्खलन से एनएच पांच बाधित रहा। जिले के कई ग्रामीण इलाकों सहित काजा और स्पीति में अंधेरा पसरा हुआ है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

बीपीएल से बाहर परिवारों की दोबारा होगी जांच, बीडीओ होंगे जांच अधिकारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बीपीएल सूची के दोबारा निरीक्षण के आदेश दिए हैं। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। सरवीण चौधरी ने कहा है कि किसी भी पंचायत को नियमों के विपरीत बीपीएल मुक्त घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने पर संबंधित उपमंडलाधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

सरवीण चौधरी बीते दिनों भूमती में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि बिना जांच परख किसी भी व्यक्ति को बीपीएल सूची से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बीपीएल योजना से कोई भी व्यक्ति लाभ लेने से वंचित न रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस मौके पर उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न क्षेत्रों में भूमि इंतकाल तथा भूमि पर कब्जे इत्यादि के मामलों में निर्धारित समय अवधि में जांच पूरी करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि भूमती पंचायत के प्लास्टा गांव के संपर्क मार्ग का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत सरली को शीघ्र पेयजल योजना से जोड़ा जाए ताकि लोगों को पेयजल की सुचारु आपूर्ति हो सके।

जनमंच में 147 शिकायतें पंजीकृत हुईं। इन शिकायतों में सड़क - बिजली - पानी, राजस्व और स्वास्थ्य विभागों से संबंधित शिकायतें शामिल रहीं। अधिकतर समस्याएं बीपीएल परिवारों को सूची से बाहर करने की रहीं। इनमें से 65 शिकायतें और 44 मांगें पूर्व जनमंच अवधि में प्राप्ति हुईं।

45 शिकायतों का निपटारा किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत बसंतपुर में किए जा रहे विकास कार्यों की अनियमितताओं की जांच जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी से करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर शिकायत निवारण के लिए अन्य विभागों को भी उचित दिशा-निर्देश जारी किए।

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि जनमंच के साथ-साथ अनेक कल्याणकारी योजनाएं सहायक सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं।

कमाणा में तेंदुए का आतंक, दस बकरियां को मारा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

सर्दी का प्रकोप बढ़ते ही वन्य प्राणियों ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया है। संगड़ाह उपमंडल के अंतर्गत कमाणा गांव में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। हाल ही में तेंदुए ने एक ग्रामीण की गोशाला में घुसकर दस बकरियों को अपना शिकार बना डाला। गोशाला में 13 बकरियां बंधी थीं। इनमें से दस बकरियों को तेंदुए ने शिकार बनाया। तेंदुए की दस्तक से गांव में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। बकरियों के मालिक आत्मा राम और ग्रामीण जोगेंद्र ने बताया कि तेंदुए के घुसने से गांव में अफरा-तफरी मच गई है। गांव के लोगों का कहना है कि बकरियों के मालिक आत्मा राम का रोजी रोटी का यह एकमात्र साधन था। इस व्यक्ति का रोजी रोटी का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया है। गांववासियों का कहना है कि सरकार आत्मा राम को इसका मुआवजा दे। ग्राम पंचायत प्रधान कांता देवी ने बताया कि इसके बारे में वन विभाग और पशु चिकित्सक को भी सूचित कर दिया है।

एनओसी खत्म होने के बावजूद चल रहे 12 क्रशर सील

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

बीबीएन में चल रहे राजनीतिक पहुंच वालों और रसूखदारों के एक दर्जन स्टोन क्रशर सील किए हैं। ये सभी क्रशर एनओसी खत्म होने के बाद चालू हालत में थे और विभाग को लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थीं। इनमें से कुछ क्रशर पर पहले भी कार्रवाई हुई है। इनकी बिजली काट दी गई थी इसके बावजूद क्रशरों के लगातार चालू होने की शिकायतें आती रही हैं।

खनन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जिससे क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार इन क्रशर में से कई की अनुमति पहले ही खत्म हो चुकी थी। इनमें से अधिकतर क्रशर क्षेत्र में राजनीतिक पहुंच और रसूख रखने वाले लोगों के बताए जा रहे हैं। कई क्रशरों की बिजली कटी हुई थी। कई क्रशरों की हाल ही में परमिशन खत्म हुई है। खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में ऐसे 12 क्रशरों को सील किया है। जिला खनन अधिकारी कुलभूषण शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में कार्रवाई को अंजाम दिया। कई क्रशरों की परमिशन पहले ही खत्म हो चुकी थी, किसी की बिजली कटी थी।

विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि अवैध खनन वाले क्षेत्रों में चलने वाले क्रशरों में काम हो रहा है। इस पर विभाग की टीम ने सभी क्रशरों की जांच की और पड़ताल में दस्तावेजों की कमी और परमिशन न होने से उन्हें सील बंद कर दिए हैं। जिला खनन

अधिकारी कुलभूषण शर्मा ने बताया कि बीबीएन क्षेत्र में क्रशरों पर की कार्रवाई में 12 क्रशरों में खामियां पाई गईं जिन्हें सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान इन क्रशरों की परमिशन समाप्त हो गई थी, वहीं दस्तावेज भी अधूरे थे। उन्होंने कहा कि दस्तावेज पूरे होने और परमिशन मिलने के बाद ही ये क्रशर रिस्टोर होंगे।

सिरमौर में बर्फबारी ने तोड़े कई सालों के रिकार्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने कई सालों के रिकार्ड तोड़ दिए। सिरमौर जिला भी इससे अछूता नहीं है। तापमान में आई गिरावट के बाद जिले में जमकर बर्फबारी हुई है। राजगढ़, सराहां से सटे इलाके, कफोटा, संगड़ाह आदि इलाकों में 20–25 वर्ष के बाद बर्फ के दीदार हुए। वर्षों बाद बर्फबारी देख लोगों के चेहरे खिल उठे।

कई स्थानों पर लोगों ने बर्फ के बीच डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। सिरमौर के ऊंचे इलाकों में करीब 72 घंटे से बर्फबारी हो रही है। जिले के ग्रामीण इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इससे घाटी का सौंदर्य भी निखर उठा है।

हरिपुरधार में तीन फीट, नौहराधार में दो फीट से अधिक हिमपात हो चुका है। जबकि चूड़ाधार की चोटी पर चार फुट से अधिक ताजा बर्फबारी की सूचना है। इसके अलवा

चाढना, अखरोट फार्म, देवामंडल, चौरास, धनदुरी, उलाना, सोतानी, संगड़ाह, भानरा, शामरा, नियोल तक भी बुधवार सुबह से बर्फबारी हो रही है। संगड़ाह, राजगढ़, कफोटा और सराहां से सटे टिक्कर में वर्षों बाद बर्फ के फाहे गिरे। टिक्कर में करीब छह सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। जबकि संगड़ाह, राजगढ़ और कफोटा में चार सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई।

राजगढ़ और संगड़ाह में लगभग 20 साल के बाद बर्फबारी के दीदार हुए। राजगढ़ के सनियो दीदग में अमूमन हर सर्दी में एक या दो इंच बर्फबारी होती आई है।

मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से बनेंगे पटाखे, धुआं नहीं खुशबू छोड़ेंगे

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे अब धुआं छोड़ने के बजाय खुशबू बिखेरेंगे। इनको मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से बनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर ईको फ्रेंडली पटाखों को बनाने के लिए जिला सिरमौर प्रशासन ने पहल की है। प्रशासन हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर) पालमपुर के साथ नाहन के एक पटाखा निर्माता का करार कराने जा रहा है। हर दिवाली पर आतिशबाजी से प्रदूषण खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है।

सिरमौर प्रशासन ने इस वर्ष दिवाली में ईको फ्रेंडली पटाखे बनाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध करवाने के प्रयास किए हैं। इसके लिए पटाखा निर्माता शकिल शेख को तैयार किया है।

उपायुक्त के प्रयासों से शेख और सीएसआईआर के बीच अनुबंध होगा, जिसके बाद इन पटाखों को बनाने की प्रक्रिया आरंभ होगी। उपायुक्त डा. आरके परूथी ने बताया कि इन पटाखों में केमिकल नाममात्र होगा। शकिल शेख ने बताया कि यह पटाखे दूसरे पटाखों की अपेक्षा 30 से 40 फीसदी कम प्रदूषण फैलाएंगे। हानिकारक धुआं भी नहीं छोड़ेंगे। खुशबू के लिए भी ईको फ्रेंडली केमिकल इस्तेमाल होगा।

सोलन में खुले में बिकने वाले दूध के दो सैंपल फेल

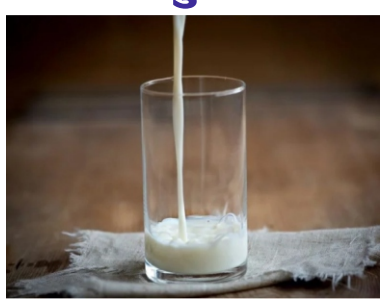

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

शहर में खुले में बिकने वाले दूध के दो सैंपल फेल हो गए। एक सैंपल सब स्टैंडर्ड जबकि सोलिड नोट फैट कम पाया गया है। अब दोनों ही व्यापारियों को 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस का जवाब न मिलने की सूरत में खाद्य सुरक्षा विभाग कोर्ट में केस करेगा। विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. एलडी ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि शहर में कुछ दिन पूर्व निरीक्षण के दौरान भरे गए हेल्थ सप्लीमेंट का एक सैंपल भी फेल हो चुका है। रिपोर्ट के आधार पर तय मानकों के अनुसार यह खरा नहीं पाया गया। इसे लेकर भी विभाग की ओर से नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा।

दूध में कीड़े निकलने की शिकायत के बाद शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गाड़ी से खुले दूध के दो सैंपल भरे गए थे। ये सैंपल स्थानीय दूध विक्रेताओं से लिए गए थे। यही नहीं, पहले भी इनके सर्विलेंस सैंपल फेल हो चुके थे, जिसके बाद विभाग ने सैंपलों को सीटीएल लैब भेजा था। यहां लीगल सैंपल भी फेल हो चुके हैं।

सीएए पर सत्ती ने शुरु किया जनसंपर्क अभियान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

प्रदेश भाजपा सत्ती ने ऊना में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत की। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के मिलकर उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के पंफलेट भी बांटे। सतपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में घर-घर जाकर सीएए पर जानकारी जनता को उपलब्ध करवाएंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए भाजपा फील्ड में रहकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की भी नागरिकता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह कानून तीन देशों के धार्मिक रूप से प्रताड़ित निवासियों को नागरिकता देने के लिए है, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। उन्होंने कहा कि देश में हताशा और निराशा के चलते कांग्रेस ऐसा वातावरण बनाना चाहती है जिससे अराजकता

फैले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ऐसे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। सत्ती ने कहा कि कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की नीतियों को भी घर - घर पहुंचाएंगे। इसके लिए भी एक पंफलेट कार्यकर्ताओं को दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता आने वाले दिनों में फील्ड में रहकर जनता से संपर्क करें और समर्थन के लिए दिए गए नंबर पर मिस कॉल भी करें। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल, महामंत्री अशोक धीमान , सुरजीत सैनी तिलक राज सैनी, बलविंद्र गोल्डी, सतीश ठाकुर, गगन ओरी, राकेश ठाकुर, भूषण पुरी, राजीव वशिष्ठ, विनोद पुरी, पंकज कालिया, खामोश जेतिक, वरुण मेहन, दीदार सिंह, सुखविंद्र सागरा, अनिल कुमार, राजेश, विजय साहिनी, नरिंद्र दूबे, उदय वीर सिंह आदि उपस्थित थे।

दुकानों का किराया नहीं चुकाने पर काटी नौ कारोबारियों की बिजली

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

नए साल की शुरूआत पर नगर परिषद नालागढ़ एक्शन मोड में आ गई है। नालागढ़ शहर के दुकानदारों से अपना बकाया वसूलने के लिए नगर परिषद ने अब उनके बिजली कनेक्शन काटना शुरू कर दिए हैं। नालागढ़ शहर में कई बकायादारों को नप ने सूचीबद्ध कर उन्हें नोटिस थमाए थे।

बारंबार चेताने पर भी बकायादारों के बकाया भुगतान नहीं चुकाने पर नप ने इनकी सूची विद्युत बोर्ड नालागढ़ को कार्रवाई के लिए सौंपी थी। विद्युत बोर्ड ने भी बकायादारों को नोटिस दिए थे लेकिन बकायादारों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। कनेक्शन कटने के बाद कई बकायादारों ने सात लाख रुपये की अदायगी भी कर दी। परिषद के सर्वेयर बलजीत राणा की अगुवाई में परिषद और विद्युत बोर्ड की टीम ने यह कार्रवाई नालागढ़ शहर में अमल में लाई।

इस कार्रवाई से बकायादारों में हड़कंप मच गया। परिषद ने 70 दुकानदारों से 70 लाख रुपये की बकाया राशि वसूलनी है। 50 दुकानदार ऐसे हैं जिनसे 50 हजार से अधिक का बकाया वसूलना है जबकि अन्य

बकायादार ऐसे हैं जिनसे 50 हजार से कम का बकाया वसूला जाना है। परिषद ने इसके लिए अपनी बैठक में कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए थे।

इसके तहत परिषद ने प्रथम चरण में 13 बकायादारों को सूची जारी कर इन पर कार्रवाई की जबकि द्वितीय चरण में एक दर्जन बकायादारों की सूची विद्युत बोर्ड को सौंपी जा रही है। नगर परिषद के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी एवं तहसीलदार नालागढ़ ने कहा कि बकायादारों की प्रथम चरण की जारी सूची के तहत नौ बकायादारों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं और कनेक्शन कटने के बाद बकायादारों ने सात लाख की राशि जमा की है।

सेना भर्ती : शपथ पत्र पर अवैध वसूली के मामले में तहसीलदार को जांच के आदेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

इंदिरा स्टेडियम ऊना में सेना भर्ती के लिए आए युवाओं से शपथ पत्र के नाम तय फीस से अधिक वसूलने वालों की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। अतिरिक्त उपायुक्त ऊना अरिंदम चौधरी ने कहा कि कुछ नोटरी पब्लिक के विरुद्ध तय शुल्क से अधिक धनराशि लेने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने तहसीलदार ऊना को इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। एडीसी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर नोटरी पब्लिक के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती में भाग लेने आए युवाओं के साथ इस तरह लूट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। जिन युवाओं के पास एफिडेविट नहीं थे, उन्हें निःशुल्क सेवा देने वाले एडवोकेट केशव चंदेल का अतिरिक्त उपायुक्त ने आभार जताया है। दूसरी ओर ईसपुर सहित बंगाणा, अंब, गगरेट समेत कई तहसीलों में भी शपथ पत्र के शुल्क के नाम पर ओवरचार्जिंग की जाने की सूचना है। उन्होंने कॉलेज में लगाए लंगर स्थल पर तुरंत प्रभाव से साफ-सफाई करने के नगर परिषद को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां पर आवश्यकता अनुसार और कूड़ेदान रखे जाएं, ताकि युवाओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो और कॉलेज में स्वच्छता बनी रहे। अरिंदम चौधरी ने सामाजिक संस्थाओं के सहयोग की सराहना करते हुए युवाओं को रहने और खाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने की पहल करने वाली संस्थाओं का आभार जताया।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

हिमकेयर योजना में स्मार्ट कार्ड बनाने की अंतिम तिथि 31 मार्च

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो गई है। इसके अंतर्गत स्मार्ट कार्ड 1 जनवरी से 31 मार्च तक बनाए जा सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर ने कहा है कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार के पांच सदस्यों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। सीएओ ने बताया कि हिमकेयर के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनाने की सुविधा लोकमित्र केंद्रों और निजी साइबर कैफे में उपलब्ध है। हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दरें तय की गई हैं।

गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल, पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले और मनरेगा के अंतर्गत जिन्होंने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है उनसे प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अंशकालिक कार्यकर्ता, अनुबंध कर्मचारी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी से केवल 365 रुपये और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है उनसे केवल 1000 रुपये का प्रीमियम अदा कर योजना के अंतर्गत कार्ड बनवा सकता है।

योजना के अंतर्गत लोकमित्र केंद्र या कहमन सर्विस सेंटर में नामांकन करने और दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लाभार्थी से प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। डॉ. दड़ोच ने बताया कि आवेदक को वेबसाइट पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवा कर और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन करवाना होगा।

दो महीने में उखड़ गई झंडूता मांडवा शाहतलाई सड़क

द रीव टाइम्स ब्यूरो बिलासपुर

उपमंडल की झंडूता मांडवा शाहतलाई मुख्य सड़क पर किया गया पैच वर्क दो माह के भीतर ही उखड़ गया।

इसके कारण सड़क पर दोबारा गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं। उखड़ी हुई बजरी से दो पहिया वाहन चालक कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। लोगों के अनुसार पैच वर्क कार्य के कुछ ही दिनों बाद सड़क से बजरी उखड़ना शुरू हो गई थी। लोगों ने लोक निर्माण विभाग से शीघ्र सड़क पर पड़े गड्ढों की मरम्मत करने की मांग की है। वहीं लोगों ने लोनिवि के कार्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों ने अन्य लोगों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने करीब दो माह पहले इस सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने के लिए पैच वर्क का कार्य करवाया था लेकिन सड़क पर कुछ दिनों बाद से ही बजरी उखड़ना शुरू हो गई थी।

इसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विभाग से समस्या का हल करने की

मांग की है। वहीं लोक निर्माण विभाग सब डिवीजन झंडूता के सहायक अभियंता प्रवीण कुमार वर्मा ने बताया कि शीघ्र ही लोगों की समस्या का हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी।

10 पेयजल योजनाओं के लिए 144 करोड़ मंजूर : कटवाल

द रीव टाइम्स, बिलासपुर

झंडूता विधायक जीत राम कटवाल ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा मुख्य वास्तुकार लोनिवि के साथ नंदनगराओं से कोटधार को जोड़ने वाले गोबिंदसागर झील के ऊपर बनने वाले पुल के स्थल और कुटवागड़ पेयजल योजना के पेयजल स्रोत स्थल, टप्पे दधोग पुल स्थल का दौरा किया।

विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र झंडूता को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र झंडूता में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 144 करोड़ रुपये की 10 पेयजल योजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति मिल चुकी है जोकि विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र झंडूता में शीघ्र ही इन पेयजल योजनाओं के क्रियान्वित होने से पेयजल किल्लत समाप्त होगी। कोटधार सहित विधानसभा क्षेत्र की 19 पंचायतों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए 38 करोड़ रुपये की डीपीआर की नाबार्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं इस पेयजल योजना में गोबिंदसागर झील से पानी उठाने की अनुमति बीबीएमबी से प्राप्त हो चुकी है जिसमें कूटवोंगड़ से 80 लाख लीटर प्रतिदिन पानी उठाया जाएगा। कटवाल ने बताया कि टप्पे दधोग के लोगों की वर्षों पुरानी पुल की मांग को पूरा किया गया है।

इस पुल का निर्माण किया जाएगा तथा इसकी शीघ्र डीपीआर बनाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। 78 करोड़ रुपये की सीआरएफ के तहत बनने वाली एमडीआर सड़क पनौल - झंडूता, नंदनगराओं - जेजवीं सड़क परियोजना कोटधार तथा झंडूता क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान बनेगी। इस परियोजना में 53 करोड़ रुपये से 330 मीटर नंद-नगराओं से छजोटी पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं 10 करोड़ रुपये झंडूता से भड़ोली कलां सड़क की अपग्रेडेशन के लिए स्वीकृत हुए हैं।

बिलासपुर रोजगार मेले में 464 युवाओं को मिला रोजगार

द रीव टाइम्स, बिलासपुर

बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से आईटीआई बिलासपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर से 1482 युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न कंपनियों की ओर से 464 युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस एक दिवसीय रोजगार मेले में 31 कंपनियों ने बिलासपुर में आकर प्रतिभावान युवाओं को रोजगार का अवसर दिया। इस दौरान विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बेरोजगार युवाओं और कंपनियों को एक ही स्थान पर आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुसार बेरोजगार युवाओं का चयन करें तथा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवा मेहनती, ईमानदार और शारीरिक रूप से हर कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। कंपनियां चयनित युवाओं को कार्य करने के लिए बेहतरीन वातावरण प्रदान करें जिससे कंपनियां भी तरक्की करें और युवाओं में भी कार्य करने की क्षमता बढ़े ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए सक्षम हों। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर प्रदेश में 93 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगे जिससे

प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस दौरान अधिकारियों की ओर से युवाओं को रोजगार से संबंधित विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर जिला रोजगार अधिकारी हंसराज गुप्ता, जिला श्रम अधिकारी प्यारे लाल साहू, प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अजेश के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

छह माह से परीक्षा परिणाम के इंतजार में 23 हजार विद्यार्थी

द रीव टाइम्स, कांगड़ा

हिमाचल के सभी निजी और सरकारी आईटीआई में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी पिछले छह महीने से वार्षिक परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

सभी आईटीआई के लगभग 23 हजार विद्यार्थियों ने जून महीने में वार्षिक परीक्षा दी है। छह महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है।

वर्ष 2019 में एनसीवीटी नई दिल्ली ने देशभर की आईटीआई में पहली बार सत्र की बजाय वार्षिक स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन किया था। इसकी कंपार्टमेंट की परीक्षाएं जनवरी - फरवरी में प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी जून में हुईं परीक्षाओं का परिणाम ही घोषित न होने के कारण कंपार्टमेंट की परीक्षाएं कब होंगी, इसको को लेकर छात्रों में असमंजस है। जून में फिर वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत भी जिन छात्रों ने पेपर दिए हैं, उसका परिणाम भी घोषित नहीं हो पाया है। वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित न होने के कारण एक साल का कोर्स करने वाले आईटीआई के विद्यार्थी सबसे ज्यादा परेशान हैं। परीक्षा परिणाम न आने से वह किसी नौकरी के लिए तक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। पिछले छह महीने से सिर्फ घरों में बेकार बैठक कर परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील वर्मा ने कहा कि आईटीआई का परीक्षा परिणाम एनसीवीटी नई दिल्ली करता है। बोर्ड की भूमिका परीक्षा संचालन तक है। उसके बाद पेपर चेक कर एनसीवीटी को भेजे जाते हैं।

आधारशिला से आगे नहीं बढ़ा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का कार्य

द रीव टाइम्स, हमीरपुर

डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर शिलान्यास तक सिमट गया है। नादौन विस क्षेत्र के अंतर्गत जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक, अकादमिक भवन और प्रशिक्षुओं के लिए हॉस्टल तथा स्टाफ के लिए आवासीय भवनों का निर्माण लटक बीते डेढ़ वर्ष से लटका पड़ा है। 16 जून 2019 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर के मैदान से इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। लेकिन डेढ़ साल से मेडिकल कालेज के नाम पर प्रस्तावित भूमि पर एक ईंट तक नहीं लगी। वर्तमान में क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर के पुराने भवन में ही मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं चल रही हैं।

लेकिन यहां पर न तो उचित क्लासरूम हैं और न ही प्रशिक्षु चिकित्सकों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था। बता दें कि यूपीए-2 निहित केंद्र सरकार ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के

विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आग्रह पर तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने हमीरपुर के नादौन के अंतर्गत आने वाले गांव जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज की अधिसूचना जारी की थी। बताया जा रहा है कि अधिसूचना के साथ ही मेडिल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपये बजट की भी व्यवस्था की गई थी।

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को हमीरपुर बुलाकर इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करवाया। उसके बाद मेडिकल कालेज प्रशासन और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के बीच निर्माण कार्य को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। लेकिन अभी तक कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया।

खेलो इंडिया के लिए सूबे की कुश्ती टीम रवाना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

गुवाहाटी में 15 से 20 जनवरी तक होने वाली खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की कुश्ती टीम रवाना हो गई है।

टीम कोच डीपीई जगदीश कुमार की अगुवाई में राष्ट्रीय स्तर पर सूबे का प्रतिनिधित्व करेगी। गुवाहाटी में होने वाली इस खेलो इंडिया प्रतियोगिता की खास बात यह है कि इसमें कई प्रकार की खेलें करवाई जाती हैं और इन सब में प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी को सरकार पांच साल तक हर माह 40 हजार रुपये का वजीफा देती है।

डीपीई जगदीश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 5 हजार खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस टीम में रावमापा पंजगाईं के ही चार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जगदीश कुमार ने कहा कि प्रदेश टीम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करके सूबे का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमकाएंगे। जगदीश कुमार रावमापा पंजगाईं में डीपीई के पद पर कार्यरत हैं। उनकी अगुवाई में रावमापा पंजगाईं के पहलवान अभी तक 28 से ज्यादा स्वर्ण पदक राष्ट्रीय प्रतियोगिता से हासिल कर चुके हैं।

अब बसों में बन सकेंगे सम्मान व ग्रीन कार्ड

द रीव टाइम्स, धर्मशाला

अब एचआरटीसी के ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड बनाने के लिए आपको काउंटर पर लगने की जरूरत नहीं। ये कार्ड अब सफर के दौरान बस में ही बन जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने यात्रियों को सस्ती बस सेवा देने के लिए फिर से अभियान छेड़ेगा। इसके तहत धर्मशाला डिपो अपने हर परिचालकों को कार्ड मुहैया करवाएगा। परिचालक इन कार्डों के माध्यम से सम्मान कार्ड, ग्रीन कार्ड और स्मार्ट कार्ड बनाने के इच्छुक यात्रियों को मौके पर ही कार्ड उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा जिला भर में लगने वाले जनमंच कार्यक्रमों के दौरान भी पथ परिवहन निगम इन कार्डों को बनाने की व्यवस्था करेगा, ताकि लोगों को घरद्वार पर ही सस्ती सेवा के लिए कार्ड बनाए जा सकें। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ

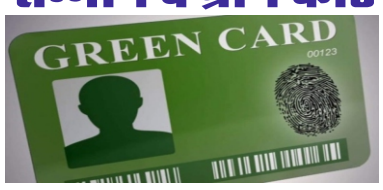

लोगों के लिए सम्मान कार्ड बनाए जाते हैं। ऐसे कार्ड धारकों को निगम की बसों में सफर के दौरान किराये में 30 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। वहीं ग्रीन कार्ड धारक को 50 किलोमीटर तक के सफर पर 25 प्रतिशत और स्मार्ट कार्डधारक को निगम की साधारण बसों में 10 प्रतिशत किराये में छूट रहती है। जिला कांगड़ा में ही अब तक हजारों लोग निगम की इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं अन्य बचे यात्री भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें, इसके लिए छूट प्रदान करने वाले कार्डों को बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा।

बीड़-बिलिंग जाने पर अब चुकाने होंगे अतिरिक्त रुपये

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

बिलिंग को जाने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों को अब प्रति वाहन 70 रुपये के स्थान पर 100 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि साडा के तहत आने वाली चार पंचायतों बीड़, चौगान, गुनेहड़ व क्योर के स्थानीय लोगों को 30 रुपये के स्थान पर मात्र 20 रुपये देने होंगे। बीड़ में स्थापित बैरियर की नीलामी में इस बार बाहरी पर्यटकों से ली जाने वाली फीस को बढ़ाया गया है, जबकि साडा की चार पंचायतों के लोगों को राहत दी गई है। वहीं अब बिलिंग घाटी में बर्फबारी होने के कारण घाटी में बाहरी पर्यटकों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। हालांकि बीड़ बिलिंग मार्ग पर कंक्रीट का कार्य जारी होने के कारण बीड़ से 10 किलोमीटर आगे के भाग का रास्ता पूरी तरह से बंद है, लेकिन पर्यटक चार किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करके बिलिंग पहुंच रहे हैं। बीड़ के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बिलिंग में वाहनों की आवाजाही को सुचारु रखने के लिए पुलिस बल तैनात करने का आग्रह किया है। उधर, एसडीएम ने बताया कि कंक्रीट के कार्य के चलते बीड़ बिलिंग मार्ग आवाजाही के लिए पूर्ण रूप से बंद है। उल्लंघना करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

भडेला पंचायत दस लाख से सियुल नदी पर बना रही नया पुल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

विकास खंड सलूणी की भडेला पंचायत सियुल नदी पर मनरेगा के तहत तीस मीटर पुल का निर्माण कर रही है। सियुल नदी पर बनने वाले तीस मीटर लंबे पुल से ग्राम पंचायत भडेला, लनोट, डियुर, पिछला डियुर और सिंगाधार की दस हजार आबादी को लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में इन पंचायतों के लोग नदी पर टूटे हुए पेड़ों को रख कर आवाजाही कर रहे हैं। नदी पर पुल बनाने के लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार लोनिवि व एनएचपीसी को ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव को भी भेजा लेकिन आज दिन तक विभाग व एनएचपीसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके चलते ग्रामीणों की समस्या बढ़ती रही। कुछेक माह पहले ग्रामीणों ने भडेला पंचायत की ग्राम सभा में उपरोक्त पुल को लेकर प्रस्ताव पास किया। इसको लेकर पंचायत को दस लाख की स्वीकृति मिल चुकी है। पंचायत की ओर से मनरेगा के तहत नदी पर पुल

बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। दो माह में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी बात पुल को बनाने में किसी ठेकेदार की लेबर नहीं लगी हुई। बल्कि स्थानीय ग्रामीण पुल बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। इसके चलते ग्रामीणों को पुल के साथ रोजगार भी हासिल हुआ है। पंचायत प्रधान लीला देवी ने बताया कि ग्राम सभा में में उपरोक्त कार्य को डाला गया था। इस कार्य की स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बीडीओ सलूणी प्रताप चौहान ने बताया कि मनरेगा के तहत दस लाख की लागत से सियुल नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए कनिष्ठ अभियंता की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। दो माह में यह कार्य पूरा हो जाएगा।

दो महीने बाद जागा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दर्ज की शिकायत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

देव आस्था के नाम पर मंडी जिले की गाहर पंचायत में वृद्ध महिला से क्रूरता मामले में दो महीने बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हरकत में आ गया है। जुब्बल कोटखाई पंचायत समिति की प्रधान प्रज्जवल बस्टा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने अब शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मामले में संलिप्त आरोपियों और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को आयोग तलब कर सकता है। आयोग की जांच पूरी होने के बाद अगर उसे लगा तो वह सरकार या जिला प्रशासन को पीड़िता को मुआवजा देने व दोषियों पर कार्रवाई को लेकर निर्देश भी जारी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि बीते नवंबर महीने के पहले हफ्ते में वृद्धा से अमानवीय व्यवहार किए जाने की बात सामने आई थी। मामला प्रकाश में आने के बाद मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद आरोपियों को जमानत भी मिल गई। चूंकि प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग ही नहीं है, ऐसे में मामला लटका रहा। अब करीब दो महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद आयोग ने मामले में शिकायत का संज्ञान लेते हुए केस रजिस्टर कर जांच शुरू की है।

चार फरवरी से शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन स्कूलों में होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

जिले के जमा दो कक्षा वाले स्कूलों में चार फरवरी से दूसरी जिला स्तरीय प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। इस संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग चंबा ने स्कूल प्रमुखों को आदेश जारी कर दिए हैं।

इसके साथ ही प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर डेटशीट भी जारी कर दी है। आदेशों के मुताबिक विभाग ने सभी स्कूलों को प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के बारे के निर्देश दिए हैं।

इससे आगामी बोर्ड परीक्षाओं में जिला चंबा के सरकारी स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम की प्रतिशतता बढ़ सकें। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में चंबा के विद्यार्थी मेरिट सूची में जगह बना सके। जानकारी के अनुसार दूसरी प्री बोर्ड परीक्षाएं चार फरवरी

से लेकर 11 फरवरी तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों में आयोजित की जाएंगी। चार फरवरी को बायोलॉजी, पांच फरवरी को मैथ, सात फरवरी को कैमेस्ट्री, नौ फरवरी को फिजिक्स और 11 फरवरी को इंग्लिश की प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। उच्च शिक्षा विभाग चंबा के उपनिदेशक देवेंद्र पॉल ने खबर की पुष्टि की है।

सलूणी-मंजीर-देवी-डियुर पेयजल योजना पर खर्च होंगे 46 करोड़ रुपये

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

सलूणी-मंजीर-देवी-डियुर पेयजल योजना पर विभाग की ओर से 46 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए विभाग ने टेंडर भी करवा दिए हैं। संबंधित ठेकेदार को तीन सालों के भीतर पेयजल योजना का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पेयजल योजना से उपमंडल की 20 पंचायतों की पेयजल किल्लत दूर होगी। पेयजल योजना से बीस पंचायतों की डेढ़ सौ बस्तियों को लाभान्वित किया जाएगा।

तीस हजार से अधिक आबादी इस पेयजल योजना का लाभ उठाएगी। इस योजना को स्वीकृति मिलने पर लोगों में खुशी है। पंचायत समिति उपाध्यक्ष योग सिंह गौतम, मंजीर के प्रधान नरेंद्र कुमार, दिघाई प्रधान महेशो देवी, सूरी प्रधान लीला देवी, खरल के बीडीसी सदस्य किशोरी लाल, बीडीसी सदस्य बिंदिया ठाकुर और मुकेश शर्मा ने बताया कि उपरोक्त पेयजल योजना से ग्राम पंचायत सलूणी, खरोटी, लिग्गा, खरल, सियुला, सालवां, मोडा, सेरी, दिघाई, मंजीर, ब्याणा, सिंगाधार, डियुर, डांड, पुखरी सहित अन्य पंचायतें लाभान्वित होंगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष डीएस ठाकुर का आभार जताया है। आईपीएच विभाग के अधिशाषी अभियंता सरवन कुमार ने बताया कि उपरोक्त योजना के टेंडर हो चुके हैं। तीन सालों में पेयजल योजना का कार्य भी पूरा हो जाएगा। ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जल जीवन मिशन के तहत 37 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना स्वीकृत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भटियात उपमंडल के वन विश्राम गृह हटली में भटियात उपमंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ककीरा कस्बा, गौहर परछोड़ और अन्य गांव के लिए जल जीवन मिशन के तहत 37 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना स्वीकृत की है। योजना के तहत 7 ग्राम पंचायतों के 16 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि हर घर को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई योजनाओं के माध्यम से फसलों में विविधता लाने और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भटियात विस क्षेत्र में 18 से 20 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए फरवरी माह तक रूपरेखा को तैयार किया जाए। इससे क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी को बल मिल सके। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में ब्लैक अंबर प्रजाति के प्लम, ग्राफ्टेड अखरोट और सेब की उन्नत प्रजाति के पौधे बागवानों को उपलब्ध करवाएं और यहां के बागवानों को सस्ते दामों पर एंटी हेल नेट भी उपलब्ध करवाए जाएं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 84 करोड़ की

21 सड़क मार्गों के लिए बजट स्वीकृत है। इसके साथ साथ उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों की दशा सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें और लाभान्वित करें।

रोपवे से जुड़ेगा मंडी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ बगलामुखी मंदिर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

जिला मंडी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर रोपवे से जल्द जुड़ेगा। यह रोपवे चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे-3 पर पंडोह डैम से मंदिर तक बनाया जाएगा। इसकी लंबाई करीब एक किलोमीटर होगी। इसका रूट तैयार कर लिया गया है और इसे हरी झंडी भी मिल चुकी है। अगर सरकार की कवायद रंग लाती है तो मंदिर जाने के लिए दस किलोमीटर की दूरी कम होगी। प्रदेश सरकार ने रोपवे के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके तैयार होने पर लोगों को आने-जाने की सुविधा मिलेगी। यह प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर शुरू होगा।

प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर अलॉट होने के बाद कंपनी को एक साल के भीतर प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर को रोप-वे की सुविधा से जोड़ने की घोषणा की थी। इसी के तहत प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर शीघ्र कंपनी का चयन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (लोक निर्माण और पर्यटन विभाग) ने इच्छुक कंपनियों से रोपवे के निर्माण का रखरखाव और इसके संचालन के लिए बात भी की है। रोप-वे बन जाने से एक घंटे में 500 लोगों को लाने ले जाने की सुविधा मिलेगी। मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इस धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन के साथ जोड़ते हुए पर्यटकों को रोप-वे की सुविधा देने जा रही है। बगलामुखी माता के प्रति लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहां साल भर लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल साथ सटे होने के कारण अधिकतर पर्यटक इस मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं।

मंदिर तक पहुंचने के लिए अभी तक रोपवे की सुविधा नहीं है। श्रद्धालुओं को सड़क से आठ से दस किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है।

बर्फबारी से 400 ट्रांसफार्मर बंद, दो दर्जन पेयजल योजनाएं जाम

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिले में बर्फबारी व बारिश के बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी से कुल्लू में 400 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। इससे कड़ाके की ठंड के बीच कई गांव अंधेरे में डूब गए हैं।

इसके साथ ही बर्फबारी का असर पेयजल योजनाओं का पर भी हुआ है। दो दर्जन पेयजल योजनाएं जाम हो गई हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पेयजल को तरस गए हैं। लोगों को बर्फ के बीच कई किमी पैदल चलकर पानी ढोना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू उपमंडल में 17, मनाली उपमंडल में 214, बंजार उपमंडल में 83, जबकि बाह्य सराज में भी 100 ट्रांसफार्मर बंद हैं। मनाली में भारी बर्फबारी हुई है। भारी हिमपात का असर बिजली लाइनों पर पड़ा है। इसके चलते यहां पर सबसे अधिक बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। मनाली में बर्फबारी व बारिश का दौर जारी रहा। ऐसे में बंद पड़ी बिजली आपूर्ति को सुचारु करना बिजली बोर्ड के लिए भी मुश्किल काम है।

मौसम विभाग ने वीरवार को भी मौसम खराब रहने का अंदेशा जताया है। ऐसे में अगर और बर्फ गिरती है तो और भी ट्रांसफार्मर बंद हो सकते हैं। बिजली बोर्ड की ओर से बर्फबारी व बारिश का दौर थमने के बाद ही विद्युत आपूर्ति को सुचारु करने का कार्य किया जाएगा। दूसरी ओर बर्फबारी के बीच बिजली गुल होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिजली चले जाने से हीटर का

इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। भारी बर्फबारी से दो दर्जन पेयजल योजनाएं जाम हो गई हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुश्किलें आ रही है। उधर, इस संबंध में उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि सभी विभागों को बिजली, पानी, सड़कें, दूरसंचार सेवा सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचायतों में साल में चार बार होंगीं ग्राम सभाएं

द रीव टाइम्स, कुल्लू

जिला कुल्लू की सभी 204 पंचायतों में इस वर्ष होने वाली चार ग्राम सभाओं की बैठकों की तिथियां तय कर दी गई हैं। जिला पंचायत अधिकारी विमला भट्टी ने जिला के पांचों विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के लिए ये तिथियां अधिसूचित भी कर दी हैं। 2020 में पांच जनवरी, पांच अप्रैल, पांच जुलाई और चार अक्तूबर को विकास खंड कुल्लू की बंदरोल, कोठीसारी, फलाण, माशना, भूमतीर, बाराहार, भूलंग, कलैहली, न्यूल, सचाणी, हुरला, बड़ा भुईंन, छैंउर, जलुग्रां, मणिकर्ण, पीणी, बाशिंग और जरी, विकास खंड नग्गर की अरछंडी, नग्गर, दुआड़ा, पनगां, जगतसुख, पलचान, मनाली, पुईद, कराड़सू और मलाणा पंचायत में ग्राम सभा होगी।

साथ ही विकास खंड बंजार की गाड़ापारली, सुचौहण, कनौन, गोपालपुर, चनौन, श्रीकोट, कंडीधार, बाहू और शिकारीघाट, विकास खंड आनी की करशैईगाड़, टकरासी, कुंगश, देउठी, शिल्ली, कुठेड़ और आनी, विकास खंड निरमंड की अरसू, बाहवा, बाड़ी, भालसी, चायल, देहरा और दुराह में पहले चरण की ग्राम सभाएं होगी।

12 जनवरी, 12 अप्रैल, 12 जुलाई और 11 अक्तूबर को विकास खंड कुल्लू की जिंदौड़, डुघीलग, मानगढ़, पीज, खड़ीहार, खोखण, भलाण-प्रथम, जेष्ठा, नरैश, भुईन, रतोचा, पुंथल, बरशैण, जिया, दनोगी, नलहाच, नारली और रैला, विकास खंड नग्गर की हलाण-प्रथम, पिछलीहार, हलाण-द्वितीय, नथान, गोजरा, शनाग, वशिष्ठ, नसोगी, गाहर और शलीण, विकास खंड बंजार की शैंशर, बनोगी, लारजी, थाटीबीड़, देउठा, तुंग, कोठीचौहणी, सराज और बलागाड़, विकास खंड आनी की फनौटी, बिशलाधार, रोपा, खणी, बुच्छैर, नमहोग, डिंगीधार और लगौटी, विकास खंड निरमंड की डीम, गडेज, गमोग, घाटू, कोट, खरगा और कुशवा में ग्राम सभा होगी।

19 जनवरी, 19 अप्रैल, 19 जुलाई और 18 अक्तूबर को विकास खंड कुल्लू की बनोगी, बस्तोरी, मझाट, ब्राह्मण, बल्ह, मौहल, शुरढ़, बजौरा, रोट, मंझली, दियार, बुआई, चौंग, शाट, कसोल, तलपीणी, मशगां और तलाड़ा, विकास खंड नग्गर की जाणा, मंडलगढ़, शिरढ़, रायसन, प्रीणी, बुरूआ, तलोगी, बराण, काईस और करजां, विकास खंड बंजार की देउरीधार, दुशाहड़, कोटला, मंगलौर, कलवारी, शरची, तांदी, टील और खाबल, विकास खंड आनी की पोखरी, लझेरी, कमांद, च्वाई, जाबन, दलाश, पलेही और बैहना, विकास खंड निरमंड की लोट, निशानी, निरमंड, नोर, नित्थर, पोशना और राहणु पंचायत में ग्राम सभा होगी। 26 जनवरी, 26 अप्रैल, 26 जुलाई और 25 अक्तूबर को विकास खंड कुल्लू की ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर, चौपाड़सा, भल्याणी, शिलानाल, बशौणा, जरड़ भुट्ठी कॉलोनी, शमशी, तेगूबेहड़, हाट, शिल्लीहार, बराधा, भ्रैण, भलाण-द्वितीय, शिलीराजगिरी, देवगढ़गोही और गड़सा, विकास खंड नग्गर की देवगढ़, हुरंग, कटराईं, बड़ाग्रां, रियाड़ा, सेउगी, नेउली, चंसारी, बैंची और सोयल, विकास खंड बंजार की शांघड़, धाउगी, चकुरठा, पलाहच, नोहांडा, मशियार, शिल्ही, खाड़ागाड़ और मोहनी, विकास खंड आनी की तलूणा, ब्यूंगल, बखनाओं, कोहिला, खनाग, कराणा, मुंडदढ़, कराड़ और मुहान, विकास खंड निरमंड की सराहन, शिल्ली, सरघा, त्वार और तुनन पंचायत में ग्राम सभा होगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

विलंबित कब्जे के लिए बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही

1993 में लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम के गुप्ता के प्रसिद्ध मामले में पारित एक ऐतिहासिक फैसले के कारण, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पारित किया कि किसी भी तरह से आवास निर्माण कार्य में संलग्न ''सभी बिल्डर–ठेकेदार सभी राज्यों के संबंधित प्राधिकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवास कार्यकलाप से संबंधित किसी भी कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी हो सकता है, जैसेः 'कब्जे के वितरण में देरी, निर्धारित समय के भीतर निर्माण की पूर्ण नहीं करना, दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण निर्माण और अधिक ... ' निर्णय स्पष्ट रूप से इस तथ्य को बताता है कि एक बिल्डर जो घर का निर्माण करता है या एक संपत्ति विकसित करने के लिए ठेकेदार की सेवाएं लेता है, अपने ग्राहक को सेवा प्रदान करने के कार्य में संलग्न है, और जिसके लिए उसे पैसे मिल रहे है। यह उन्हें एक सेवा प्रदाता बनाता है और इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा के तहत उत्तरदायी है।

अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा परिषद ने निम्नलिखित आधारों को सूचीबद्ध किया है जिसमें एक संपत्ति खरीदार एक अक्षम संपत्ति डेवलपर को उपभोक्ता न्यायालय में ले जा सकता है।

एक संपत्ति खरीदार निम्नलिखित स्थितियों में मामला दर्ज कर सकता है

1. पर्याप्त अग्रिम राशि प्राप्त करने के बावजूद प्रासंगिक बिक्री अनुबंध का निष्पादन नहीं करना
2. सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां जारी नहीं करना, विकास अनुबंध, मुख्तारनामा, स्वीकृत योजना (संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा), मंजूर योजना के अनुसार निर्माण सामग्री, डिजाइन के विनिर्देश और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज
3. सहमत राशि से अधिक दाम लेना
4. भुगतान की गई राशि के लिए उचित प्राप्तियां जारी नहीं करना
5. खराब गुणवत्ता का निर्माण
6. सहमत विनिर्देशों का पालन न करने वाले एक घर को वितरित करना
7. परिसर के भीतर कोई मुफ्त पार्किंग स्थान नहीं है
8. एक सहकारी आवास सोसाइटी का निर्माण नहीं किया और घर सदस्यों को सौंप दिए ।
9. जल भंडारण टैंक का प्रावधान नहीं है
10. उचित वेंटिलेशन और प्रकाश का प्रावधान नहीं है
11. निर्धारित समय सीमा से परे विलंबित कब्जा
12. संबंधित प्राधिकरण के वास्तुकार द्वारा पंजीकृत पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं करना ।
13. अपने रहने वालों के लिए संबंधित फ्लैट, घर के वितरण के समय अधिवास प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया ।
14. व्यय जिसके लिए डेवलपर ने धन अर्जित किया की घोषणा न करना ।

कोई परियोजना उपरोक्त लिखित कारणों में कम पड़ती है या अनुपालन नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए उत्तरदायी और योग्य है।

उपभोक्ता न्यायालय में किसी निर्माता के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें?

एक निर्माता को एक सेवा प्रदाता के रूप में बुलाया जाता है, उनके खिलाफ एक उपभोक्ता अदालत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया अन्य सेवा प्रदाताओं के समान है।

एक बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए नीचे दिए गये कदम उठाए जाते हैं:

1. अपने असंतोष के कारणों को बताते हुए निर्माता को एक अच्छी तरह से प्रारूपित कानूनी नोटीस भेजें
2. अन्य पक्ष (निर्माता) की ओर से निर्धारित समय के लिए प्रतिक्रिया का इंतजार करना
3. अगर कोई जवाब नहीं मिलता, तो विशेषज्ञ कानूनी सलाह की सहायता से तथ्यों और प्रमाणों को बताते हुए एक याचिका तैयार करें
4. उपभोक्ता न्यायालय से संपर्क करें और बिल्डर के खिलाफ अपनी याचिका दायर करें
5. किसी बिल्डर के द्वारा कब्जे में देरी करने की स्थिति में, कोई समय सीमा नहीं है जिसका खरीदार को शिकायत दर्ज करने के लिए पालन करना होगा।

बिल्डर के अधिग्रहण विस्थापन पर राष्ट्रीय आयोग का फैसला

राष्ट्रीय आयोग ने एक फैसले में कहा कि 'बिल्डर पर कार्रवाई का कारण साइट के आवंटन या आवंटन के इनकार पर धन की पूरी वापसी तक जारी रहता है' जिसका मतलब है कि उसको सेवा अनुबंध का सम्मान करने के लिए, चाहे कितनी देरी हो, बिल्डर को अनुबंध का पालन कर समय पर कार्य पूरा करना होगा । फिर आयोग द्वारा एक और तथ्य यह बताया गया था कि 'डेवलपर प्रत्येक संपत्ति बिक्री के लिए एक अनुबंध करने के लिए उत्तरदायी है और ऐसा करने में विफलता, उपभोक्ता न्यायालय में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई का कारण हो सकती है ।'

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

जीवन में स्वस्थ रहने के लिए अपनाये ये तरीके

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आज हर सफल व्यक्ति खुद को जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनाने में लगा हुआ है । खुद को ऐसे मुकाम पर ले जाने की कोशिश करने में लगा है जहाँ उसका जीवन सुखी और खुशहाली से भरपूर हो । अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वह नए तरीके ढूंढता है और नए विचारों को अपनाता रहता है ।

इस कामयाबी या अपने सपनो को पाने में कई लोग सफल हो जाते है किन्तु कई ऐसे लोग भी होते है जो अपने जीवन में सफलता पाकर भी खुश नहीं रहते । उनके पास दौलत होती है, परिवार होता है, इज्जत होती है तथा अपने ऐशो-आराम की हर चीज को खरीदने के वे काबिल भी होते है । लेकिन उनके पास जो चीज नहीं होती वह है-अच्छी सेहत । जब वे खुद को स्वस्थ ही नहीं रख पाते तो ऐसी सफलता तथा धन - दौलत उनके किसी काम की नहीं रहती ।

1. खाने में संतुलन अपनाये

अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खाना या भोजन प्रमुख भूमिका निभाता है । अगर आपका खाना अच्छा और पौष्टिक होगा तो वह आपकी सेहत को भी अच्छा बनाएगा वही अगर आप अपने भोजन के प्रति लापरवाही बरतते है या पौष्टिक भोजन नहीं लेते है तो यह आपके स्वास्थ्य को बीमार बना देगा । आपको कौन सी चीज खानी चाहिए तथा किन चीजों से आपको परहेज करना चाहिए यह बात आपको अपने शरीर के हिसाब से पता होनी चाहिए ।

2. अपनी दिनचर्या को रखे संतुलित

हमारी दिनचर्या का जितना प्रभाव हमारी सफलता पर होता है उतना ही असर इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है । अगर आपकी दिनचर्या बहुत संतुलित होगी तो आपका स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा रहेगा । जब हमारी दिनचर्या रोजाना एक ही होती है तो इससे हमारे मन को हमारे शरीर को समझने में बड़ी आसानी होती है और वह हर काम को करने का आदी बन जाता है ।

सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, हमारी दिनचर्या यानि दिन भर का शेड्यूल क्या हो, यह हमारी सेहत के लिए जानना बहुत जरुरी है । मान ले आप रोज सुबह 6 बजे उठते है तो हल्का व्यायाम या मोर्निंग वाक करने के बाद नहा ले । फिर अपने रोजाना के समय पर नाश्ता करे और नाश्ता करने के बाद 15 मिनट आराम करे । उसके बाद फिर आपको अपने काम में लग जाना चाहिए ।

ऋतुचर्या का मतलब है ऋतु के मुताबिक हो जाना । प्रकृति का नियम है परिवर्तन, इससे प्रकृति हमें यह सन्देश देती है कि अब हमें भी प्रकृति के हिसाब से खुद को परिवर्तित कर देना चाहिए । जाड़ा, गर्मी और बरसात प्रकृति में जब ऋतु परिवर्तन होता है तब हमें भी खुद में परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए ।

3. जैसे ऋतु के बदल जाने पर प्रकृति में बदलाव दिखाई पड़ता है, उसी तरह हमें अपने खान-पान, रहन-सहन, दिनचर्या और योगासनों में भी बदलाव कर लेना चाहिए । प्रकृति ने हर ऋतु के अनुकूल फल, सब्जी और खाद्य पदार्थ बनाये है ।

मसलन की कोल्ड स्टोरेज में रखा तरबूज या बेल, बरसात के महीने में सेवन नहीं करना चाहिये तथा ठन्डे के दिनों में हमें ठंडी चीजो का सेवन नहीं करना चाहिए ।

4. योगासन अपनाकर रहे स्वस्थ

आज योग हमारे जीवन में अपना प्रमुख योगदान निभा रहा है । योग करना आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है । योग करना इतना अधिक प्रचलित यों ही नहीं हुआ बल्कि योग द्वारा ऐसे परिणाम भी हमारे सामने आये है जिसमे किसी को भी अचरज हो । योग द्वारा कई लोगो ने गंभीर बीमारियों से निकलकर स्वस्थ जीवन पाया है । इसलिए योग करना हमारे हेल्थ के लिए भी बहुमूल्य है ।

5. पॉजिटिव सोच अपनायें

दोस्तों सकारात्मक सोच हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका अदा करती है यह आप जरुर जानते होंगे । ज्यादातर तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं नेगेटिव सोच की वजह से पैदा होती है । इसलिए तनाव व डिप्रेशन से लड़ने के लिए हमें अपनी थिंकिंग को सकारात्मक बनाना होगा । आपको अपनी सकारात्मक सोच को बढाने के लिए रोजाना भ्रामरी का अभ्यास करना चाहिए । रोज सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दे ।

6. खुलकर हँसने का प्रयास करे

अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आप एक रूठे हुए इन्सान या एक हँसते हुए इन्सान में से किसी एक का चुनाव करे तो आपकी पसंद वह हँसता हुआ इन्सान ही होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी लोग हँसते-मुस्कराते हुए व्यक्ति के साथ रहना ही पसंद करते है । कोई भी मायूस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहेगा । हमेशा खुश रहने से या हँसते-खिलखिलाने से हमारी खुबसूरती भी बहुत बढ़ जाती है जो हमारे व्यक्तित्व में चार चाँद लगाती है ।

7. तन व मन में रखे संतुलन

सन्तुलित आहार, आसन-व्यायाम और अन्य तरीको को आजमाने से आप यह बिल्कुल भी न समझे कि आप पूरी तरह फिट है क्योंकि खुद को सेहतमंद बनाये रखने का यह मतलब नहीं है कि आप कोई भी शारारिक या मानसिक काम से तौबा करे । अगर आपका काम मानसिक रूप से अधिक होता है तो फुरसत में थोड़ा बहुत शारारिक कार्य भी करे और अगर वही आप शारारिक कार्य अधिक करते है तो खुद को मानसिक रूप से बेहतर रखने के लिए अपने आप को समय दें और अपना मनचाहा कार्य करे जिससे आपको अच्छा महसूस होगा।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला

अधिक जानकारी के लिए लिखें:hem.raj@iirdshimla.org

इस बार द रीव टाइम्स आपको बता रहा है कि कैसे बनाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पुराने और व्यापक विषयों में से एक इंजीनियरिंग विषय है । यह मशीन्स और टूल्स की डिजाइनिंग, प्रोडक्शन और ऑपरेशन के लिए हीट और मैकेनिकल पॉवर के उत्पादन और इस्तेमाल से संबद्ध है। इस फील्ड में करियर शुरू करने वाले छात्रों के लिये यह बहुत ज़रुरी है कि उन्हें कोर कन्सेप्ट्स जैसे कि, मैकेनिक्स, कीनेमेटीक्स, थर्मोडायनामिक्स, मेटीरियल साइंस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस आदि की अच्छी समझ होनी चाहिए । इन कोर्सेज में मुख्यतः टेक्निकल एरियाज जैसेकि जनरेटर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर्स, डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स, अहटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट और अन्य हैवी व्हीकल्स शामिल हैं ।

मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं?

मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके जीवन के तकरीबन हरेक पहलू को प्रभावित करती है । अधिकांश चीजें, जो हम अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर्स ही डिजाइन और डेवलप करते हैं। उदाहरण के लिए, माइक्रो-सेन्सर्स, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेज, रोबोट्स और कई अन्य वस्तुऐं हमारे जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इन नई डिवाइसेज और इक्विपमेंट से मदद मिलती है ।

डिप्लोमा कोर्सेजः यह कोर्स छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ऑफर करता है और आप 10 वीं और 12 वीं क्लास पास करने के बाद यह कोर्स कर सकते हैं । इस कोर्स की ड्यूरेशन या अवधि 3 वर्ष है ।

अंडरग्रेजुएट कोर्सेज : यह एक 4 वर्ष की अवधि का कोर्स है जिसे पूरा करने पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक (बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) की डिग्री मिलती है । आप 12 वीं क्लास पास करने के बाद यह कोर्स कर सकते हैं ।

पोस्टग्रेजुएट कोर्सेजः यह 2 वर्ष की अवधि का कोर्स है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक (मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी) की पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री ऑफर करता है । इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपके पास उपयुक्त फील्ड में अंडरग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए ।

डॉक्टोरल कोर्सेज : यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टोरल डिग्री या पीएचडी (डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी की डिग्री) प्राप्त करने के लिए एक 3 वर्ष की अवधि का कोर्स है । यह कोर्स करने के लिए छात्रों के पास किसी उपयुक्त विषय में पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुख्य विषय

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शामिल कुछ मुख्य विषय निम्नलिखित हैं:

- कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर
- कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑफ थर्मल सिस्टम
- फंडामेंटल्स ऑफ कास्टिंग एंड सॉलिडीफिकेशन
- इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च
- मॉडलिंग ऑफ टरबूलेंट कम्बस्शन
- प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन कंट्रोल
- रेलरोड व्हीकल डायनामिक्स
- रोबोट मैनिपुलेटर्स डायनामिक्स एंड कंट्रोल
- ट्रांजीशन एंड टर्बुलेंस
- वेब प्रोपेगेशन इन सोलिड्स

एडमिशन प्रोसेस

मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग विषयों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोर्सेज में से एक है। छात्र विभिन्न लेवल्स जैसे कि डिप्लोमा, अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, डॉक्टोरल के तहत मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई कोर्स कर सकते हैं। लेकिन, उक्त कोर्सेज में से हरेक कोर्स के लिए पहले से जरूरी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और छात्रों के पास अवश्य ये योग्यतायें होनी चाहियें । इसलिये, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विभिन्न कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निम्नलिखित हैः

डिप्लोमा कोर्सेज : छात्र ने किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10 वीं क्लास का एग्जाम पास किया हो । छात्र ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आदि मुख्य विषयों के साथ 12 वीं क्लास पास की हो ।

अंडरग्रेजुएट कोर्सेजः यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए छात्र को उपयुक्त एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं । इसके अलावा, छात्र ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आदि मुख्य विषयों के साथ 12 वीं क्लास पास की हो ।

पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज : पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए भी छात्र को उपयुक्त एंट्रेंस एग्जाम्स पास करने होते हैं । छात्र के पास किसी मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से संबद्ध विषय में अंडरग्रेजुएट की डिग्री भी होनी चाहिए ।

डॉक्टोरल कोर्सेज : डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, छात्र के पास किसी मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी संबद्ध विषय में पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री अवश्य होनी चाहिए ।

मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई अन्य कार्यों के साथ ही मशीन्स की डिजाइनिंग और टेस्टिंग के विभिन्न पहलू शामिल हैं । इस जहब में विभिन्न फील्ड्स जैसेकि, थर्मल पॉवर प्लांट्स, न्यूक्लियर स्टेशन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आदि में लाइव प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और सुपरविजन के कार्य आते हैं । इस फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स, क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि कुछ नई और ऐमर्जिंग फील्ड्स हैं । इंजीनियरिंग में अंडरग्रेजुएट डिग्रीज प्राप्त करने के बाद छात्रों के लिए मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सर्विसेज और डेवलपमेंट की विभिन्न फील्ड्स में जॉब के काफी अच्छे अवसर मौजूद हैं । आजकल हम मशीन्स के युग में जी रहे हैं और जहां एक मशीन है, वहां एक मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है । इसलिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कभी भी जॉब ऑप्शन्स की कमी नहीं हो सकती है ।

HOW LONG WILL WE REMAIN IN THE STATE OF CONFUSION ?

The Republic of India has been passing through a state of turmoil for quite some time despite the fact that there seems complete clarity in the affairs of the Government. The groups who earn their bread and butter by being in the limelight amongst the people of their influential, are bound to create confusion amongst the people, otherwise they will find themselves losing their importance. In fact, the nation is being regulated by the big nexus on different fronts, it may be the money-makers, the power hungry people, land mafias, mega industries or whether the communal heroes.

The recent agitation against the **Citizenship Amendment Act (CAA)** at Shaheen Bagh of Delhi and other places across the country clearly show that the government machinery has failed to stop illegal and illogical agitations from taking place. The Constitution of India gives right to an individual to raise one's voice if they find any issue to be detrimental and derogatory to the common good. This democratic right can be seen in the light of the Fundamental Right of 'Freedom of Speech', 'Right to Freedom to Assemble and Demonstrate' by holding dharnas or peaceful agitations. People have the right to raise their voice against the decisions and actions of the government on any subject of social or national importance.

With the right to freedom of disagreement with the decisions of the government, people need to know their duty of being Responsible Citizens. When 'rights' are used without the due importance to the 'duties', the rights starts losing their essence. The agitator have to introspect whether their conduct comes in the purview of being a **Responsible Citizen**.

Here the intent and concern of the agitators need to be spelt out.

The Citizen Amendment Act which came into effect on December 12, 2019, is a noble step towards ensuring shelter to the persecuted minority of the neighbouring nations, namely Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. These people could not come to India during the Partition, and have been facing discrimination, persecution in these Islamic countries and have entered into the Indian soil prior to 2014 and who wish to apply for the Citizenship of India hence forth. India has been the country of Budha and Gandhi, which preaches and acts on the principle of

" सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत् ।" – a universal doctrine to 'live and let live', with the prayer and appeal of universal brotherhood. Though the past governments had also taken the cognizance of minorities' struggle in neighbouring islamic countries, but could not dare to adopt this.

With the enactment of this provision, no citizen of India, irrespective of cast, creed and religion, is going to get affected adversely. Moreover, the present number of such recognition of new citizens is in mere hundreds and, that too, in the vast population of more than 130 crores.

Interestingly, the concern of the agitators is not to stop the entry of the new citizens into Indian territory, but the concerns of the agitation are pertaining to so-called ''National Register of Citizen'', which has so far not come in the picture officially, but present in the realm of ideas only.

No citizen can be allowed to demonstrate on the subjects which are not at all in existence. With such narrow mindset we are gradually going to demean and decline our proud label of 'Responsible Citizen'.

The political and communal mafias behind such irrelevant agitations need to be dealt with effectively and the government also need to make its firm communication on what concrete steps have to be taken in this regard so that peaceful atmosphere and law can be upheld for the benefit and safety of the Indians, the present ones and the ones who will soon legally become the citizens of this great nation.

Dr. L.C. Sharma
Editor-in-Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

भारतीय सभ्यता और संविधान

पारंपरिक भारत ही आज के भारत का उद्भव और स्रोत है। यही भारत के अस्तित्व की रीढ़ है। दार्शनिक स्तर पर यही उसकी आत्मा है। यदि अत्यधिक आधुनिकता से अंधे हो गए 'आधुनिक' भारतीय सभी परंपराओं को पिछड़ी बताकर खारिज नहीं करते और उनका असर महसूस करने से चूक नहीं जाते तो यह जीवन के हरेक क्षेत्र में नजर आता है। भारत में दर्शन एवं अध्यात्म की खोज स्पष्ट दिखती है और समय-समय पर भारत के जनसामान्य को एक साथ लाती है तथा उन्हें उनकी धरती से ऐसे पवित्र विचार के माध्यम से जोड़ती है, जिसे कोई अन्य सभ्यता जानती ही नहीं है। वास्तव में लोगों को एकजुट करने और उन्हें उनकी धरती से जोड़ने की इस प्राचीन राष्ट्र की क्षमता ही राष्ट्रीयता का आधार है।

भारतीय सभ्यता ने अपनी धरती से मजबूती से जुड़ी अपनी आस्था का न तो युद्ध के जरिये अपनी सीमा के बाहर विस्तार किया और न ही दूसरे लोगों या देशों पर इसे जबरन थोपा । इसीलिए इसकी आस्था न तो दूसरे क्षेत्रों या लोगों में गई और न ही उनकी पहचान में इसकी मिलावट हुई। इसीलिए इसकी पहचान भारत की धरती से ही जुड़ी रही । इसका धार्मिक प्रभाव जब इसकी सीमाओं से बाहर गया तो भी भारतीय धर्म दूसरे क्षेत्रों की आस्थाओं और संस्कृतियों के साथ फले-फूले और उस क्षेत्र पर भारतीय शासन स्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार भारत ने चीन पर बौद्ध मत थोपने का प्रयास नहीं किया। उसके बजाय चीन ने स्वयं ही बौद्ध मत स्वीकार किया। इंडोनेशिया और अन्य पूर्वी देशों में हिंदू प्रभाव का मामला भी इसी तरह का था। जो धर्म भारत भूमि से जुड़ी आस्थाओं का समूह है, उसकी अनूठी विशेषता यह है कि वह टकराव से दूर रहता है।

अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता के सिद्धांत वाले इस धर्म ने कभी किसी अन्य धर्म का विरोध नहीं किया है। इसके उलट इसने दूसरे सभी धर्मों को सबको समाहित करने वाले अपने समुदाय में मिला लिया। चूंकि यह टकराव से दूर रहता है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं रही। इसने सर्व धर्म समभाव के सिद्धांत में विश्वास किया। इन्हीं परंपराओं ने सदियों तक संरक्षण देने वाली सत्ता नहीं होने और इसकी आत्मा को नीचा दिखाने तथा नष्ट करने पर आमादा शत्रु सत्ता होने के बाद भी इस प्राचीन देश का अस्तित्व बरकरार रखा है एवं इसकी आत्मा की रक्षा की है। कोई भी 'आधुनिक' सत्ता अज्ञात काल की इस प्राचीनता और परंपराओं की लगातार सहायता के बगैर इस देश में नहीं चल सकती। यह पारंपरिक भारत आध्यात्मिक भारत से जुड़ा हुआ है और उससे अलग नहीं हो सकता।

लेकिन भारत को संगठित देश का व्यक्तित्व देने में पारंपरिक भारत का महत्व एकदम स्पष्ट होने के बाद भी स्वतंत्र भारत के संविधानवाद और राजनीतिक प्रतिष्ठान ने 'आधुनिक' भारत का सफलतापूर्वक वास्तविक भारत के रूप में गठन किया है और प्रचारित भी किया है। और 'आधुनिक' संवैधानिक भारत पारंपरिक भारत पर गर्व तो क्या करेगा, उसने उतनी ही सफलता के साथ उस भारत को भूलने लायक और खेद करने लायक खराबी बताते हुए तुच्छ बना दिया है। पारंपरिक भारत को झगड़ालू और कठिन तथा पिछड़ा बताते हुए आधुनिक भारत उसे बोझ की तरह खारिज करता गया। ऐसा करते-करते और पारंपरिक भारत के बारे में अपनी कल्पनाओं को सच मानकर आधुनिक भारत ने स्वयं को उन आध्यात्मिक मूल्यों से काट लिया, जो पारंपरिक भारत के हृदय में बसी हैं।

'आधुनिक' भारत का विचार दार्शनिक स्तर पर प्राचीन अंग्रेजी मॉडल पर आधारित है, जिसे ईसाइयत के उन प्रयोगों और अनुभवों पर गढ़ा गया है, जो उसने व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा उदारता को आधुनिकता का प्रतीक मानते हुए किए गए। संक्षेप में कहा जाए तो आधुनिक भारत ऐसी अनूठी और मोहक प्रयोगशाला है, जो इस प्राचीन राष्ट्र के मूल एवं स्थानीय विचारों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए इस पर प्राचीन अंग्रेजी अनुभवों को थोपकर प्रयोग करने में लगातार जुटी है। भारत में जबरन थोपी गई आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करने वाला इस अनजाने दर्शन और बाहरी संस्थानों ने पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक भारत के सौहार्द को बिगाड़ दिया है और इसकी राजनीतिक व्याख्या ने अंत में वोट बैंक की राजनीति तैयार कर दी है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न फैसले पारंपरिक भारत के प्रति धर्मनिरपेक्ष भारत के रुख को चुनौती देने में उतने ही प्रभावी रहे हैं, जितना स्वयं पारंपरिक भारत । संपूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य की स्रोत रही संस्कृत भाषा का मामला ही लीजिए। 'धर्मनिरपेक्ष' भारत ने उसे कोस-कोसकर एक तरह से भुला ही दिया था और देखिए कि न्यायपालिका ने प्राचीन भाषा के प्रति धर्मनिरपेक्ष भारत की आपत्तियों को किस प्रकार निपटाया है। 'धर्मनिरपेक्ष' भारत ने संस्कृत को एक प्रकार से मृत भाषा ही करार दे दिया था और इसे हिंदू धर्म से भी जोड़ दिया था तथा इसे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक संपत्ति के बजाय धार्मिक भाषा बनाकर पेश किया था। इसने तो आंखें मूंदकर यहां तक कहा था कि संस्कृत को बढ़ावा देने का अर्थ हिंदू धर्म को बढ़ावा देना होगा और बहुसंख्यकों के अतिक्रमण के रूप में यह धर्मनिरपेक्षकता का उल्लंघन होगा। इसके उलट उर्दू के प्रोत्साहन को धर्मनिरपेक्ष भारत ने अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के संवैधानिक कर्तव्यों का हिस्सा बताया। किंतु न्यायपालिका ने अलग रुख अपनाया और संस्कृत को समुचित स्थान दिया । उच्चतर न्यायपालिका द्वारा धरती की व्याख्या और हिंदू पद्धति अथवा हिंदुत्व को भारत का सदियों पुराने सामाजिक-सांस्कृतिक अवलंब बताना न्यायिक व्याख्या भर नहीं था। वास्तव में यह उन सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक तथा राजनीतिक नियमों को स्वीकार करना है, जिन्होंने भारत की जनता और भूमि को उनकी विशिष्ट पहचान प्रदान की है।

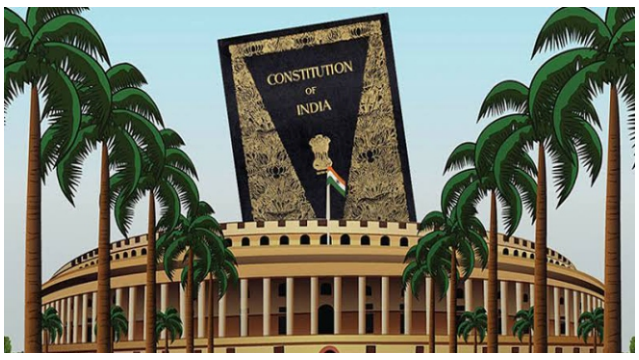

विकृत धर्मनिरपेक्षता के रखवालों द्वारा भारत के परिवेश के हिंदू अवलंब को नकारे जाने के वर्तमान चलन के बाद भी स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अवलंबों को बहुत महत्व दिया है और स्वतंत्र भारत द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं के ढांचे में इसे सूक्ष्म रूप से लेकिन आग्रह के साथ समाहित कर दिया गया है। हमारा संविधान, हमारी संसद, हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण अंग स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र भारत का भाग्य गढ़ने के लिए प्रेरणा का अंतिम स्रोत हजारों वर्ष पुराने हिंदू आदर्श तथा सभ्यतागत संबंध ही होंगे। भारत की राजनीतिक प्रणाली के संस्थापकों के मन में इस बात को लेकर लेशमात्र भी संदेह नहीं था कि भारत बहुलवादी और लोकतांत्रिक राज्य तभी रह पाएगा, जब यह लोकतांत्रिक और बहुलवादी हिंदुत्व के बुनियादी मूल्यों से जुड़ा रहेगा।

संभवतः यही कारण था कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान के पाठ में शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह बात बिना हिचक स्वीकार कर ली गई थी कि हिंदू बहुसंख्यक भारत देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ राज्य का संबंध स्थापित करने में धर्मनिरपेक्ष और निष्पक्ष रहेगा। लेकिन 1976 में आपातकाल के दौरान उन लोगों के दबाव के कारण 42वें संशोधन के जरिये धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में शामिल कर दिया गया, जो लोग भारतीय सभ्यता के मूलभूत मूल्यों में विश्वास नहीं करते थे। 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' शब्दों के स्थान पर 'संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' शब्द डाल दिए गए।

भारतीय संविधान के जनक भारत की हिंदू धरोहर से परिचित मालूम देते थे। संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए गए संविधान की पहली प्रति में सर्वाधिक चित्र दिए गए हैं। संविधान के मुख्य पाठ में कुल 21 रेखाचित्र हैं। इन चित्र संविधान के प्रत्येक भाग के आरंभ में दिए गए हैं, जिनसे बहुत दिलचस्प जानकारी मिलती है। ये चित्र भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का प्रतिनधित्व करने के लिए चुने गए हैं।

साभार : RNP Singh Senior Fellow, vif

बोया बीज बबूल का अंबुआ कहां से होय...

ये नई पीढ़ी चल पड़ी है मौत की राह पर

असंस्कारहीन पीढ़ी समाज के लिए बन गई ख़तरा

इंसान जो बोयेगा वही काटेगा....ये कहावत तो आप-हम ने कई बार सुनी होगी। बोये बीज़ बबूल के अंबुआ कहां से होय.....आज के संदर्भ में इसकी सार्थकता सहज ही समझ आ जाती है। समाज की दशा और दिशा में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। कॉफी हाउस में कुछ मित्रों के साथ चर्चा करते समय एक अदृष्य भय मस्तिष्क में पसर जाता है जब अपने आस-पास की सड़ती-गलती ज़िंदगियों को उनके भयावक रुप के साथ मित्र व्याख्यान करते हैं। लगता तो ये था कि इस बहस को बंद किया जाए और कुछ ऐसी बातों पर चर्चा की जाए जिनसे मन को शांति और प्रसन्नता प्राप्त हो सके। लेकिन हम कब तक यों ही इस कोढ़ से अछूते रह सकते हैं ? आख़िर हम इसी तथाकथित सभ्य समाज का अंग है।

नई पीढ़ी की एक बड़ी आबादी बड़े ही समर्पित भाव से स्वयं को खोखला करने के साथ-साथ हमारे समाज को भी लाइलाज बीमारी से ग्रसित कर रही है। यहां बात मात्र नशे के विभिन्न प्रकारों के उपयोग की नहीं हो रही अपितु संस्कारों की भी है जिसे ये नई पीढ़ी भस्म कर चुकी है। हम स्वयं और इस समाज को किस दिशा में अग्रसर कर रहे हैं, यहां ये एक बड़ा प्रश्न है। एक तो इस नादान उम्र में लड़खड़ाते क़दमों की आहट शिथिल और बेबस समाज की तस्वीर को उकेरता है वहीं भाषा और संस्कारों की तो पूछना ही बेकार है। छोटे-बड़े नशों के बाद अब चिट्टा जैसा नशा इस पीढ़ी को अपने आगोश में ले चुका है। कुछ परामर्शदाताओं से जब बात हो रही थी तो हमने जानना चाहा कि ये चिट्टा क्या है और किस प्रकार का नशा है ? उन्होंने जो थोड़ा-बहुत बखान किया उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कॉलेज और पढ़ाई के नाम पर युवा आज जंगलों की खाक छानते नज़र आते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यदि आप शिमला में ही टहलने के लिए कोई आरामदायक रास्ता चुनते हों तो वहां भी हर मोड़ पर शीशा बंद गाड़ियों में युवा धुऐं के छल्ले उड़ाऐ जाते हुए मिल जाऐंगे। रास्तों में खूबसूरत जंगलों में पार्टियों की धमाचौकड़ी और अश्लीलता का नंगा नाच असहनीय और अदर्शीनय है।

परिवार की भूमिका अहम्

बच्चों में नैतिक मुल्यों और शिक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेवारी घर-परिवार से शुरु होती है जिसमें मां-बाप एक अहम् किरदार निभाते हैं। बच्चों के परवरिश से ही यह तय होगा कि वो किस प्रकार का चरित्र और मुल्यों को लेकर आगे बढ़ेगा। आज युवाओं में नैतिक मुल्यों के ह्रास के पीछे एक बड़ा कारण हमारे घर से ही मुल्याधारित शिक्षा और लालन-पालन का अभाव भी है। घर का परिवेश जैसा होगा उसका प्रभाम निश्चित रुप से बच्चों पर भी पड़ता है। आज ही तीसरा घर कलह और अशांति का शिकार होता जा रहा है। माता-पिता के रिश्तों में खट्टास कहीं न कहीं लड़ाई-झगड़ों में तबदील होता जाता है और बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

एक किस्सा यहां साझा करते हुए याद आता है जब शहर की एक जंगल से होती सड़क पर अक्सर टहलते समय एक युवा को देखता रहता था। उस युवा ने घने जंगल में एक तीखे से मोड़ पर बैठ कर कुछ सूंघने अथवा कभी कुछ हथेली पर मलते हुए घंटो उसी स्थान पर बैठे रहना। एक दिन मैं भी वहीं बैठा और इसका कारण उससे जानने का प्रयास किया। उसने प्रति उत्तर न करते हुए वहां से जाना ही उचित समझा। एक सप्ताह बाद वही युवा एक भीड़ वाले बाज़ार में मिला तो उसने मुझे पहचान लिया। मैंने हाथ बढ़ाकर हैलो कहा तो हल्की सी मुस्कान के साथ उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा कि हम दोनों एक ही राह के साथी हैं जहां हम रोज़ टहलने निकलते हैं। इस नाते आप दोस्त ही हुए। एक कप चाय तो बनती ही है। उसने तुरंत कहा कि मुझे आपके साथ बैठना ही था। एक चाय की दुकान पर बैठकर और यहां-वहां की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि उस कमसिन उम्र में इस प्रकार स्वयं से दुश्मनी करने पर उतारु हो गए। उस युवा ने बताया कि घर जाने का मन नहीं करता है और कॉलेज में भी कभी-कभार ही जाता हूं। दोस्तों के साथ इसी सुनसान सड़क पर आना शुरु किया और फिर कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे बदल दिया। बहुत मज़ा आता था। कभी सिगरेट में भर कर तो कभी हम इसे एक कागज़ पर सूंघ कर लेते थे। इसी के चक्कर में मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी वो भी ख़त्म हो जाती तो मुश्किल हो जाती थी। अब दोस्त भी कम ही रह गए हैं और नशे की आदत ऐसी हो गई है कि मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूं। उस युवक से ही पता चला कि कॉलेज जा रहे युवाओं की आज वास्तव में क्या स्थिति है ? उसे परामर्श हेतु बहुत सी बातें हुई और बाद में उससे मिलना होता रहा। लेकिन यहां प्रश्न यह नहीं कि उस एक युवक का परामर्श हो गया बल्कि ऐसे हज़ारों युवाओं का भविष्य और जीवन दांव पर लगा हुआ है जो इस चिट्टे और अन्य बेहद ख़तरनाक नशीले पदार्थों की चपेट में ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं या कर रहे हैं।

परिवार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है जब कि इसी कर्तव्य को परिवार के मुखिया या बड़े समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों की संगत किस के साथ है, दिनभर की गतिविधियों की जानकारी आदि पर अभिभवाकों को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

सरकार के प्रयास नाकाफी

नशे की रोकथाम के लिए सरकार नित नये फार्मूलों पर नशे के ख़िलाफ अभियान चलाकर इसकी रोकथाम के लिए प्रयास करने का दावा करती है। क्या ये प्रयास इस बीमारी के लिए सार्थक है ? शायद नहीं, क्योंकि समाज में इसकी पकड़ और भी मज़बूत होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश की पहचान अब उड़ते हुए हिमाचल के रुप होने लग पड़ी है। ऐसा कोई दिन नहीं जब नशे की खेप के साथ गिरफ्तारी की ख़बरों से अख़बार न भरा हो। सरकार कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि हमारे प्रयास सार्थक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सरकार कई बार तो ऐसे कार्यक्रम लेकर आती है जिस पर विश्वास ही नहीं हो पाता है कि इससे नशे के प्रति जागरुकता का अहम् रोल है। सरकार मुख्य हैडक्वाटर पर दूध और जूस पिला कर लोगों को नशा छुड़ाने के जब दावे करती हैं तो हैरानी होना लाज़मी है। एक घंटे में सारा दूध बिक जाता है, लोग पी कर चले जाते हैं, अब क्या उसके बाद क्या समाज पर इसका कोई असर पड़ा ? शायद फाईलों में तो पड़ा ही होगा क्योंकि इसका एक बड़ा बजट होता है जिसे खर्च करना आवश्यक होता है। वहां तो खर्चा भी हो गया और कार्यक्रम सफल भी। इसके अलावा गाहे-बगाहे नशा रोकने के लिए दौड़ें, स्कूलों में छोटे-मोटे कार्यक्रम....इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये तो सरकार बेहतर जानती होगी लेकिन नशे के प्रति यह गंभीरता नाक़ाफी है। सरकार को इसके लिए स्थानीय संस्थाओं का सहयोग लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसे कार्यक्रम न बनाकर, एक नियमित प्रक्रिया का भाग बनाकर देखने की आवश्यकता है। सरकार की प्रत्येक गतिविधि का नशा

जागरुकता और रोकथाम के दावे खोखले...

रोकथाम एक मुख्य पहलु हो तथा स्थानीय संस्थाओं और परामर्शदाताओं को साथ लेकर इसके लिए गंभीर होना होगा। कानून की सख़्ती यहां एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि बाहर से आने वाली नशे की खेप ही प्रदेश का माहौल ख़राब करने के लिए अधिक जिम्मेवार है। सरकार ग्रामीण स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को एकत्रित कर सकती है। इसके अलावा गांव-गांव में बने युवा मंडलों से संपर्क कर उन्हें जागरुक करें तथा नशे में लिप्त युवाओं की पहचान करने में यह सबसे कारगर क़दम होगा। इन युवा मंडलों में सरकार कुछ वित्तिय सहायता प्रदान करके इनके लिए कार्य योजना बनाए तथा

वर्ष भर में की जाने वाली गतिविधियों को करवाने के लिए प्रयास करें। इससे युवा न केवल स्वरोजगार के लिए प्रेरित होगा बल्कि समाज सेवा के जज़्बे को लेकर सही दिशा में अपना समय व्यतीत कर सकता है। वर्तमान में ऐसे सैंकड़ों युवा मंडल हैं जो संगठन बना कर बैठे हैं और सही दिशा व प्रोत्साहन न होने के कारण उनकी बैठकें नशा करने के लिए ही होती है। गांव में ऐसे अनेक युवाओं से बात के दौरान ये बातें साफ हुई है। मेरा अधिकतर समय इन्हीं युवा मंडलों के साथ सेवाऐं देते व्यतीत हुआ है। युवा मंडल बनाने के बाद गांव के युवा एक चौपाल पर एकत्रित होकर भांग मलते हैं तथा उसके बाद नशा करते हैं। आज जबकि युवा इस देश का भाग्य निर्माता है और विकास की मुख्यधारा का सूत्रधार भी, तो ऐसे समय में उसे सही दिशा में ले जाने का उत्तरदायित्व कहीं न कहीं सरकार का है। सरकार यथासंभव सहयोग नहीं कर पा रही है। यह युवा अभी भी असंगठित है तथा सरकार इसे सामाजिक सरोकार से नहीं जोड़ पाई है। युवा मंडल गांव-समाज का नक्शा बदल सकते हैं। यदि यह युवा नशे के दलदल में धंसता गया तो सामाजिक विकास की नींव ही खोखली हो जाऐगी। यही युवा जब बाहरी ग़लत लोगों के झांसे में आते हैं तो स्थानीय युवाओं को साथ लेकर इनकी ऐसी एक कड़ी बनती जाती है। दुखद तो ये है कि स्कूलों में किशोरों को ये लोग अपना निशाना बनाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे कितने ही मामले हैं तो रोज सुर्खियां बनते हैं और उस पर जागरुकता का कोई ठोस उपाय नहीं किया जाता है। स्कूलों के पास दुकानों में सहजता से चोरी-छुपे नशे की चीजें मिल जाती है। ये बच्चे धीरे-धीरे बीड़ी-सिगरेट से शुरु करते हैं और फिर भंगी बीड़ी और उसके बाद ये अनंत मौत का सफर चल पड़ता है। मैं कितने ही ऐसे भटके हुए स्कूली बच्चों से मुख़ातिब हुआ जिन्होंने मुझे बताया कि नशे का काला अजगर कैसे बच्चों को भी निगल रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीण परिवेश में तो स्कूल के साथ लगती दुकानों में अवैध रुप से नशे का व्यापार होता है और बच्चों को सुगमता से ही नशीली वस्तुओं की उपलब्धता हो जाती है। पुलिस को इसकी लगभग पूरी जानकारी होती है लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई सहयोग न मिल पाने के कारण उपयुक्त कार्यवाही नहीं हो पाती है। दुकानों में सरेआम आज भी प्रतिबन्धित वस्तुओं का बिकना आम बात है लेकिन इस पर कार्यवाही न के बराबर है। गुटखा आदि सब कुछ अवैध तरीके से बेचे जाते हैं। इसके लिए लोग 5 रुपये की चीज़ के 20 रुपये देने को भी तैयार है। कानून बनाना कठिन नहीं है अपितु उसे लागु करना मुश्किल है। सरकार की इसमें भूमिका बढ़ जाती है। लेकिन नशे के ख़िलाफ जो अवाज़ शहर से गांव के कस्बों और गलियों तक सरकार ने पहुंचानी होती है उसके लिए शहर के रिज मैदान पर कार्यक्रम होता है और चाय-पानी, फूल मालाओं के बीच ही ख़त्म भी हो जाता है। गांव की बात गांव में जब तक नहीं होगी, लाभार्थियों के साथ नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार के सुधार की उम्मीद करना बेमानी होगी।

नशे के ख़िलाफ हो चरणबद्ध प्रक्रिया

आज युवाओं के हाल देखकर लगता है कि भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इन युवाओं को संस्कारहीन और पथ भ्रष्ट करने में नशे ने बड़ी भूमिका निभाई है। इन युवाओं के अभिभावक अब स्वयं ही परेशानी में है क्योंकि उनके युवा बच्चे जिस दिशा में हैं वहां से वापिस आना बेहद कठिन हो जाता है। यहां तक कि अभिभावक अब इतने लाचार है कि चिट्टे से मुक्ति के लिए स्वयं शराब का लालच देकर इससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह शोचनीय विषय है कि हमें ऐसे क़दम उठाने होंगे जिससे चरणबद्ध तरीके से इसका स्थाई उपचार संभव हो सके। जैसे सरकार अपने उन संपर्कों को आम युवाओं और लोगों तक पंहुचाऐं जिसमें नशामुक्त अभियान से जुड़ने की अपील की जा रही है। ताकि इसके लिए संपूर्ण जानकारी उसे सरलता से प्राप्त हो। सरकार की हरेक संबन्धित जानकारी युवाओं तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे। युवाओं को नशे के छुटकारे और इसके अवगुणों के प्रति जागरुकता के अलावा इसमें लिप्त युवाओं को सही प्रकार से उपचार की आवश्यकता रहती है।

नशे में डूबे देश में आंकड़ों की भी भयावक कहानी है। देश की 70 से 75 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार का नशा करती है जिसमें शराब, तंबाकु, बीड़ी-सिगरेट आदि शामिल है। हर तीन में से एक युवा इस लत का शिकार है। एक सर्वे के अनुसार प्रतिदिन 5500 युवा किसी न किसी प्रकार के तुबाकु सेवन से जुड़ रहे हैं। सिगरेट पीने में भारत की लड़कियां एवं औरतें अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में 12 करोड़ से अधिक लोग धुम्रपान करते हैं जिसमें 20 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। सबसे गंभीर विषय यही है कि नशा करने वाले युवाओं में महिलाओं/युवतियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 50 लाख से अधिक युवा हेरोइन जैसे ख़तरनाक नशे के आदी हो चुके हैं। यही हाल नशीली दवाईयों के मामले में भी है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नशीली दवाईयों का सेवन ही नहीं करते बल्कि इसके आदी हो चुके हैं। पंजाब में यह स्थिति और भी ख़राब हो चुकी है और अब हिमाचल की बारी है। यही स्थिति भांग के मामले में भी है। देश में रोज भांग का सेवन करने वालों की तादात करोड़ों में है। देश आज नशे की चपेट में चुका है विशेषकर पंजाब जैसे राज्य जिसकी सीमाऐं पाकिस्तान के साथ लगती है और वहां से नशे की खेप की तस्करी की जा रही है। पंजाब के साथ लगते राज्यों में हिमाचल भी शामिल है। लाज़मी है इसका प्रभाव यहां भी पड़ेगा। बंगलादेश, म्यांमार आदि से भी भारत में नशे की तस्करी की जा रही है जिस पर प्रतिबंध लगना एक चुनौती से कम नहीं है।

ये आंकड़े सिर्फ सरकारी है और वो भी पुराने हैं। हालात बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच चुके हैं। सरकार सिर्फ राजस्व को बढ़ाने के लिए इसे समझौता करने के लिए तैयार है। और इस पर कोई भी सख़्त क़दम नहीं उठा रहे हैं। सरकार के हाल तो यहीं से समझे जा सकते है कि गांव-गांव में शराब के ठेक खोले जा रहे हैं। इतना ही नहीं मंदिर और आश्रमों के गेट पर ही कई जगह शराब के ठेके खोल दिये गए। ऐसा ही एक मामला कच्ची घाटी के राधाकृष्ण सदन के गेट पर ही शराब का ठेका खोल दिया गया था। इस पर जब विरोध किया गया तो सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इतना ही नहीं पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि यह शराब का ठेका सरकार ने वहां से नहीं उठाया तो वो स्वयं आश्रमवासियों के साथ धरने पर बैठेंगे। लेकिन तत्कालीन अधिकारी ने इसे सिरे से ख़ारिज़ करते हुए कहा कि यह मामल राजस्व से जुड़ा है। अंततः वहां से शराब का ठेका नहीं उठाया गया। ऐसी मनोवृति यदि सरकार की ही होगी तो नशे की रोकथाम नहीं इसे बढ़ावा ही मिलेगा। सरकार को राजस्व को बढ़ाने के लिए विकल्प के रुप में अन्य उपायों पर विचार करते हुए नशे के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस अपनानी होगी। ऐसा न हो कि राजस्व के फेर में प्रदेश को ये नशे का दीमक अंदर से इतना खोखला कर दे कि भावी पीढ़ी सहारे के लिए कांधा ढूंढते रहे। इतना ही नहीं, देश और प्रदेश में वीभत्स एवं जघन्य अपराधों के पीछे इसी नशे का हाथ रहा है। एक बड़ा नुकसान सामाजिक चारित्रिक पतन को लेकर है क्योंकि नशे में धुत युवा सार्वजनिक स्थलों, बसों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों एवं अन्य स्थलों पर जिस चरित्र का प्रदर्शन करते हैं वो बेहद शर्मनाक है। हमें ज़िंदगी को जीना है, नशे को नहीं। इस बात को प्रत्येक नागरिक को गांठ बांध कर सुनने, समझने की आवश्यकता है। जीवन का राग गाया तो गुनगुनाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये जो बांस है ये खोखला है और उससे बांसुरी तो नहीं बन सकती है .....

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगे योग-शतरंज और भारद्वाज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अब संस्कृत शुरू की जाएगी। यह विषय दूसरी कक्षा से पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए मानसिक और शारीरिक विकास को सरकार जल्द स्कूली पाठ्यक्रम में योग और शतरंज को शामिल करेगी।

बीते दिनों कायाकल्प संस्थान पालमपुर में स्वामी विवेकानंद पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का मुख्य लक्ष्य आत्मा की स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। यह एक व्यक्ति के धर्म की संपूर्णता को समाहित करता है। शिकागो में स्वामी ने विश्व को दिखाया कि भारत केवल सपेरों का देश न होकर महान विचारकों एवं महापुरुषों का निवास स्थान भी है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारत की एकता के मूल सिद्धांत से अवगत करवाया। विश्व समुदाय को यह बताया कि इतनी भिन्नताओं के बावजूद राष्ट्र कैसे मानवता और भाईचारे के सूत्र से बंधा है। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के परामर्श पर उन्होंने उनकी शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार को पूरे भारत की यात्रा की। भाषण प्रतियोगिता की विजेता पारुल शर्मा और नंदनी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं के बारे में भी बताया।

हिमाचल में मार्च तक हवाई सेवाएं देगी पवन हंस कंपनी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल सरकार ने हवाई सेवाएं दे रही कंपनी पवन हंस का करार मार्च तक बढ़ा दिया है। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह कंपनी पुराने रेट पर ही हवाई सेवाएं देगी।

एक महीने में 40 घंटे सेवाएं देने पर सरकार इस कंपनी को करीब तीन करोड़ तीन लाख रुपये तक भुगतान करेगी। कंपनी मुख्यमंत्री के अलावा जनजातीय क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान लोगों को हवाई सेवाएं मुहैया करवाती है। पवन हंस कंपनी पांच साल से हिमाचल में हवाई सेवाएं उपलब्ध करा रही है। करार खत्म होने पर बीच - बीच में इस कंपनी का एक्सटेंशन भी दी गई है। पवन हंस कंपनी का हेलीकाप्टर बार-बार खराब होने के कारण सरकार ने कंपनी को एक्सटेंशन देने की बजाय टेंडर आमंत्रित किए। इसमें स्काई वन कंपनी को टेंडर दिया है। नई कंपनी ने जनवरी से हवाई सेवाएं देनी थीं, लेकिन स्काई वन कंपनी को हेलीकाप्टर बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में कंपनी से सरकार से समय मांगा था। सचिवालय सामान्य प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे 17 सीटर चॉपर में डबल इंजन के साथ दो पायलट होंगे। सरकारी स्तर पर औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

हिमाचल में महंगा हुआ सीमेंट, लोगों में रोष

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद नए साल में सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाकर हिमाचल के लोगों को झटका दिया है। सीमेंट के दामों में 5 और 10 रुपये प्रति बैग बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रदेश में तीनों बड़ी सीमेंट कंपनियां एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के एक साथ दाम बढ़ाने से उपभोक्ताओं में रोष है। बता दें कि इन तीनों सीमेंट कंपनियों के हिमाचल में प्लांट भी हैं।

यहीं सीमेंट बनने के बावजूद सूबे के लोगों को पड़ोसी राज्यों से महंगा सीमेंट मिल रहा है। एसीसी कंपनी ने पहले 5 जनवरी को 5 रुपये, फिर 9 जनवरी को 5 रुपये दाम और बढ़ा दिए। वर्ष 2019 में एसीसी सीमेंट बैग की कीमत 374 थी। वर्ष 2020 के दूसरे सप्ताह 384 रुपये कीमत हो गई है। अंबुजा सीमेंट कंपनी के दामों में भी 10 रुपये का उछाल आया है। एक बैग की कीमत 390 रुपये हो गई है। कंपनी ने 4 जनवरी को दाम 10 रुपये बढ़ा दिए। मार्केट के जानकारों के अनुसार अंबुजा सीमेंट के दामों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है।

अल्ट्राटेक कंपनी ने भी सीमेंट के दाम 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब सीमेंट बैग की कीमत 379 रुपये हो गई है। एरिया मैनेजर एसीसी अमित गौतम, अंबुजा के डीलर रमेश कुमार और अल्ट्राटेक के डीलर देव राज का कहना है कि सीमेंट की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेश में भारी बारिश-बर्फबारी से 1100 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में हुई भारी बारिश और बर्फबारी से 1100 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन स्कीमों को नुकसान पहुंचने से आईपीएच विभाग को करीब 34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ. आरएन बत्ता ने कहा कि सरकार ने विभाग को क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को तीन दिन के भीतर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, भारी बारिश और बर्फबारी से अभी तक प्रदेश में सड़कों को सौ करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी से अधिकांश जिलों में छोटी-बड़ी पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। अभी तक करीब 1100 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से अधिकांश बस्तियों में लोगों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ता है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के भीतर सभी पेयजल योजनाएं बहाल की जाएं। दूसरी ओर, प्रदेश के विभिन्न भागों में सड़कों को सौ करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग बंद पड़ीं सड़कों को खोलने में जुटा है। आईपीएच विभाग के सचिव डॉ. आरएन बत्ता ने कहा कि प्रदेश में 1100 पेयजल योजनाएं भारी बारिश और बर्फबारी से क्षतिग्रस्त हुई हैं। अभी तक 34 करोड़ का नुकसान पेयजल योजनाओं को हुआ है। इन्हें तीन दिन के भीतर बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति पर्व को जिला स्तरीय दर्जा देने की घोषणा की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में आयोजित ब्राह्मण कल्याण परिषद के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने ब्रजेश्वरी धाम में मकर संक्रांति पर्व को जिला स्तरीय दर्जा देने की घोषणा की है।

उन्होंने जिला प्रशासन को परशुराम भवन निर्माण के लिए लीज डीड की औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए दिए निर्देश भी दिए। उन्होंने ब्राह्मण कल्याण परिषद को भवन निर्माण के लिए 21 लाख का अंशदान देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर जय राम ठाकुर ने कहा कि संस्कृति तथा परंपराओं के संरक्षण में सामाजिक संस्थाओं की अहम भूमिका रही है, समाजिक संस्थाएं विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से आम जनमानस की भलाई के कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनमानस को अनुशासित व एकता के सूत्र में बांधने के लिए सामाजिक समरसता तथा समभाव जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में बसे ब्राह्मण समाज के प्रति आदर व सम्मान का दृष्टिकोण रहा है। यहां के मंदिर व देव स्थान इस सत्य के उदाहरण हैं। हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा है। लोक संस्कृति की परंपरा को निरंतर बनाए रखने में ब्राह्मण समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019(सीएए) पारित किया है।

कीरतपुर-नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लेनिंग के लिए 1455.73 करोड़ के टेंडर करने को केंद्र की मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार ने कीरतपुर से नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लेनिंग के शेष कार्य के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय भूतल, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के पास इस मामले को उठाया था और यह निर्णय उसी का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर सुदंरनगर बाईपास को छोड़कर एनएच 21 ग्रीन फील्ड एलाईनमेंट के कीरतपुर से नेरचौक की चार लेन के शेष कार्य के लिए 1455.73 करोड़ रुपये के टेंडर को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाईब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर इस सड़क के शेष काम के लिए टेंडर दिया है और जो कम्पनी इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करेगी, वह 15 सालों तक इसकी देखरेख भी करेगी। उन्होंने कहा कि 29 किलोमीटर का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के विकास रखरखाव और प्रबंधन का जिम्मा एनएचएआई को सौंपा था। प्राधिकरण ने कीरतपुर से नेरचौक के फोर लेन के लिए बनावट, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर कार्य करने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए एक निजी संस्था के चयन के लिए बोली प्रक्रिया कराने का फैसला लिया है, जिसके माध्यम से इस परियोजना का कार्य दिया जाएगा।

मुश्किल में जैदी, जमानत निरस्त करने की अपील करेगी सीबीआई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी व बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म तथा हत्याकांड से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड के आरोपी आईजी जहूर हैदर जैदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

शिमला की पूर्व एसपी सौम्या सांबशिवन के चंडीगढ़ स्थित सीबीआई अदालत में जैदी की ओर से फोन कर बयान बदलने का दबाव बनाने और मानसिक प्रताड़ित करने का बयान देने के बाद अब सीबीआई उनकी जमानत को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सीबीआई की चुनौती की वजह से ही जैदी लंबे समय तक जेल में रहे और कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। चूंकि, किसी भी जमानत के दौरान गवाहों को प्रभावित न करने की चिंता हर जांच एजेंसी की रहती है। इस मामले में गवाह सौम्या ने जैदी के खिलाफ कोर्ट में ही गवाही दे दी है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सीबीआई अगली सुनवाई में जैदी की जमानत खारिज करने को लेकर कोर्ट में आवेदन कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सीबीआई के आला अधिकारी विधि अधिकारियों के साथ इस बात को लेकर मंथन में जुटे हैं।

चूंकि, अभी कोर्ट के आदेश आधिकारिक रूप से सीबीआई या हिमाचल सरकार के पास नहीं पहुंचे हैं, ऐसे में वह समय ले रही है। उधर, प्रदेश सरकार भी कोर्ट के आदेश व सौम्या के बयान की प्रति मिलने का इंतजार कर रही है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि मामले में मुख्यमंत्री ने पहले ही सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए हैं।

ऐसे में सिर्फ कोर्ट से आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद प्रदेश सरकार उनके निलंबन को लेकर भी फिर से विचार कर सकती है।

हिमाचल समेत देशभर में इन 47 दवाओं के सैंपल फेल, कहीं आपने भी तो नहीं किया सेवन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के उद्योगों में बन रहीं दवाएं लगातार मानकों पर खरा नहीं उतर रही हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन (सीडीएससीओ) के दिसंबर के ड्रग अलर्ट में देशभर के फेल 47 दवा सैंपलों में हिमाचल की 14 दवाएं शामिल हैं।

इनमें बीबीएन की छह और सिरमौर की चार, कांगड़ा की तीन और ऊना में बनी एक दवा शामिल है। सीडीएससीओ ने नवंबर में देशभर से 1336 दवाओं के सैंपल एकत्रित किए थे। फेल दवा सैंपलों में थियोन फार्मास्यूटिकल सैणीमाजरा नालागढ़ की एमोक्सीसिलिन पोटाशियम कलवुनेट, सनवेट हेल्थकेयर गांव शंभुवाला नाहन पांवटा रोड की डैबिगारटन इटेक्सजाइलेट मेसीलेट कैप्सूल, एचएल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया फेस-2 गगरेट की एजीथ्रोमाइसिन टैबलेट, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बद्दी की इंडेपामाइड एसआर टैबलेट, अमेसटेर लैब्स सराजमाजरा गुज्जरां बद्दी की 3जी मैक्स सॉफ्टजेल कैप्सूल, सेल्स फार्मास्यूटिकल हररायपुर बद्दी की फैक्सोफेनडाइन हाइड्रोक्लोराइड शामिल हैं। ग्रैमपस लैबोरेट्रीज जोहरों इंडस्ट्रियल एरिया कालाअंब सिरमौर की न्यूमाइसिन सल्फेट पॉलीमिक्सिन-बी सल्फेट एंड बेसिट्रसिन जिंक पाउडर, मोनटेक बायोफार्मा हिमुडा इंडस्ट्रियल एरिया भटौलीकलां बद्दी की लैक्टूलोज ओरल सॉल्यूशन, टैरेस फार्मास्यूटिकल फेस-3 इंडस्ट्रियल एरिया संसारपुर टैरेस कांगड़ा की आईसोसोब्राइड मोनोनाइट्रेट टैबलेट, सिवरॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल एरिया फेस-3 संसारपुर टैरेस कांगड़ा की नाइट्रोग्लिसरिन कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट 2.6 और नाइट्रोमेड सीआर-6.4, निकविन हेल्थकेयर काठा बद्दी की सैफूरोक्सिम एक्सेटिल टैबलेट, डिजिटल विजिन कालाअंब सिरमौर की रेबेप्राजोल सोडियम टैबलेट, जी लैबोरेट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया पांवटा साहिब की मोनटूलेकास्ट सोडियम व लीवसिटरेजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट शामिल है।

सैंपल इंदौर, असम, त्रिपुरा, बद्दी, ड्रग्स कंट्रोल आफिस हिमाचल, गाजियाबाद से लिए गए हैं। इनकी जांच सीडीटीएल मुंबई, आरडीटीएल गुवाहाटी, चंडीगढ़, कोलकाता में की गई है। सहायक राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि सैंपल फेल होने वाले उद्योगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। फेल सैंपलों के बैच मार्केट से हटाने के निर्देश जारी किए हैं।

महिला टी-20 विश्व कप: टीम में हिमाचल से खेलने वाली हरलीन देओल शामिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

महिला विश्व कप क्रिकेट के लिए टीम इंडिया में हिमाचल से खेलने वाली ऑलराउंडर हरलीन देओल को भी शामिल किया गया है। प्रतियोगिता आस्ट्रेलिया में 21 फरवरी से खेली जाएगी।

बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप-2020 के लिए टीम इंडिया के 16 नामों की घोषणा कर दी है। 16 सदस्यीय टीम में एचपीसीए की हरलीन देओल को जगह मिली है। वह अपना पहला विश्व कप टूर्नामेंट खेलेंगी। घरेलू स्तर पर हरलीन ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसी का इनाम हरलीन को मिला है। वर्ल्ड कप के अलावा आस्ट्रेलिया में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम की घोषणा कर दी है। हरलीन इस टीम में शामिल होने में भी कामयाब हुई हैं। विश्व कप से पहले त्रिकोणीय सीरीज आस्ट्रेलिया में 31 जनवरी से खेली जाएगी। इसमें तीसरी टीम इंग्लैंड होगी। हरलीन भारत के लिए पहले ही डेब्यू कर चुकी हैं। 22 फरवरी, 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन ने नीली जर्सी पहनी थी। वह पहली बारी विश्व कप जैसी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जनरल बिपिन रावत ने एयर डिफेंस कमान का खाका तैयार करने का दिया निर्देश

द रीव टाइम्स ब्यूरो
सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने देश की हवा में ताकत बढ़ाने और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एयर डिफेंस कमांड को बनाने को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। सीडीएस का मुख्य उद्देश्य तीनों सेवाओं हेतु समग्र रक्षा अधिग्रहण योजना तैयार करते हुए हथियारों एवं उपकरणों के स्वदेशीकरण को अधिकतम सीमा तक संभव बनाना है। वायु रक्षा कमान के गठन का उद्देश्य देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा अभेद्य बनाना है।

इंडियन नेवी ने अपने जवानों के फेसबुक इस्तेमाल पर लगाया बैन

द रीव टाइम्स ब्यूरो
भारतीय नौसेना के अनुसार, जहाजों और नौसैन्य अड्डों पर अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य मैसेंजर्स समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय नौसैनिकों द्वारा फेसबुक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य संवेदनशील और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना हैं। भारतीय नौसेना के अनुसार, यह फैसला सात नौसैनिकों द्वारा सोशल मीडिया पर दुश्मन की खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के बाद उठाया गया है। इसे देखते हुए ही सभी संवेदनशील जगहों पर सेना के स्मार्टफोन उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है।

भारतीय सेना की बढ़ी ताकत रूस से एक लाख एके-203 असॉल्ट राइफलें मिलेंगी

द रीव टाइम्स ब्यूरो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 03 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भारत-रूस के

आयुध कारखाने का उद्घाटन किया था। योजना के मुताबिक, पहले चरण में एक लाख राइफलें रूस से आयात की जाएंगी, जबकि शेष 6.5 लाख राइफलें भारत में निर्मित की जाएंगी। यह सीरीज की सबसे आधुनिक एवं भरोसेमंद राइफल मानी जाती है।

फोर्ब्स पत्रिका के 20 प्रभावशाली लोगों में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर शामिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो
फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के टॉप-20 शक्तिशाली लोगों में कन्हैया कुमार को 12वें स्थान पर तथा प्रशांत किशोर को 16वें स्थान पर रखा है। कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर के अतिरिक्त पांच भारतीयों को भी इस सूची में जगह मिला है।
फोर्ब्स ने कहा कि दोनों युवा नेता आगामी दशक में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। फोर्ब्स के इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और कॉमेडियन हसन मिन्हाज हैं। इस सूची पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को भी जगह मिली है। वे इस सूची में 15वें स्थान पर है।

अमिताभ बच्चन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित

द रीव टाइम्स ब्यूरो
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अमिताभ बच्चन को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 'दादा साहेब फाल्के पुरस्कार' से सम्मानित किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान हेतु दिया जाता है।

केंद्र सरकार ने पहला 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान' देने की घोषणा की

द रीव टाइम्स ब्यूरो
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया संस्थानों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत और विदेश में

योग के प्रचार-प्रसार में सकारात्मक भूमिका और जिम्मेदारी को मान्यता देने हेतु जून 2019 में पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की स्थापना की।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये पुरस्कार भारत और विदेश में योग के प्रचार-प्रसार में भूमिका और जिम्मेदारी हेतु मीडिया का सम्मान करने के लिए शुरू किये गये हैं।

अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र कर्नाटक के चल्लकेरे में स्थापित किया जाएगा- इसरो

द रीव टाइम्स ब्यूरो
इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र के विकास हेतु 2700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। योजना के अनुसार यह नया केंद्र अगले तीन साल में तैयार होगा। इस केंद्र से अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण से लेकर मानव मिशन से जुड़ी सभी गतिविधियां संचालित होंगी। इस केंद्र को तैयार हो जाने के बाद मानव मिशन से जुड़ी गतिविधियों हेतु कहीं और जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। गगनयान मिशन के तहत साल 2022 तक तीन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन के लिए चार अंतरिक्षयात्रियों का चयन किया जा चुका है।

1 फरवरी को पेश होगा 2020 -आम बजट

द रीव टाइम्स ब्यूरो
केंद्रीय बजट 2020-21 का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 02 मार्च से 03 अप्रैल तक चलेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट 01 फरवरी 2020 को पेश होगा। इस बजट सेशन की तैयारी जोरों से शुरू हो चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट के संबंध में लोगों से सुझाव मांगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी 2020 को अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। पहली बार साल 2017-18 का बजट 01 फरवरी को पेश किया गया था।

9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस

द रीव टाइम्स ब्यूरो
प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस साल 2003 में मनाया गया था। भारत सरकार इस मौके पर प्रत्येक साल अमूमन तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करती है।
इस दिवस का उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच और उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ ही उनकी अपने देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत हेतु एक मंच उपलब्ध कराना है।

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एससीओ के आठ अजूबों में शामिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो
यूरेशिया के आठ देशों के अंतरराष्ट्रीय संगठन शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को एससीओ के आठ अजूबो में शामिल किया है। एससीओ के आठ सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और

उज्बेकिस्तान शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और एससीओ के सदस्य राज्यों के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। गौरतलब है कि भारत ने एससीओ प्रमुखों की परिषद की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी ली है। विदेश मंत्री ने नोरोव से मुलाकात करने के बाद ट्वीट किया कि एससीओ के अन्य सदस्य देशों में पर्यटन के बढ़ावा के प्रयासों की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि एससीओ के आठ अजूबों में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का शामिल होना एक प्रेरणा के रूप में देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्तूबर 2018 को दुनिया के सबसे ऊंचे स्टेच्यू 'स्टेच्यू ऑफ इंडिया' का उद्घाटन किया था। अब यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुका है।

आरबीआई ने दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु 'मनी मोबाइल' ऐप लॉन्च किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने 01 जनवरी 2020 को 'मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर' (मनी) ऐप जारी किया।

दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आरबीआई ने उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मनी मोबाइल ऐप लांच किया है। यह ऐप नोट की पहचान के बाद आवाज के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी में नोट का मूल्य बताएगा। आरबीआई के तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारतीय बैंक नोट में कई विशेषता होती है। यह ऐप मोबाइल के कैमरे के जरिये नोटों को स्कैन करता है।

भारत ने बनाया रिकॉर्ड, नए साल के पहले दिन जन्म लिए 67385 बच्चे

द रीव टाइम्स ब्यूरो
हाल ही में यूनिसेफ की ओर से जारी की गई 190 देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है नए साल पर 2020 की पहली तारीख को

पूरी दुनिया में भारत का स्थान पहला है, जहां 67,385 बच्चे पैदा हुए। इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है जहां 46,299 बच्चों ने जन्म लिया। भारत के बाद चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इथियोपिया है। विश्वभर में पैदा होने वाले कुल बच्चों का 50 प्रतिशत इन्हीं आठ देशों में है। विश्वभर में 01 जनवरी 2020 को जन्में बच्चों मे अकेले भारत में 17 प्रतिशत बच्चों ने जन्म लिया है।

दिल्ली में 08 फरवरी को मतदान 11 फरवरी को जारी होंगे नतीजे

द रीव टाइम्स ब्यूरो
हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि दिल्ली में 13750 बूथों पर वोटिंग होगी और 2689 जगहों पर मतदान होगा। दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी को सिंगल फेज में मतदान होगा और मतगणना 11 फरवरी 2020 को होगी।
साल 2015 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें हासिल हुई थीं। आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़कर इतनी सीटें हासिल करने का इतिहास रचा था। भारतीय जनता पार्टी को केवल तीन सीटें प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी।

जीओ ने लॉन्च की वाई-फाई कॉलिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो
जीओ ने लॉन्च की वाई-फाई कॉलिंग सेवा लॉच कर दी है। ग्राहक इस सर्विस के जरिए वॉयस और वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। यह सर्विस किसी भी वाई-फाई पर और भारत में प्रत्येक जगह काम करेगी। रिलायंस जियो की वाई-फाई सेवा के नाम से जानी जायेगी। सभी जियो के ग्राहक इस सेवा के तहत वाई-फाई नेटवर्क की सहायता से 'फ्री' में कॉलिंग कर पाएंगे। यह सर्विस 150 से ज्यादा स्मार्टफोन को सपोर्ट करेंगे। इस सर्विस को 'जियो' काफी महीनों से टेस्ट कर रहा था।

जनरल सुलेमानी की हत्या से जागी सरकार, 31 जनवरी तक ड्रोन रजिस्ट्रेशन करवाएं नहीं तो मिलेगी सजा

द रीव टाइम्स ब्यूरो
भारत के उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन रखने वाले नागरिकों को 31 जनवरी तक पंजीकरण करवाने के लिए कहा है। साथ ही चेताया है कि इसके गैर पंजीकृत ड्रोन व उनके ऑपरेटरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी सेना द्वारा ड्रोन का उपयोग कर की गई हत्या के बाद यह सख्ती कर रही है। मंत्रालय के अनुसार बड़ी संख्या में ड्रोन और ड्रोन ऑपरेटर नागरिक उड़ान अनिवार्यताओं (सीएआर) का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक अवसर दिया जा रहा है कि वे अपना व अपने ड्रोन का स्वैच्छिक खुलासा 31 जनवरी तक ऑनलाइन पंजीकरण से करें।

जनरल मनोज नरवाने भारत के 28वें सेना प्रमुख

द रीव टाइम्स ब्यूरो
जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की नियुक्ति सेना प्रमुख के तौर पर ऐसे समय में हुई है, जब भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव शीर्ष पर है। सितंबर 2019 में सेना का उप-प्रमुख पद संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। सीडीएस का काम सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल लाना होगा। उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद संभाला था। इसके अतिरिक्त, उन्हें ऑपरेशन पराक्रम मेडल, विशेष सेवा पदक, सम्मान सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।

इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो
यह पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के थुटुकुडी में बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जायेगा। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि सरकार ने चंद्रयान-3 अभियान को भी मंजूरी दे दी है और इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। इसरो ने 2020 के लिए 25 मिशनों की योजना बनाई है। के. सिवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की।

सीसीआई ने 'भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन: महत्वपूर्ण निष्कर्ष' रिपोर्ट जारी की

द रीव टाइम्स ब्यूरो
सीसीआई ने 'भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन: महत्वपूर्ण निष्कर्ष' रिपोर्ट जारी की है। यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि ई-कॉमर्स भारत में सभी क्षेत्रों में महत्व प्राप्त कर रहा है। अध्ययन से पता चलता है कि ई-कॉमर्स ने देश में मूल्य पारदर्शिता और मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। विशेष रूप से अध्ययन में 'मोबाइल फोन' पर दी जाने वाली छूट का उल्लेख किया गया है। यह अध्ययन उपभोक्ता वस्तुओं मोबाइल, जीवनशैली, विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं किराने के सामान, आवास सेवाओं और खाद्य संबंधी सेवाओं की तीन व्यापक श्रेणियों को कवर करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य देश में ई-कॉमर्स के कामकाज के साथ-साथ बाजारों एवं प्रतिस्पर्धा हेतु भी इसके निहितार्थों को समझना था।

कैबिनेट मंजूरी 08 जनवरी 2020

द रीव टाइम्स ब्यूरो
खनिज कानून संशोधन अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 जारी करने की मंजूरी दे दी है यह अध्यादेश सभी क्षेत्रों के लिए कोयला खनन को खोलने तथा कोयला खदानों की नीलामी के नियम को आसान करेगा। अध्यादेश जारी होने के बाद 31 मार्च 2020 से पहले 46 लौह अयस्क तथा अन्य खानों की नीलामी की जा सकेगी। 46 खानों की खनन पट्टे की अवधि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है। नीलामी की अनुमति से उत्पादन कार्य जारी रखते हुए इनका आसानी से हस्तांतरण किया जा सकेगा।

कैबिनेट ने बीएमजीएफ के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है।

शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों हेतु भारत और मंगोलिया के बीच समझौते को मंजूरी

भारत और स्वीडन के बीच ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी

भारत और फ्रांस के बीच आवागमन और स्वतंत्र गतिशीलता साझेदारी समझौते को मंजूरी

गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर, जामनगर में आयुर्वेद संस्थानों के समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

ईरान का कबूलनामा – गलती से मार गिराया था यूक्रेनी विमान, रुहानी बोले – जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ईरान ने आखिरकार कबूल कर ही लिया कि उसकी सेना ने गलती से यूक्रेनी यात्री विमान बोइंग 737 को मार गिराया था। इस विमान में 176 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई थी। सेना ने बयान जारी कर इसे मानवीय भूल करार दिया। यह घटना ऐसे समय पर हुई थी जब ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला किया था। विमान ने तेहरान के इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यूक्रेन की राजधानी कीव के बोर्यस्पिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लिए उड़ान भरी थी। ईरानी अधिकारियों ने पहले दावा किया था कि इस दुर्घटना का कारण तकनीकी खामी थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता रजा जाफरजादेह ने बताया था कि यह विमान तेहरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में दुर्घटना का शिकार हुआ। जांचदल और बचाव कर्मी

दुर्घटनास्थल पर पहुंचें तब उन्हें कोई भी जिंदा नहीं मिला। सेना के बयान को लेकर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा, सशस्त्र बलों की आंतरिक जांच से निश्कर्ष निकला है कि मानवीय त्रुटि के कारण गलती से यूक्रेनी विमान को मिसाइल ने निशाना बनाया। जिसके कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 176 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी और अक्षम्य गलती की जांच जारी रहेगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास उसी दिन में जारी करेगा तत्काल पासपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुबई और उत्तरी अमीरात में रह रहे भारतीय अप्रवासियों को अब 'तत्काल' श्रेणी के तहत आवेदन करने पर उसी दिन पासपोर्ट मिल जाएगा।

दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत विपुल ने हाल में ही को इसका एलान किया। उन्होंने बताया कि दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने आपात मामलों में आवेदन के दिन ही तत्काल पासपोर्ट जारी करने की सुविधा शुरू की है। दूतावास में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में विपुल ने कहा कि तत्काल पासपोर्ट की सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अपना आवेदन अल खलीज सेंटर में स्थित बीएलएस इंटरनेशनल कार्यालय में दोपहर से पहले जमा कराएंगे। बीएलएस इंटरनेशनल भारतीय पासपोर्ट और वीजा आवेदकों के लिए सुविधा प्रदाता कंपनी है। हम पहले से ही 24 घंटे के अंदर तत्काल पासपोर्ट मुहैया करा रहे हैं। हम अब उससे एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। यदि दोपहर 12 बजे से पहले आवेदन किया जाता है तो हम उसी दिन शाम तक पासपोर्ट जारी कर देंगे।

भारतीय मिशन को रोजाना करीब 850 पासपोर्ट आवेदन मिलते हैं। पिछले साल वाणिज्य दूतावास ने 2,00,000 से अधिक पासपोर्ट जारी किए थे।

ब्रिटेन का ईयू से बाहर होने का रास्ता साफ सांसदों ने दी ब्रेग्जिट समझौते को मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमंस ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समझौते को मंजूरी दे दी। समझौते के पक्ष में 330 वोट पड़े जबकि विरोध में 231 वोट डाले गए। मालूम हो कि बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट मुद्दे पर ही प्रचंड बहुमत के साथ पिछले महीने में सत्ता में दोबारा वापसी की थी। ब्रेग्जिट पर सांसदों की मंजूरी के साथ सालों की देरी के बाद ब्रिटेन के 31 जनवरी को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हालांकि अभी ईयू-यूके विदड्रॉल एग्रीमेंट बिल को अनिर्वाचित हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यूरोपीय संसद द्वारा पारित किया जाना बाकी है, जिसे केवल औपचारिकता मात्र माना जा रहा है।

ब्रिटेन साल 1973 में 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना था। ब्रेग्जिट के साथ ब्रिटेन की करीब पांच दशक पुरानी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ऐसा करने वाला ब्रिटेन पहला देश होगा। हालांकि, ईयू के नियमों के तहत 31 दिसंबर तक वह कारोबार करेगा। इस साल ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। बोरिस जॉनसन की कंजरवेटिव पार्टी को 650 सीटों वाली संसद में 364 सीटें मिलीं। चुनाव परिणाम के साथ ही ब्रेग्जिट का रास्ता साफ हो गया था।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर लगाई पाक को लताड़

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ा है। अकबरुद्दीन ने कहा कि इस्लामाबाद नई दिल्ली पर गलत बयानबाजी करना बंद करें। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां कोई आपके झूठ को मानने वाला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली बहस के दौरान अकबरुद्दीन ने कहा कि यह तेजी से स्वीकार किया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद पहचान और वैधता के संकटों का सामना कर रही है। साथ ही प्रासंगिकता और प्रदर्शन का भी। उन्होंने कहा कि आतंकी नेटवर्कों का वैश्वीकरण, नई तकनीकों का शस्त्रीकरण, विध्वंसक राज्यक्राफ्ट को रोकने में असमर्थता परिषद की कमियों को दिखा रहा है। अकबरुद्दीन ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल जो हमेशा से अपनी काली करतूतों के लिए प्रसिद्ध हैं। उसने एक बार

फिर, झूठ को दरकिनार कर अपने माल को प्रदर्शित किया। ये हम तिरस्कार के साथ खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रति मेरी सरल प्रतिक्रिया भले ही देर से आई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पड़ोसी, पहले आप खुद को ठीक करिए। आपके झूठ को यहां कोई मानने वाला नहीं है। राजनयिक ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए चल रहे और भविष्य के खतरों को संबोधित करने के लिए परिषद को एक राजनीतिक टूलकिट के हिस्सा के रूप में बदलने के लिए जोर दिया।

कूटनीतिक तरीके से हल किए जाएंगे सीमा विवाद, एक इंच जमीन से भी समझौता नहीं : नेपाल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नेपाल ने साफ कह दिया है कि भारत के साथ सीमा से जुड़े विवाद कूटनीतिक तरीके से हल किए जाएंगे और नेपाल अपनी एक इंच जमीन के साथ भी समझौता नहीं कर सकता है। नेपाली उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने पोखरा में यह बात कही और बताया कि इस समस्या का कारगर समाधान निकालने की कूटनीतिक कोशिशें हो रही हैं। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भी नेपाल बेहद सतर्क है। पोखरेल ने कहा कि इन इलाकों में काम करने वाले नेपाली लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और इसके लिए सैन्य मुख्यालय का संपर्क संयुक्त राष्ट्र और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से लगातार बना हुआ है। नेपाल इस बारे में हाई अलर्ट है। पोखरेल ने ये भी साफ कर दिया कि नेपाल किसी भी तरह के सैन्य समझौते और बाहरी देशों के साथ सैन्य तालमेल की कोशिशों का हिस्सा नहीं बनेगा। ईश्वर पोखरेल ने कहा है कि अमेरिका की ओर से भेजा गया मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते का प्रस्ताव अभी नेपाली संसद में विचाराधीन है और इस पर हर नजरिये से विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन यह तय है कि नेपाल अपने राष्ट्रीय हितों और नीतियों के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है।

उप प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान इस तरह के समझौते का प्रस्ताव अमेरिका की ओर से आया था जिसके तहत नेपाल में ढांचागत विकास और पावर ट्रांसमिशन के विस्तार की बात कही गई है।

चीन ने अपने सबसे भारी संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा कहा जा रहा है कि यह मिशन अंतरिक्ष में चीन के लिए संवदेनशील अभियानों हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा। यह सफल प्रक्षेपण 2020 में मंगल ग्रह के लिए चीन की योजना की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सैटेलाईट चीन में स्थित हैनान में वेनचांग प्रक्षेपण स्थल से स्थानीय समयानुसार रात पौने नौ बजे लॉन्ग मार्च-5 द्वारा अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ।

चीन के वुहान शहर में खतरनाक कोरोना वायरस से पहली मौत, 41 मामले आए सामने

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के कारण फैले निमोनिया से पहली मौत हुई। इसकी जानकारी शहर के स्वास्थ्य आयोग ने दी है। इस नए प्रकार के वायरस के संक्रमण के 41 मामले सामने आए हैं। दो लोगों को पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। सात लोगों की हालत गंभीर हैं और एक की मौत हो गई है। अन्य लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। रोगियों के साथ संपर्क रहने के कारण 419 डॉक्टरों सहित लगभग 740 लोगों को चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। वुहान में स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शहर रहस्यमय ढंग से फैले निमोनिया से जूझ रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में चीनी मीडिया ने बताया था कि यह बीमारी एक नए प्रकार के कोरोना वायरस के कारण फैली थी। समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार स्वास्थ्य आयोग के अनुसार, पिछले तीन दिनों में किसी भी तरह के संक्रमण का पता नहीं चला है। इसके नए मरीज सामने नहीं आए हैं। साल 2003 में एसएआरएस देश भर में फैला था और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, कुल 646 मौतें (दुनिया भर में 813 मौतें) हुई थीं। कई लोग इसे नए वायरस से जोड़कर देख रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एसआरएस के 14 से 15 फीसद मामलों में मौत हुई।

चुनाव में जीत के बाद अमेरिकी राजनयिक से मिलीं ताइवान की राष्ट्रपति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने चुनाव जीतने के बाद यहां अमेरिकी राजनयिक विलियम ब्रेंट क्रिस्टेंसेन से मुलाकात की। ताइवान में अमेरिकी इंस्टीट्यूट के निदेशक क्रिस्टेंसेन ने उन्हें जीत की बधाई दी जबकि साई ने समर्थन देने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया। साई ने इस मुलाकात के दौरान कहा, ताइवान और अमेरिका की भागीदारी द्विपक्षीय स्तर से बढ़कर वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है। भविष्य में हम वैश्विक मुद्दों पर अपने संबंधों को मजबूत करने का काम जारी रखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अपने भाषण में साई ने चीन से बिना पूर्व शर्त के वार्ता फिर शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, आज मैं बीजिंग के अधिकारियों को फिर याद दिलाना चाहती हूं कि शांति, समता, लोकतंत्र और संवाद स्थिरता की कुंजी है। बीजिंग के अधिकारी इस बात को जान लें कि लोकतांत्रिक ताइवान और उसकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार कभी खतरों को स्वीकार नहीं करेगी। आर्थिक मंदी और हांगकांग में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच साई की जीत चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए झटका मानी जा रही है। वर्ष 1949 में गृहयुद्ध के दौरान चीन से अलग होने के बाद से ताइवान ने अपनी अलग पहचान बनाई है लेकिन कभी औपचारिक

रूप से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। चीन अब भी 2.3 करोड़ की आबादी वाले ताइवान पर संप्रभुता का दावा करता है और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग की धमकी देता है।

सोशल मीडिया पर हेटस्पीच से निपटने को तैयार नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सोशल मीडिया पर फैली नकारात्मक और घृणात्मक टिप्पणियों के कारण वर्तमान में यह मुद्दा बहस में आ गया है। विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा इसके लिए नियम बनाकर कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि, शोधकर्ता अब इससे निपटने के वैज्ञानिक तरीके भी खोज रहे हैं।

वर्तमान में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) प्रणाली विकसित की है जो किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणात्मक भाषणों को रोक सकती है। अमेरिका की कर्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह एआइ प्रणाली सोशल मीडिया पर हजारों टिप्पणियों का तेजी से विश्लेषण कर सकती है। इसके साथ ही यह यह उन टिप्पणियों को पहचान भी सकती है जो सकारात्मक होती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि विभिन्न देशों में बसे अल्पसंख्यक समुदाय हों या फिर कोई जाति विशेष, वर्तमान में उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत ही घृणात्मक टिप्पणियां लिखी जाती हैं।

हालांकि, बहुत सी टिप्पणियां उनके पक्ष में या सकारात्मक भी होती हैं। यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूट (एलटीआइ) में पोस्ट डाक्टरल शोधकर्ता आशिकुल आर खुदाबख्श ने कहा कि इन सकारात्मक टिप्पणियों को खोजकर उन्हें हाइलाइट करने से इंटरनेट को उसी तरह सुरक्षित और स्वस्थ्य बनाया जा सकता है जैसे नकारात्मक टिप्पणियों और ट्रोलर्स को खोजकर प्रतिबंधित करके। शोधकर्ताओं ने इस एआइ प्रणाली का उपयोग करके यूट्यूब में समुदाय विशेष के खिलाफ एक लाख से अधिक टिप्पणियों की खोज की। एलटीआइ के

निदेशक और इस अध्ययन के सह लेखक जेम कार्बोनल ने कहा कि भाषा के मॉडल में हाल में हुए बड़े सुधारों की वजह से इतनी बड़ी मात्रा में टिप्पणियों का विश्लेषण किया जा सका। इन मॉडल से यह अनुमान लगता है कि कोई शब्द के किसी जगह होने का क्या मतलब है। इसके माध्यम से एआइ को यह समझने में मदद मिलती है कि लिखने वाला क्या कहना चाहता है।

तिब्बत में जातीय एकता अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित, खुद को चीन का हिस्सा बताया

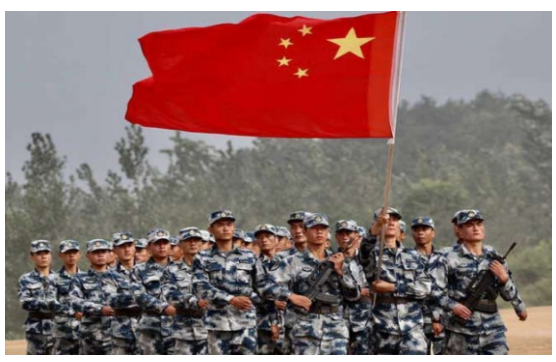

द रीव टाइम्स ब्यूरो

तिब्बत ने पहली बार जातीय एकता को अनिवार्य करने वाला कानून बनाया है। इसमें सुदूर हिमालयी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में इसकी अहम भूमिका की झलक मिलती है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार तिब्बत की पीपुल्स कांग्रेस ने विधेयक पारित किया। यह एक मई से अमल में आएगा। अखबार ने लिखा है कि नए कानून में कहा गया है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का अभिन्न हिस्सा है। यही नहीं नए कानून में यह भी कहा गया है कि क्षेत्रीय एकीकरण को सुरक्षित रखना सभी जातीय समूहों के लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

जातीय एकता को मजबूत किया जाए तथा अलगाववाद के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया जाए। तिब्बत एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में समकालीन अध्ययन संस्थान के उप प्रमुख पेनपा लहामो ने कहा, 'पूरे चीन के स्वायत्तशासी क्षेत्र में जातीय एकता पर यह पहला कानून है।'

मालूम हो कि तिब्बत में 40 से ज्यादा जातीय अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो कुल आबादी 30 लाख का 95 फीसद हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीनों के लिये बढ़ा दिया है- नागालैंड
- हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से जितने लोगों को चुना है- चार
- यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जिस देश में नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है- भारत
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में जिस राज्य में डीआरडीओ की पांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया- कर्नाटक
- जिस फिल्म को 92वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है- द लास्ट कलर
- हाल ही में जिस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है- पलाऊ
- श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है- संतुष्ट
- आरबीआई ने हाल ही में जिस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे- मनी
- रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जिस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिये नियमों में संशोधन किया है-65 वर्ष
- वह राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु 'दामिनी' नामक हेल्पलाइन लांच की- उत्तर प्रदेश
- हाल ही में जिसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया- एस. सौम्या
- हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है- राजस्थान सरकार
- पूर्व विश्व चौम्पियन मीराबाई चानू ने अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएफ) द्वारा जारी ओलंपिक क्वालीफायर रैंकिंग सूची में कौन सा स्थान बरकरार रखा- आठवॉ
- इंडियन रेलवे ने 'रेलवे सुरक्षा बल' का नाम बदलकर यह नाम रखा है- भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा
- भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने-अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया- पाकिस्तान
- भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्प लाइन नवम्बर यह जारी किया है-139
- चीन, रूस और जिस देश ने हाल ही में अपनी नौ-सेनाओं के मध्य विनिमय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया- ईरान
- हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु 'रन फॉर फाइल्स' प्रणाली की शुरुआत की है- हरियाणा सरकार
- हाल ही में तालिबान परिषद ने जिस देश में एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिये सहमति व्यक्त की है- अफगानिस्तान
- यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स ऐंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2026 तक जिस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है- जर्मनी
- जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद जिसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है- मनोज मुकुंद नरवाने
- केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी 'वन स्थिति रिपोर्ट-2019' के अनुसार जिस राज्य में सबसे अधिक वन अच्छादित क्षेत्र बढ़ा है - कर्नाटक
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पैन और आधार को लिंक किये जाने की डेडलाइन को जब तक के लिए बढ़ा दिया है -मार्च 2020
- अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनीं- क्रिस्टीना कोच
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जिस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 'दादा साहेब फाल्के पुरस्कार' से सम्मानित किया है- अमिताभ बच्चन
- वह लेखक जिसको हाल ही में आकाशदीप सम्मान-2019 प्रदान किया गया- ज्ञानरंजन
- शांति के लिये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला युसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक - गुल मकई
- हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ जिसने ली- हेमंत सोरेन
- कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिये पहचाने जाने वाला जिस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है- मिग-27
- वह देश जिसने हाल ही में अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किये जाने की घोषणा की है- रूस
- जिस महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चौंपियनशिप का खिताब जीता है- कोनेरू हम्पी
- इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को यह नाम दिया गया है- आदित्य एल-1
- हाल ही में जिस संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार वर्ष 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा- सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स ऐंड बिजनेस रिसर्च
- वह देश जिसने हाल ही में देश के नये एवं सबसे बड़े रॉकेट लांग मार्च-5 के जरिए अपने सबसे भारी और सर्वाधिक अत्याधुनिक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया- चीन
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने 'किसान नवोन्मेष कोष' की स्थापना जिस शहर में करने की घोषणा की है- नई दिल्ली
- हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है- गुजरात
- ईरान ने हाल ही में जिस देश में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया है -इराक
- प्रवासी भारतीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है -09 जनवरी
- केंद्र सरकार ने जितने पूर्वोत्तर राज्यों का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को 5059 करोड़ का पूंजीगत अनुदान मंजूर किया है -8
- भारतीय मूल की जिस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है -जसबिन्दर बिलान
- नासा के उपग्रह TESS ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के जिस गृह की खोज की है जिस पर जीवन की संभावनाएं भी जताई गई है -TOI 700 डी
- वह स्थान जिस पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है -भागलपुर
- भारत के जिस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है- बांग्लादेश
- अमेरिकी एयरस्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने जिसको कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है -इस्माइल कानी
- वह व्यक्ति जिस पर आधारित पुस्तक 'कर्मयोद्धा ग्रन्थ' का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया- नरेंद्र मोदी
- जिस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गये -ईरान
- हाल ही में रवींद्र नाथ महतो को सर्वसम्मति से जिस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है -झारखंड
- उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस शहर में 234 करोड़ रुपये की लागत से शहीद अशफाकुल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने का घोषणा किया है- गोरखपुर
- 5वें एशिया-प्रशांत 'ड्रोसोफिला' अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन जिस शहर में किया जा रहा है- पुणे
- देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार के जिस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की- इन्द्रधनुष 2.0
- ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से जिस वनीय प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है- कोआला
- जिस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी- कर्नाटक
- वह भारतीय खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड में हेस्टिंगस अंतरराष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता- पी. मंगेश चन्द्रन
- केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने राज्यों के लिए 5,908 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है- सात
- सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में जितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है-10 मीटर
- वह राज्य जिसके पूर्व राज्यपाल त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी का नोएडा कैलाश अस्पताल में हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया- कर्नाटक
- जो राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है- महाराष्ट्र
- वह फिल्म जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया - 1917
- वह खिलाड़ी जो एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का सातवां बल्लेबाज बना - लियो कार्टर
- इस दिन प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है -04 जनवरी
- वह भारतीय ऑल-राउंडर जिसने 04 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की - इरफान पठान
- मीडिया संस्थानों की संख्या जिनके लिए सरकार द्वारा पहले 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान' की घोषणा की गई है -30
- साविवह वैज्ञानिक जिसे वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है - आर. रामानुजम
- हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारतोलक सरबजीत कौर पर जितने वर्ष का प्रतिबन्ध लगा दिया है- चार वर्ष
- हाल ही हुए में एक नए अध्ययन में पूर्वी भारत और जिस देश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा का जलस्तर इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमान लगाया है- बांग्लादेश
- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को अस्पतालों-शैक्षणिक संस्थानों में इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल करने और सभी पाबंदियों को जितने दिन में समीक्षा करने का आदेश दिया है-7 दिन
- मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम 'मिलन' की मेजबानी जो भारतीय शहर करेगा- विशाखापत्तनम
- विश्व हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है-10 जनवरी

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में हिमाचल का कौन सा स्थान है- दूसरा
- मुकिला ग्लेशियर कहां स्थित है- भागा वैली
- हाल ही में नोयडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में किसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड दिया गया- बूढ़ी दिवाली
- हाल ही में राज्यस्तरीय अटल सर्वश्रेष्ठ योजना पुरस्कार किसे दिया गया है- सुंदरनगर
- सुशासन सूचकांक में पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में हिमाचल को कौन सा स्थान मिला है- पहला
- सबट्रॉपीकल हार्टीकल्चर , इरिगेशन एंड वैल्यू एडीशन प्रोजेक्ट -शिवा किसकी सहायता से चलाया जा रहा है- एडीबी
- हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंडी जिला से संबंध रखने वाले किस खिलाड़ी ने आलंपिक क्वालीफायर टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है- बाक्सर आशीष कुमार
- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से हिमाचल के किस स्थान पर विधानसभा अकादमी खोलने का आग्रह किया है- तपोवन
- लुहरी जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या है- 210 मेगावाट
- मंडी के अंतर्राराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए कितने देवी देवता पंजीकृत है-216
- हिमाचल सरकार की ओर से टोल फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर क्या है- 1908
- सुंदरनगर जिला मंडी में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किस वर्ष हुई थी- वर्ष 1992
- माई गॉव वेबपोर्टल को लांच करने वाला हिमाचल देश का कौन सा राज्य बना है- 11वां
- हिमाचल सरकार की ओर से प्रदेश को पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करने वाले राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है-वर्ष 2022 तक
- हिमाचल प्रदेश से प्लास्टिक के चम्मच प्लेट कटोरी और स्ट्रा पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू होगा- 25 जनवरी 2020
- हिमाचल के कौन साहित्यकार हैं जो अंग्रेजी में गजलें लिखने वाले देश के दूसरे व्यक्ति बने- शिमला के डाक्टर दिनेश कुंबर
- दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है- हिमाचल प्रदेश
- फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2019 सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच हरित आवरण में कितनी वृद्धि हुई है- 334 वर्ग किलोमीटर
- अशोक ने हिमालया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा था -माझिमा
- देवी भेड़ोली और गुगा गेहड़वीं का मंदिर कहां पर है- बिलासपुर स्थित झांझियार पहाड़ी पर
- सुजानपुर टिहरा में वर्ष 1793 में प्रसिद्ध गौरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था- संसार चंद ने
- संसार चंद ने 1790 में मुरली मनोहर और 1823 में नर्बदेश्वर मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया - सुजानपुर टिहरा
- बलिकेशवर महादेव मंदिर का निर्माण नादौन में किसने करवाया था- पांडवों ने
- लोमासा ऋषि को हिदुंओं में किस नाम से जाना जाता है - पद्मसंभव
- क्यांग, बक्यांग और बनयानछू नृत्य का संबंध जिले से है- किन्नौर से
- छोहरा कहां का प्रसिद्ध नृत्य है- किन्नौर का
- शिमला के अनाडेल ग्राउंड में पहला फन फेयर उत्सव कब आयोजित किया गया था- 1833

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

हिमाचल रोशनी योजना

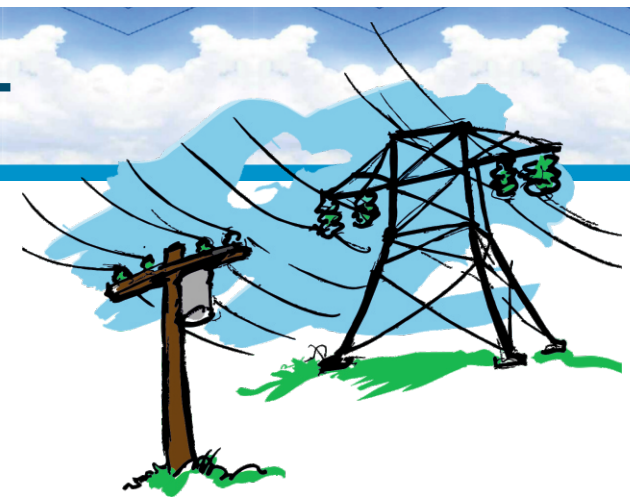

हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों को बिजली की सुविधा पहुंचाने के लिए रोशनी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी ने हिमाचल का बजट 2019–20 पेश करते हुए इस सरकारी योजना की घोषणा की थी। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम इस बार आपको हिमाचल सरकार की इसी रोशनी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहें हैं। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश बजट 2019–20 में होने के बाद इसको मंत्रिमंडल से मंजूरी जून में मिली थी और जुलाई 2019 में लागू किया गया है। राज्य सरकार हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 17,550 गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। वे लोग जिनके पास अभी भी बिजली कनेक्शन नहीं हैं वही इस एचपी फ्री बिजली कनेक्शन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए रोडमैप तैयार होने के बाद बिजली बोर्ड ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। यह योजना प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। "हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना" के कार्यान्वन के लिए सरकार ने शुरूआती तौर पर 13 करोड़ 16 लाख रुपये का बजट भी आवंटित किया गया।

योजना की विशेषताएं

- गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन
- राज्य के ऐसे लोग जिन्हें अब तक बिजली का कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ हैं, वे अब इस योजना के तहत बिजली का कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

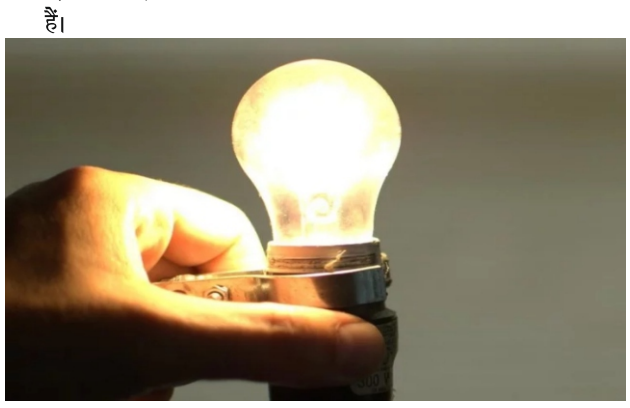

नाम	मुख्यमंत्री रोशनी योजना
लांच हि.प्र. बजट	2019-20
घोषणा	मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
संबंधित विभाग	राज्य का विद्युत विभाग
निगरानी	राज्य बिजली बोर्ड
मूल योजना	प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना
कुल बजट	13 करोड़ 16 लाख रूपये

निःशुल्क बिजली कनेक्शन

- इस योजना के योग्य लाभार्थियों को बिजली कनेक्शन अब निःशुल्क प्राप्त होगा, उन्हें इसके लिए कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

कुल लाभार्थी

- इस योजना के तहत लगभग 17,550 गरीब परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा।

मूल योजना

- इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना' के तहत शुरू किया गया है।

हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना के लिए जरुरी पात्रता

- लाभार्थी परिवार के घर का विद्युत लोड दो केवी से अधिक नहीं होना चाहिए।
- परिवार के सदस्यों का नाम अंत्योदय अन्न योजना की सूची में होना चाहिए।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत उम्मीदवारों का चयन बीपीएल परिवारों की सूची में से किया जाएगा।
- आवेदक उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर 35 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवारों का चयन प्राथमिकता परिवार की सूची के द्वारा भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री फ्री बिजली कनेक्शन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

फ्री बिजली कनेक्शन योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेजो की आवश्यकता होगी

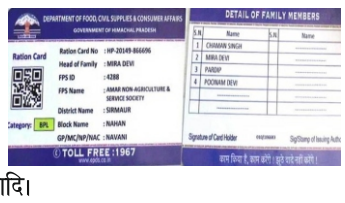

- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान एवं पते का प्रमाण यानि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी आदि।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री फ्री बिजली कनेक्शन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित जानकारी बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर - 1800–1808–060 या 1912 पर प्राप्त की जा सकती है।

डेयरी एंटरप्रेन्यूरशिप डिवेलपमेंट स्कीम

ग्रामीण क्षेत्रों लोगों को पशुधन के प्रति आकर्षित करने और दूग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से वर्ष 2010 में दूध गंगा योजना शुरू की गई। लेकिन 2013 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद अब योजना को शुरू करने के लिए हरी झंडी दी, लेकिन दूध गंगा योजना का नाम बदलकर डेयरी एंटरप्रेन्यूरशिप डिवेलपमेंट स्कीम रखा गया है।

हिमाचल में सरकार की ओर से इस योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको इस योजना के तहत सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक सहायता और इस योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं। 2010 में शुरू की गई इस योजना में वर्ष 2014–15 में केंद्र सरकार ने काफी फेरबदल किया गया।

पशुपालकों को राहत देते हुए एक लाख तक का ऋण लेने के लिए 10 प्रतिशत सीमांत राशि बैंक में जमा नहीं करवानी पड़ेगी। हिमाचल में भी पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए डेयरी एंटप्रेन्यूरशिप स्कीम को दोबारा मंजूरी मिली। अगस्त, 2013 के बाद यह स्कीम बंद हो गई थी। लेकिन फिर से इसे दोबारा शुरू किया गया।

ऋण		
1.	2 से 10 दुधारू पशुओं के लिए ऋण	रु॰ 05.00 लाख
2.	5 से 20 के बछडियो पालन हेतू ऋण	रु॰ 4.80 लाख
3.	वर्मी कम्पोस्ट (दुधारू गायों के इकाई के साथ जुड़ा होगा)	रु॰ 0.20 लाख
4.	दूध दोहने की मशीन मिल्कोटैस्टर बड़े दूध कूलर इकाई (2000 लीटर तक)	रु॰ 18.00 लाख
5.	दूध से देसी उत्पाद बनाने की इकाइयाँ	रु॰ 12.00 लाख
6.	दूध उत्पादों की ढुलाई तथा कोल्ड चौन सुविधा हेतु ऋण	रु॰ 24.00 लाख
7.	दूध व् दूध उत्पादों के शीत भण्डारण हेतु	रु॰ 30.00 लाख
8.	निजी पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए ऋण	
(क)	मोबाइल इकाई	रु॰ 2.40 लाख
(ख)	स्थाई इकाई	रु॰ 1.80 लाख
9.	दूध उत्पाद बेचने हेतु बूथ स्थापना	रु॰ 0.56 लाख
इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए 25% तथा अनुसूचित जाती व् अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को ऋण पर 33.33% अनुदान अन्त में समायोजित करने का प्रावधान है।		

इस योजना के मुताबिक जहां पहले दो से 10 दुधारू पशुओं के लिए पांच लाख ऋण पशुपालक ले सकते थे, वहीं अब बछड़ियों के पालन हेतु 4.80 लाख राशि को बढ़ाकर 5.30 लाख किया गया है।

वर्मी कंपोस्ट के लिए 0.22 लाख, दूध दोहन मशीनों की खरीददारी के लिए 20 लाख, दूध से देशी उत्पाद बनाने के लिए 13.20 लाख, दूध उत्पादन की ढुलाई तथा कोल्ड चेन सुविधा के लिए 26.50 लाख, निजी पशु चिकित्सा ऋण के लिए 2.66 लाख और दूध व दूध उत्पादकों के शीत भंडारण के लिए किसान व पशुपालन 33.00 लाख तक का ऋण ले सकेंगे।

योजना के मुताबिक अभी तक यदि किसान दो पशुओं के लिए भी ऋण लेता था तो उसको 10 प्रतिशत सीमांत राशि बैंक में जमा करवानी पड़ती थी, मगर अब यह राशि केवल वही पशुपालक जमा करवाएंगे, जो एक लाख से अधिक ऋण लेते हैं। इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को ऋण पर 33.33 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए 25% तथा अनुसूचित जाती व् अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को ऋण पर 33.33% अनुदान अन्त में समायोजित करने का प्रावधान है।

इस योजना का व्यक्ति विशेष स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, दुग्ध संगठन, दुग्ध सहकारी सभाएं, तथा कम्पनियां इत्यादि लाभ उठा सकती है। इस परिवार के एक से ज्यादा सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग इकाइयाँ अलग-अलग स्थानों पर स्थापित कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते उन के द्वारा स्थापित इकाइयों की आपस की दूरी कम से कम 500 मीटर की हो। इन सभी मदों पर ऋणदाता को कुल ऋण की 10 प्रतिशत सीमान्त राशी अग्रिम रूप में सम्बंधित बैंक में जमा करवाई जाती है।

दुग्ध गंगा परियोजना का कार्यन्वयन नाबार्ड के सौजन्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों व् राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पशुपालन विभाग के साथ मिल कर चलाया जा रहा है।

योजना के मुख्य उदेश्य

- स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म तैयार करना
- उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं को तैयार करने तथा उनके संरक्षण हेतु बछड़ी पालन को प्रोत्साहन देना
- असंगठित क्षेत्र में आधारभूत बदलाव लाकर दूध के आरंभिक उत्पादों को गाँव स्टार पर ही तैयार करवाना
- दूध उत्पादन के परम्परागत तरीकों को उन्नत कर व्यावसायिक स्तर पर लाना
- स्वरोजगार उत्पन्न करना तथा असंगठित डेरी क्षेत्र को मूलाधार सुविधा देना

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अटल भूजल योजना

World Bank approves Rs.6,000 Crore for Atal Bhujal Yojana

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि भारत में भूजल भंडार के लगातार कम होने की चिंता को दूर करने के लिये विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना (ABHY) के तहत 6,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

क्या है अटल भूजल योजना?

इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया हैं। योजना का उद्देश्य भूजल की मात्रा में इजाफा करना है। साथ ही किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भी ये योजना केंद्र सरकार की ओर से लाई गई है।

यह योजना 2018–19 से 2022–23 तक पाँच साल की अवधि में लागू की जानी है।

अटल भूजल योजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- इस योजना के तहत पहचान किये गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- ये राज्य भारत के कुल भूजल के दोहन के संदर्भ में 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक जोखिम तथा कम जोखिम वाले ब्लॉक हैं।

विश्व बैंक से प्राप्त निधि का उपयोग

विश्व बैंक से मिलने वाली यह निधि राज्यों में भूजल के लिये काम करने वाले संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही भूजल को बढ़ावा देने के लिये सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि की जाएगी।

योजना के बारे में

वर्ष 2016–17 के केंद्रीय बजट में 'राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार योजना' (National Groundwater Management Improvement Programme & NGMIP) की घोषणा की गई थी। मई 2017 में व्यय

वित्त समिति द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में इस योजना को 'अटल भूजल योजना' के रूप में पुनः नामकरण कर फिर से शुरू किया गया।

इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) द्वारा किया जा रहा है।

अटल भूजल योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है।

- इस योजना में विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50/50 की है।
- यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत इन प्रदेशों के 78 जिलों, 193 ब्लॉकों और 8350 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड की विगत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 6584 भूजल ब्लॉकों में से 1034 ब्लॉकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है। सामान्यतः इन्हें 'डार्क जोन' (पानी के संकट की स्थिति) कहा जाता है।

विश्व बैंक (World Bank)

- विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं के एक सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा पटरी पर लाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं का गठन किया गया था।
- विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो ऋण प्रदान करती है।
- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है।
- विश्व बैंक समूह पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है।
- इसके उद्देश्यों में शामिल हैं- विश्व को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाना, विश्व में गरीबी को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना।

स्रोत : पी.आई.बी.

साइबर सुरक्षित भारत

भारत में साइबर सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस करते हुए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' के विजन के अनुरुप, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिविजन (एनईजीडी) एवं उद्योग जगत के सहयोग से साइबर सुरक्षित भारत पहल की घोषणा की गई।

विशेषताएँ

इसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) एवं अग्रिम पंक्ति के आईटी कर्मचारियों के लिये सुरक्षा उपायों हेतु क्षमता निर्माण करने एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा।

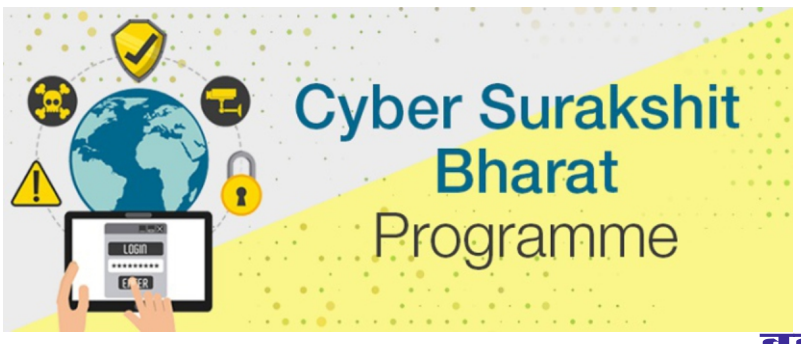

- इस मिशन का परिचालन जागरूकता, शिक्षा एवं सक्षमता के तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा।
- इसमें साइबर सुरक्षा के महत्त्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम, सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों पर कार्यक्रम की एक श्रृंखला तथा साइबर खतरों को प्रबंधित करने तथा इनमें कमी लाने के लिये साइबर सुरक्षा हेल्थ टूल किट्स के साथ अधिकारियों की सक्षमता जैसे पक्षों को शामिल किया गया है।
- साइबर सुरक्षित भारत अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी साझीदारी है और यह साइबर सुरक्षा में आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।

संस्थापक सदस्य

- इस सहायता संघ के संस्थापक साझीदारों में आईटी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियाँ माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहैट एवं डाइमेंशन डाटा शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, नॉलेज साझीदारों में सर्ट-इन, एनआईसी, नेसकॉम एवं एफआईडीओ अलायंस तथा कंसल्टेंसी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियाँ डेलॉयट एवं ईवाई शामिल हैं।

अन्य मुख्य बिंदु

- देश के साइबर स्पेस की सुरक्षा सुनिश्चित करना डिजिटल इंडिया के विजन का सबसे अहम् पक्ष है। वस्तुतः इसका उद्देश्य यह है कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिये।
- जैसा की हम सभी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया की वजह से अभिशासन प्रणाली में त्वरित रूपांतरण हुआ है। अतः सुशासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये निश्चित रूप से निजी क्षेत्र की कपंनियों को आगे आना होगा, ताकि भविष्य के संदर्भ में इसकी राह को और अधिक दृढ बनाया जा सके।
- वर्तमान में भारत में 118 करोड़ से अधिक आधार खाते मौजूद हैं जो लोगों को एक विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराते हैं। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जैसे-जैसे हम आर्थिक संवृद्धि की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे हमें निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करते जाना चाहिये कि हमारी डिजिटल व्यवस्था उसी के अनुरूप सुरक्षित रहे और हमारे डाटा की ठीक से हिफाजत सुनिश्चित हो।
- इस चिंता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षित भारत पहल लॉन्च की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे डाटा को भली-भाँति सुरक्षित रखना है।
- हालाँकि, इसके लिये सरकार के साथ-साथ उद्योग जगत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भी एकजुट होकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।

साइबर अपराध

ये ऐसे गैर-कानूनी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पाइरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता हैं।

साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में भारत के प्रयास

- भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिये पर्याप्त हैं।
- इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013' जारी की गई जिसके तहत सरकार ने अति-संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये 'राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection centre & NCIIPC) का गठन किया।
- सरकार द्वारा 'कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)' की स्थापना की गई जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।
- विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (Information Security Education and Awareness- ISEA) परियोजना प्रारंभ की है।
- भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।
- अंतर-एजेंसी समन्वय के लिये 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (Indian Cyber Crime Co-ordination Centre-I4C) की स्थापना की गई है।

बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है?

साइबर अपराध के संबंध में बुडापेस्ट कन्वेंशन (Budapest Convention on cyber crime) पर हस्ताक्षर करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध (cyber crime), क्रांतिकारीकरण (radicalization) और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।

बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन या बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।

यह अपनी तरह की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके, जाँच-पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई है।

इस कन्वेंशन में 56 सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं।

सीसीटीएनएस क्या है?

- जून 2009 में शुरू किया गया सीसीटीएनएस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य पुलिस स्टेशनों के स्तर पर पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली तैयार करना है।
- सीसीटीएनएस (CCTNS & Crime and Criminal Tracking Network & Systems) सभी स्तरों पर, विशेष रूप से पुलिस स्टेशन स्तर पर दक्षता और प्रभावी पुलिस कार्रवाई करने के लिये ई-शासन के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली पर आधारित व्यवस्था है।
- सीसीटीएनएस सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan of Govt) के अंतर्गत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (Mission Mode Project & MMP) है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप हुआ शुरु, अंतरिक्ष में एलियंस की करेगा खोज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनियाभर में विज्ञान दिनोंदिन तरक्की करता जा रहा है। नए-नए उपकरण बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप भी जुड़ गया है। यह चीन में स्थित है, जिसे तीन साल के लंबे ट्रायल के बाद शुरू कर दिया गया है। सितंबर 2016 से यह रेडियो टेलीस्कोप ट्रायल पर था। इसे अंतरिक्ष की आंख कहकर भी पुकारा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुइझोऊ प्रांत में पहाड़ी पर स्थापित यह रेडियो टेलीस्कोप 20 साल में बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाने में अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान समेत 10 देशों के वैज्ञानिकों ने मदद की है।

इसमें 1207 करोड़ रुपये का खर्च आया है। चीन का यह टेलीस्कोप एक सेकंड में 38 गीगाबाइट (जीबी) डाटा जुटाने में सक्षम है। दुनिया का सबसे बड़ा और संवेदनशील यह रेडियो टेलीस्कोप प्यूर्टोरिका की अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी से 2.5 गुना संवेदनशील है। बता दें कि प्यूर्टोरिका स्थित ऑब्जर्वेटरी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल-डिश रेडियो टेलीस्कोप स्थापित है। इस रेडियो टेलीस्कोप को बनाने का मकसद अंतरिक्ष में जीवन की खोज करना है।

इसके अलावा यह एलियंस का भी पता लगाएगा। इस टेलीस्कोप का नाम फाइव हंड्रेड मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप यानी फास्ट है। 4450 पैनल वाला यह टेलीस्कोप आकार में 30 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसकी अंतरिक्ष रेंज चार गुना ज्यादा है

यह अब तक करीब 44 पल्सर की खोज कर चुका है। दरअसल, पल्सर तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन या तारा होता है, जो रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है।

भारत का इकलौता ऐसा जज जिसे फांसी पर लटकाया गया, वजह है बेहद खौफनाक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

किसी अपराधी को जज द्वारा फांसी की सजा दिए जाने की बातें तो आपने बहुत सुनी और देखी होंगी, लेकिन क्या किसी जज को फांसी पर लटकाया गया हो, ऐसा सुना है। यह बात बहुत पुरानी है, लेकिन है हकीकत। आज से 44 साल पहले यानी साल 1976 में एक जज को फांसी पर लटकाया गया था और इसकी वजह बेहद ही खौफनाक है, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस जज का नाम है उपेंद्र नाथ राजखोवा। वह असम के ढुबरी जिले (जिसे डुबरी या धुबरी नाम से भी जाना जाता है) में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात थे।

उन्हें सरकारी आवास भी मिला हुआ था, जिसके अगल-बगल में अन्य सरकारी अधिकारियों के भी आवास थे। यह 1970 की बात है। तब उपेंद्र नाथ राजखोवा सेवानिवृत होने वाले थे। फरवरी 1970 में वो सेवानिवृत हो गए थे। हालांकि उन्होंने सरकारी बंगला खाली नहीं किया था।

इसी बीच उनकी पत्नी और तीन बेटियां अचानक गायब हो गईं। हालांकि इसके बारे में उपेंद्र नाथ के अलावा किसी को भी कुछ पता नहीं था। जब भी उनसे कोई पूछता कि उनका परिवार कहां है, तो वह कुछ न कुछ बहाना बना देते कि यहां गए हैं, वहां गए हैं। अप्रैल 1970 में उपेंद्र नाथ राजखोवा सरकारी बंगला खाली करके चले गए और उनकी जगह एक दूसरे जज आ गए। हालांकि राजखोवा कहां गए, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। चूंकि राजखोवा के साले यानी उनके पत्नी के भाई पुलिस में थे, उन्हें कहीं से पता चला कि राजखोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में कई दिनों से ठहरे हुए हैं। इसके बाद वह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ होटल में गए और उनसे मिले और अपनी बहन और भांजियों के बारे में पूछा।

इस पर राजखोवा ने तरह-तरह के बहाने बनाए। इस बीच उन्होंने कमरे के अंदर ही आत्महत्या करने की भी कोशिश की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में राजखोवा ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और तीनों बेटियों की हत्या की है और उन चारों की लाश को अपने उसी सरकारी बंगले में जमीन के अंदर गाड़ दिया है।

गगनयान मिशन के लिए ऐसे हुआ भारतीय अंतरिक्षयात्रियों का चयन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नए साल की शुरुआत में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के. सिवन ने साल 2020 के अपने लक्ष्यों की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि साल 2020 में गगनयान प्रोजेक्ट के साथ चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। गगनयान अंतरिक्ष में इसरो का पहला मानव मिशन होगा।

इसके लिए भारतीय वायु सेना के चार पायलट चुने गए हैं। उनकी ट्रेनिंग जनवरी के तीसरे सप्ताह से रूस में शुरू होगी। इसरो ने गगनयान की घोषणा भले ही अब की हो लेकिन अंतरिक्ष में मानव मिशन की योजना पर काम साल 2007 से ही शुरू हो गया था। हालांकि तब बजट की कमी के चलते यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका।

उस वक्त इसरो के शक्तिशाली जीएसएलवी रॉकेट इंसानों को ले जाने वाले मॉड्यूल में सक्षम नहीं थे।

इसरो के पास ऐसे रॉकेट या क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे जो भारी क्रू मॉड्यूल का वजन उठा सकें। तब इस दिशा में प्रयोग शुरू हुए और साल 2014 में जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट बनने के बाद इसका समाधान हुआ। इसरो के प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भी सफल रहे। इसरो ने एक बार फिर जीएसएलवी मार्क 3 के जरिए गगनयान मिशन की तैयारी की है। जीएसएलवी मार्क 3 वो रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में इस्तेमाल हुआ।

इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ मार्क 3 रॉकेट को

तीन बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसी की वजह से अंतरिक्ष में मानवमिशन का इसरो का सपना एक बार फिर 2017 में शुरू हुआ। 15 अगस्त 2018 को लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का प्रोग्राम लॉन्च करेगा। इसके लिए 10 अरब करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ऐसी जगह, जहां हर वक्त कड़कती रहती है आसमानी बिजली, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए रहस्य

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विज्ञान आज भले ही कितनी भी तरक्की कर चुका है, लेकिन धरती पर आज भी ऐसी बहुत ही जगहें हैं, जहां का रहस्य सुलझाने में वैज्ञानिक भी नाकाम रहे हैं।

ऐसी ही एक जगह दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी है, जहां एक झील के ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। ये तो आपने सुना ही होगा कि आसमान में बिजली एक जगह पर दो बार कभी नहीं चमकती, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जगह पर एक घंटे में हजारों बार बिजली चमकती है। दुनिया को हैरान कर देने वाले इस रहस्य को बीकन ऑफ मैराकाइबो कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि कैटाटुम्बो लाइटनिंग, एवरलास्टिंग स्टॉर्म, ड्रैमेटिक रोल ऑफ थंडर। इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहते हैं।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी जिस जगह पर मैराकाइबो झील में मिलती है, वहां साल में 260 दिन तूफानी होते हैं। इन 260 दिनों की तूफानी रातों में यहां रात भर बिजली चमकती रहती है। मैराकाइबो झील का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है।

वैज्ञानिकों को जंगल में मिला दुनिया का सबसे बड़ा खिला हुआ फूल, दो साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंडोनेशिया के पश्चिम मध्य सुमात्रा के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा खिला हुआ फूल मिला है। यह इतना बड़ा है जिसकी कल्पना शायद ही आपने कभी की हो। जानकारी के मुताबिक, यह फूल चार वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस फूल का नाम रेफलिसिया बताया जा रहा है और यह अब तक दर्ज रेफलिसिया फूलों में सबसे बड़ा है। इस फूल की बनावट काफी हद तक सूरजमुखी की तरह होती है। हालांकि इसका रंग पीला न होकर केसिरया आसमानी और सफेद होता है। स्थानीय लोग इस फूल को लाशों का फूल कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही बदबूदार होता है। इस फूल की बनावट काफी हद तक सूरजमुखी की तरह होती है। हालांकि इसका रंग पीला न होकर केसिरया आसमानी और सफेद होता है। इस फूल के पौधे की खासियत है कि इसमें कोई पत्ती या जड़ नहीं होती है। ये अपना भोजन-पानी दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। इसकी प्यालीनुमा पुष्पनाल में मौजूद गंध कीट-पतंगों को खूब आकर्षित करता है और वो जैसे ही फूल के अंदर घुसते हैं, उसमें गिरकर मर जाते हैं। यह फूल साल के कुछ महीने में ही खिलता है। इसके खिलने की शुरुआत अक्तूबर से होती है और यह अगले साल मार्च तक पूरी तरह से खिल जाता है। हालांकि इस फूल का जीवन ज्यादा दिनों का नहीं होता। यह जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं

ऑस्ट्रेलिया में 10 हजार ऊंटों को गोली मारने का आदेश, वजह है बेहद अजीब

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आमतौर पर आपने देखा होगा कि दुनियाभर में जीव-जंतुओं को बचाने की कोशिश होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी नेताओं के एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने सूखाग्रस्त इलाकों में पीने के पानी को बचाने के लिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में करीब 10 हजार जंगली ऊंटों को मारने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कुछ आदिवासी समुदायों की शिकायत है कि जंगली ऊंट पानी की तलाश में उनके इलाके में आते हैं और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी शिकायत के बाद ऊंटों को मारने का फैसला लिया गया है।

इसमें करीब पांच दिनों का समय लग सकता है। चिंता का विषय यह भी है कि पशु ग्लोबल वार्मिंग में भी अपना योगदान दे रहे हैं क्योंकि वे एक वर्ष में एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जंगली ऊंट प्रबंधन योजना का दावा है कि अगर ऊंटों को लेकर कोई रोकथाम योजना नहीं लाई गई तो यहां जंगली ऊंटों की आबादी हर नौ साल में दोगुनी हो जाएगी। कार्बन फार्मिंग विशेषज्ञ रेजेनको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम मूर का कहना है कि एक लाख जंगली ऊंट प्रति वर्ष जितनी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, वह सड़क पर चलने वाली अतिरिक्त चार लाख कारों के बराबर है। हालांकि ऊर्जा एवं पर्यावरण विभाग का कहना है कि जंगली जानवरों के उत्सर्जन को देश के उत्सर्जन अनुमान में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे घरेलू प्रबंधन के तहत नहीं हैं।

92 साल की डॉक्टर दादी कभी नहीं होंगी रिटायर! अभी भी हर हफ्ते देखती हैं 600 मरीज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून हो, जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। इंसान उम्र को किनारे करके अपना काम करते रहता है। चीन की रहने वाली एक 92 वर्षीय महिला भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। वह पेशे से एक डॉक्टर हैं और वह 25 साल पहले यानी साल 1994 में ही सेवानिवृत हो गई थीं, लेकिन वह अभी भी चीन के जियांगसु प्रांत के नानजिंग शहर के सिटी हॉस्पिटल में लोगों का इलाज कर रही हैं। इनका नाम है डॉ. आओ झोंगफैंग। हालांकि इन्हें डॉक्टर दादी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टर दादी जब सेवानिवृत हुई थीं, तभी उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेंगी। इसलिए वह सेवानिवृत होने के अगले ही दिन फिर से अस्पताल लौट गईं और लोगों का इलाज करने लगीं।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

द रीव टाइम्स

संस्थापक: डॉ एल.सी. शर्मा

प्रकाशक: आईआईआरडी काम्पलेक्स, बाईपास रोड शनान, सन्जौली शिमला-6 हि.प्र.

द रीव टाइम्स के लिए मुद्रक प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस, सायबू निवास समीप सेक्टर-2, बस स्टैंड, मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित

संपादक: हेम राज चौहान

फोन न. : 0177 2640761
आर.एन.आई. रिफ्रेंस नं. 1328500
टाइटल कोड : HPBIL00313
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/129/SML/2019-2021

E-mail : hem.raj@iirdshimla.org
Website : www.therievtimes.com

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के / लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

दूरभाष : 9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़..... द रीव टाइम्स उत्कृष्ठ गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर – द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट ीजजचरुध्ेनइण्उपेपवदतपमअण्पद पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता / अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500 रुपये, छः माह के लिए 250 रुपये में और घर बैठे पांऐ द रीव टाइम्स..... क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र